

दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

आ.प्र.अ. (मू.प.) (वाणि.) 296/2018, सि.वि. आ. 5557/2015 एवं
46196/2019

इंटेक्स टेक्नोलॉजीज (इंडिया) लिमिटेड अपीलार्थी

द्वारा: श्री जे. साई दीपक सह श्री जी. नटराज, श्री अविनाश के.
शर्मा और श्री आर अभिषेक, अधिवक्तागण।

बनाम

टेलीफोनेक्टीबलगेट एल एम एरिक्सन (पब्लिक) प्रत्यर्थी

द्वारा: श्री सी. एस. वैद्यनाथन और श्री संदीप सेठी, वरिष्ठ
अधिवक्तागण सह सुश्री साया चौधरी कपूर, श्री आशुतोष
कुमार, श्री विनोद चौहान, सुश्री वृंदा बागरिया, सुश्री
राधिका पारेवा, श्री विनायक गोयल और श्री विक्रम
सिंह, अधिवक्तागण।

आ.प्र.अ. (मू.प.) (वाणि.) 297/2018

टेलीफोनेक्टीबलगेट एल एम एरिक्सन (पब्लिक)अपीलार्थी

द्वारा: श्री सी. एस. वैद्यनाथन और श्री संदीप सेठी, वरिष्ठ
अधिवक्तागण सह सुश्री साया चौधरी कपूर, श्री आशुतोष
कुमार, श्री विनोद चौहान, सुश्री वृंदा बागरिया, सुश्री
राधिका पारेवा, श्री विनायक गोयल और श्री विक्रम
सिंह, अधिवक्तागण।

बनाम

इंटेक्स टेक्नोलॉजीज़ (इंडिया) लिमिटेड

..... प्रत्यर्थी

द्वारा: श्री जे. साई दीपक सह श्री जी. नटराज, श्री अविनाश
के. शर्मा और श्री आर अभिषेक, अधिवक्तागण।

सुरक्षित : 21 फरवरी, 2023

निर्णय की तिथि: 29 मार्च, 2023

कोरम:

माननीय न्यायमूर्ति श्री मनमोहन

माननीय न्यायमूर्ति श्री सौरभ बनर्जी

विषय-सूची

पैरा सं.

क्रॉस-अपीलें.....	2-4
इंटेक्स की ओर से तर्क.....	5-12
एरिक्सन की ओर से तर्क.....	13-31
इंटेक्स की ओर से प्रत्युत्तर तर्क.....	32-33
एरिक्सन की ओर से प्रत्युत्तर तर्क.....	34
न्यायालय के तर्क.....	35-151
बौद्धिक संपदा विधियों पर प्रौद्योगिकी के तीव्र विकास का प्रभाव.....	35-38
मानकों की श्रेणियाँ और उनका महत्व.....	39-59

मानक आवश्यक पेटेंट क्या है और ऐसे पेटेंट धारकों के दायित्व क्या हैं?.....	60-62
एफआरएएनडी मानक आवश्यक पेटेंट धारकों और कार्यान्वयनकर्ताओं दोनों पर दायित्व अधिरोपित करता है.....	63-73
मानक आवश्यक पेटेंट की अवधारणा भारतीय विधि के लिए अज्ञात नहीं है.....	74-75
यदि अतिलंघनकर्ता/कार्यान्वयनकर्ता एक अनिच्छुक लाइसेंसधारी है तो मानक आवश्यक पेटेंट स्वामी व्यादेश राहत की माँग कर सकते हैं.....	76-91
मानक आवश्यक पेटेंट मामले में अतिलंघन की कसौटी क्या है?.....	92-98
यदि प्रथम दृष्टया एक पेटेंट का अतिलंघन सिद्ध हो जाए तो भी व्यादेश दिया जा सकता है.....	99-104
क्या एक मानक आवश्यक पेटेंटधारी विवादित या संभावित रूप से विवादित विदेशी पेटेंट से संबंधित लाइसेंस सहित पोर्टफोलियो लाइसेंस की पेशकश कर सकता है?	105-111
नोकिया बनाम ओप्पो (पूर्वोक्त) मामले में चौगुना परीक्षण विधि के विपरीत है.....	112-117
एरिक्सन द्वारा अपने पेटेंट की अनिवार्यता और इंटेक्स द्वारा अतिलंघन के दावे स्वीकार किए गए तथ्य हैं.....	118-128
केवल इसलिए कि इंटेक्स द्वारा एक प्रतिसंहरण याचिका दायर की गई थी, यह कोई उपधारणा नहीं हो सकती कि एरिक्सन के पेटेंट प्रथम दृष्टया अवैध हैं.....	129-138

अधिनियम की धारा 3 और 8 के अंतर्गत चुनौती नहीं दी गई है.....	139-148
इंटेक्स वांडर लिमिटेड एवं अन्य बनाम एंटोक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड मामले में निर्धारित विधि के सिद्धांत को पूरा करने में विफल रहा है, लेकिन एरिक्सन उक्त कसौटी पर खरा उतरता है।.....	149-150
राहत.....	151

निर्णय

न्या. मनमोहन:

1. प्रौद्योगिकी के तीव्र विकास ने बौद्धिक संपदा विधियों के लिए अभूतपूर्व चुनौतियाँ पेश की हैं। यह मामला एक सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत सत्य को दर्शाता है कि 'विधि हमेशा प्रौद्योगिकी से पीछे रह जाती है'। एक समान अंतरराष्ट्रीय विधि के अभाव में, दुनिया भर के न्यायालय विधि के बुनियादी सिद्धांतों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए राष्ट्रीय विधियों, राष्ट्रीय नीतियों के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय मानकों और विदेशी निर्णयों (इस हद तक कि वे राष्ट्रीय विधियों के विपरीत न हों और राष्ट्रीय वास्तविकताओं के अनुकूल हों) को लागू करते आ रहे हैं। वर्तमान निर्णय में, इस न्यायालय ने भी ऐसा ही करने का प्रयास किया है।

क्रॉस-अपीलें

2. वर्तमान क्रॉस-अपीलें 13 मार्च, 2015 के निर्णय और आदेश को चुनौती देते हुए दायर की गई हैं, जिसे इसके पश्चात् सि.वा.(मू.प.) सं. 1045/2014 में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित 'आक्षेपित आदेश' के रूप में संदर्भित किया गया है।
3. इंटेक्स टेक्नोलॉजीज (इंडिया) लिमिटेड (संक्षेप में 'इंटेक्स') ने आ.प्र.अ. (मू.प.) (वाणि.) सं. 296/2018 दायर किया है, जिसमें सि.वा. (मू.प.) सं. 1045/2014 में अं.आ. सं. 6735/2014 में पारित आक्षेपित आदेश [टेलीफोनक्टीबलगेट एलएम एरिक्सन (पब्लिक) (संक्षेप में 'एरिक्सन') द्वारा सि.प्र.सं. के आदेश XXXIX नियम 1 और 2 के अंतर्गत दायर एक आवेदन] को चुनौती दी गई है, जिसके अंतर्गत विद्वान एकल न्यायाधीश ने अभिनिर्धारित किया है कि एरिक्सन के आठ वादग्रस्त पेटेंट प्रथम दृष्टया वैध, आवश्यक थे और इंटेक्स ने प्रथम दृष्टया एरिक्सन के पेटेंट का अतिलंघन किया है। विद्वान एकल न्यायाधीश ने आगे अभिनिर्धारित किया कि एरिक्सन ने प्रथम दृष्टया अपनी निष्पक्ष, उचित और गैर-भेदभावपूर्ण (संक्षेप में 'एफआरएनडी') प्रतिबद्धता का अनुपालन प्रदर्शित किया है और इंटेक्स द्वारा वाद-पूर्व वार्ता को लंबा खींचने और उसके बाद लाइसेंस संबंधी वार्ता के बीच में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (संक्षेप में 'सीसीआई') और बौद्धिक संपदा अपीलीय बोर्ड (संक्षेप में 'आईपीएबी') के समक्ष एरिक्सन के विरुद्ध कार्यवाही शुरू करने के कृत्य ने प्रथम दृष्टया एफआरएनडी लाइसेंस निष्पादित

करने की उसकी अनिच्छा को दर्शाया है। विद्वान एकल न्यायाधीश ने यह भी अभिनिर्धारित किया है कि स्वामिस्व की गणना के लिए चिपसेट के आधार को स्वीकार नहीं किया जा सकता है और अंतिम उपकरण के मूल्य पर स्वामिस्व की गणना की प्रथा गैर-भेदभावपूर्ण है।

4. एरिक्सन ने आ.प्र.अ. (मू.प.) (वाणि) सं. 297/2018 दायर कर उक्त वाद में पारित 13 मार्च, 2015 के आक्षेपित आदेश और उसके बाद 26 मार्च, 2015 के संशोधन आदेश में संशोधन की माँग की है, जिसके अंतर्गत विद्वान एकल न्यायाधीश ने इंडेक्स को अंतरिम चरण में 50% स्वामिस्व और शेष 50% बैंक गारंटी के माध्यम से भुगतान करने का निर्देश दिया है। एरिक्सन ने प्रार्थना की है कि इंडेक्स को पूरी स्वामिस्व राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया जाए।

इंडेक्स की ओर से तर्क

5. इंडेक्स के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि भारतीय विधि के लिए मानक आवश्यक पेटेंट की अवधारणा अज्ञात है। उन्होंने कहा कि चूँकि मानक निर्धारण संगठन (संक्षेप में 'एसएसओ') यह जाँच नहीं करते हैं कि कौन से पेटेंट वास्तव में आवश्यक हैं और घोषणाकर्ता अनिवार्यता का कोई प्रमाण नहीं देते हैं, इसलिए विचाराधीन पेटेंट को मानक या आवश्यक उपनिर्धारित नहीं किया जा सकता है।

6. उन्होंने इस बात पर बल दिया कि विद्वान एकल न्यायाधीश अंतरिम चरण में स्वामिस्व का भुगतान करने के साथ-साथ उसे जमा करने का निर्देश नहीं दे

सकते थे, क्योंकि मानक आवश्यक पेटेंट स्वामियों का एकमात्र अधिकार, यहाँ तक कि विदेशी न्यायालयों द्वारा निर्धारित विधि के अनुसार भी, विचारण के अंत में स्वामिस्व प्राप्त करना है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि मानक आवश्यक पेटेंट मामलों में कोई व्यादेश नहीं दिया जा सकता, भले ही कार्यान्वयनकर्ता एक अनिच्छुक लाइसेंसधारी हो।

7. उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि विद्वान एकल न्यायाधीश यह विवेचना करने में विफल रहे कि किसी इकाई, जिसने कथित तौर पर मानक आवश्यक पेटेंट का अतिलंघन किया है, को एक विशेष दर पर स्वामिस्व का भुगतान करने का निर्देश देने से पहले संतुष्ट होने वाले परीक्षण हैं: (i) दावा किए गए पेटेंट वास्तव में मानक आवश्यक पेटेंट हैं, (ii) कार्यान्वयनकर्ता द्वारा उपयोग की जाने वाली तकनीक मानक आवश्यक पेटेंट का अतिलंघन करती है, (iii) स्वामिस्व दर जिस पर पेटेंटधारक अपने मानक आवश्यक पेटेंट का लाइसेंस देने के लिए तैयार है वह एफआरएएनडी है, और (iv) कार्यान्वयनकर्ता उक्त एफआरएएनडी दर पर लाइसेंस लेने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि चूँकि वर्तमान मामले में ये सभी चार कारक एक साथ नहीं आए तथा चूँकि इंटेक्स दिवालिया हो चुका है तथा अब मोबाइल फोन नहीं बेच रहा है, इसलिए विद्वान एकल न्यायाधीश इंटेक्स को वादग्रस्त पेटेंट का उपयोग करने हेतु लाइसेंस प्राप्त करने के लिए एरिक्सन को स्वामिस्व के रूप में कोई राशि देने का निर्देश नहीं दे सकता था। अपनी प्रस्तुति के समर्थन में, उन्होंने *नोकिया*

टेक्नोलॉजीज ओवाई बनाम ग्वांगडोंग ओप्पो मोबाइल टेलीकम्युनिकेशंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड और अन्य, 2022 एससीसी ऑनलाइन दिल्ली 4014 (संक्षेप में 'नोकिया बनाम ओप्पो') में इस न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश के हालिया निर्णय के पैराग्राफ 77 पर धरोसा किया। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि यू.के. सुप्रीम कोर्ट के अनवायर्ड प्लैनेट इंटरनेशनल लिमिटेड एवं अन्य बनाम हुआवेई टेक्नोलॉजीज (यू.के.) कंपनी लिमिटेड; 2020 यू.के. एस.सी. 37 के निर्णय के बाद, (i) से (iv) तक उल्लिखित उपरोक्त परीक्षण नोकिया बनाम ओप्पो मामले में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा अनुबंधित किए गए थे। नोकिया बनाम ओप्पो मामले का पैराग्राफ 77 नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:-

“77. अनवायर्ड प्लैनेट में दी गई उद्धोषणा के उपर्युक्त अंशों को पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है कि, किसी प्रतिवादी, जिस पर वादी के स्वामित्व वाले एसईपी का अतिलंघन करने का आरोप है, को किसी विशेष दर पर स्वामिस्व के भुगतान पर वादी से लाइसेंस लेने की आवश्यकता है, इस निर्णय पर पहुँचने से पहले, न्यायालय को, सबसे पहले, स्वयं को संतुष्ट करना होगा कि (i) दावा किया गया वादग्रस्त पेटेंट वास्तव में एक एसईपी है, (ii) प्रतिवादी द्वारा उपयोग की गई तकनीक एसईपी का अतिलंघन करती है, (iii) जिस स्वामिस्व दर पर वादी अपने एसईपी का लाइसेंस देने के लिए तैयार है वह एफआरएएनडी है, और (iv) प्रतिवादी उक्त एफआरएएनडी दर पर लाइसेंस लेने के लिए तैयार नहीं है। जब तक ये सभी चार कारक एक साथ नहीं आते, न्यायालय प्रतिवादी को वादी से वादग्रस्त पेटेंट का दोहन करने के लिए

लाइसेंस प्राप्त करने के लिए वादी को स्वामिस्व के रूप में कोई राशि का भुगतान करने के लिए नहीं कह सकता।”

8. इंटेक्स के विद्वान अधिवक्ता ने प्रतिवाद दिया कि सीसीआई की शिकायत को स्पष्ट रूप से पढ़ने से निस्संदेह यह स्थापित हो जाता है कि इंटेक्स ने कहीं भी एरिक्सन के आठ वादग्रस्त पेटेंटों की अनिवार्यता और वैधता को स्वीकार नहीं किया है। उन्होंने कहा कि सीसीआई शिकायत के पैराग्राफ 3.2, 6.10-6.12, 6.25, 9.18, 9.44 और 9.47 में इंटेक्स ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वह किसी भी तरह से आठ वादग्रस्त पेटेंटों की वैधता या अनिवार्यता की गारंटी नहीं दे सकता है या उसे स्वीकार नहीं कर सकता है। इंटेक्स के विद्वान अधिवक्ता द्वारा भरोसा किए गए उक्त सीसीआई शिकायत के प्रासंगिक अंश को नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:-

“3.2 मोबाइल उपकरणों के लिए आवश्यक सबसे बड़े एसईपी धारक होने का दावा करने वाले एरिक्सन ने आरोप लगाया है कि सूचक के मोबाइल फोन उसके पेटेंट का उपयोग/कार्यान्वयन करते हैं और उसका अतिलंघन करते हैं। इसलिए इसने सूचक को अपने पेटेंट के उपयोग के लिए लाइसेंस प्राप्त करने की आवश्यकता बताई है। सूचक, मोबाइल उपकरणों का निर्माता न होकर केवल ऐसे उपकरणों का आयातक है, उसे इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि हैंडसेट में शामिल घटकों/प्रौद्योगिकी ने एरिक्सन जैसे तीसरे पक्ष के पेटेंट अधिकारों का उल्लंघन किया है या नहीं। सूचक ने अपने विक्रेताओं के साथ यह अनुबंध किया था कि उनके द्वारा आपूर्ति की गई वस्तुएँ किसी भी लागू पेटेंट का अतिलंघन नहीं करती हैं/नहीं

करेंगी, तथापि वह ऐसे किसी भी कथित अतिलंघन से पूरी तरह अनभिज्ञ था। इसके अतिरिक्त, इस तरह के कथित अतिलंघन के संबंध में एरिक्सन द्वारा कोई ठोस विवरण प्रदान करने में विफल रहने के बावजूद, विधि के अंतर्गत उपलब्ध अपने सभी अधिकारों और प्रतिवादों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, सूचक ने एरिक्सन के बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करते हुए, सद्भावनापूर्वक एरिक्सन के साथ लाइसेंस वार्ता में प्रवेश किया। इस प्रकार, एरिक्सन के साथ सूचक का आचरण बहुत निष्पक्ष और उचित रहा है।

XXX XXX XXX

6.10 स्वतंत्र तीसरे पक्ष के विश्लेषण से पता चलता है कि यूएमटीएस, जो कि एक 3जी सेलुलर मानक है, के लिए आवश्यक घोषित किए गए 7300 पेटेंटों में से अधिकांश, तकनीकी रूप से यूएमटीएस मानक के लिए आवश्यक नहीं हैं। रूडी बेकर और जोएल वेस्ट द्वारा प्रस्तुत 2008 के एक प्रबंध में, पीए परामर्श समूह की एक रिपोर्ट, "3जीपी-एफडीडी में आवश्यक बौद्धिक संपदा" (मई 2006) का संदर्भ देते हुए, प्रबंध में पाया गया कि एसएसओ को घोषित एसईपी में से केवल 37% ही वास्तव में आवश्यक थे, जिसे अनुलग्नक ज के रूप में संलग्न किया गया है। यह उल्लेख करना भी महत्वपूर्ण होगा कि मोटोरोला मोबिलिटी इंकॉर्पोरेशन ने यूएस और जर्मनी में एप्पल के विरुद्ध 10 घोषित आवश्यक पेटेंटों का दावा किया था, जिनमें से 9 को अवैध या अतिलंघन रहित या दोनों पाया गया। इसी प्रकार, सैमसंग ने एप्पल के विरुद्ध 20 आवश्यक पेटेंटों पर दावा किया है, जिनमें से 13 को वह पहले ही खो चुका है,

या तो गैर-अतिलंघन या अवैधता या दोनों के कारण, तथा केवल 3 में ही जीत हासिल कर सका है; उसने अन्य घोषित आवश्यक पेटेंटों को भी वापस ले लिया है - और उन पेटेंटों में दोषों को मौन स्वीकृति दी है। यह अभिलेख घोषित आवश्यक पेटेंटों की सामान्य सफलता दर को दर्शाता है। दावा किए गए पेटेंट, हालाँकि मानकीकृत नेटवर्क पर परिचालन योग्य हैं, लेकिन चूँकि वे मानक में वर्णित कार्यक्षमता का उपयोग नहीं करते हैं या क्योंकि यह वैकल्पिक है या अवैधता सहित अन्य कारणों से, अनिवार्यता परीक्षण में असफल हो गए हैं।

6.11 यह ध्यान देने योग्य है कि इस बात का कोई स्वतंत्र सत्यापन नहीं है कि दावा किए गए आवश्यक पेटेंट वैध हैं और वास्तव में मानक के लिए आवश्यक हैं। ईटीएसआई अपने मानक के लिए किसी कंपनी के दावे की वैधता और अनिवार्यता के बारे में कोई घोषणा नहीं करता है। ईटीएसआई के पास उन सभी प्रौद्योगिकी मानकों का भंडार है जो किसी न किसी रूप में आईपीआर (पेटेंट सहित) के अंतर्गत आते हैं और जो इसके सदस्यों के स्वामित्व में हैं। प्रासंगिक रूप से, नीचे ईटीएसआई आईपीआर ऑनलाइन डेटाबेस पर उपलब्ध अस्वीकरण का प्रासंगिक अंश उद्धृत किया गया है:

“वर्तमान डेटाबेस प्राप्त जानकारी पर आधारित डेटा प्रदान करता है। ईटीएसआई ने जानकारी की वैधता की जाँच नहीं की है, न ही पहचाने गए पेटेंट/पेटेंट आवेदनों की ईटीएसआई मानकों के लिए प्रासंगिकता की जाँच की है और इसलिए यह इस बात की पुष्टि या खंडन नहीं कर सकता है कि पेटेंट/पेटेंट आवेदन वास्तव में आवश्यक हैं या संभावित रूप से आवश्यक हैं। ईटीएसआई द्वारा कोई

जाँच या आईपीआर खोज नहीं की गई है और इसलिए अन्य आईपीआर के अस्तित्व के बारे में कोई गारंटी नहीं दी जा सकती है जो आवश्यक हैं या हो सकते हैं।

संभावित लाइसेंसधारियों को इस डेटाबेस में उपलब्ध जानकारी का उपयोग अपने विवेक के अनुसार करना चाहिए तथा पेटेंट लाइसेंस संबंधी निर्णय लेने से पहले पेटेंट धारकों से संपर्क करना चाहिए, उदाहरण के लिए, किसी प्रकटित पेटेंट परिवार के लिए दावा की गई स्थिति स्थापित करने के लिए।”

6.12 इस प्रकार, यह ध्यान देने योग्य बात है कि दावा किए गए एसईपी की वैधता या अनिवार्यता की कोई गारंटी नहीं है। ऐसे दावों की संख्या बहुत अधिक है तथा इनकी सफलता दर कम है। यहाँ यह उल्लेख करना समीचीन होगा कि चूँकि मानक निर्धारण की प्रक्रिया में प्रतिस्पर्धियों द्वारा उपलब्ध कराए गए समान रूप से व्यवहार्य तकनीकी विकल्पों के संग्रह से प्रौद्योगिकी का चयन करना शामिल है, इसलिए प्रस्ताव के तकनीकी गुणों के अतिरिक्त पक्ष जुटाव, समझौता और खरीद-फरोख्त से जुड़े अन्य मुद्दे भी अक्सर मानक निर्धारण के संदर्भ में निर्णायक कारक बन सकते हैं। पेटेंट को उनके स्वामी के अवसरवादी, रणनीतिक व्यवहार के परिणामस्वरूप मानक में शामिल किया जा सकता है, न कि उनकी तकनीकी गुणागुण के कारण। इस संबंध में, रूडी बेकर की रिपोर्ट, जिसका शीर्षक है, "संगतता मानकों में आवश्यक पेटेंट दावों के निर्धारकों पर एक अनुभवजन्य अध्ययन", अनुलग्नक 1 के रूप में संलग्न है। हालाँकि, सामान्य तौर पर एसएसओ ने ऐसे मानकों को बढ़ावा दिया है जो सर्वोत्तम तकनीकी समाधान प्रदान करते हैं, तथा

नवाचार, अनुकूलता, अंतर-संचालन और विभिन्न प्रकार के उत्पादों के विकास को बढ़ावा देते हैं। उनके प्रयासों के परिणामस्वरूप, मोबाइल नेटवर्क और मोबाइल हैंडसेट सर्वव्यापी हो गए हैं और कम लागत पर अधिक सेवाएँ प्रदान कर रहे हैं।

XXX XXX XXX

6.25 वर्तमान मामले में, कृपया ध्यान दें कि एरिक्सन ने ईटीएसआई को घोषित किया है कि 2जी, 3जी और जीएसएम, डब्ल्यू-सीडीएमए, एलटीई और विभिन्न अन्य वायरलेस प्रौद्योगिकियों पर उसके पेटेंट, जो कि वर्तमान सूचना के लिए प्रासंगिक प्रौद्योगिकियाँ हैं, "मानक आवश्यक पेटेंट" (एसईपी) हैं। इसके पास एसईपी का एक बड़ा पोर्टफोलियो है, जिसकी वैधता या अनिवार्यता का अभी तक न्यायनिर्णयन नहीं किया गया है। एरिक्सन की स्वामिस्व माँगों और अन्य शर्तें पेटेंट स्थगन और स्वामिस्व इकट्ठा करने का खतरा पैदा करती हैं। इसके अतिरिक्त, एरिक्सन ने सीमा-शुल्क अधिकारियों के पास अपने एसईपी भी पंजीकृत करा लिए हैं, जिनकी इस मामले में एकमात्र भूमिका दावेदार के आईपीआर का कथित रूप से अतिलंघन करने वाले माल को परिबद्ध करना है। एरिक्सन के सीमा-शुल्क पंजीकरण अनुलग्नक ट के रूप में संलग्न हैं। उपरोक्त संदर्भ को ध्यान में रखते हुए, सूचक प्रासंगिक बाजार और प्रासंगिक बाजार में एरिक्सन की प्रधानता को परिभाषित करने का प्रयास करता है।

XXX XXX XXX

9.18 अपने आईपी अधिकारों को लागू करने की माँग कर रहे एरिक्सन ने अपने दावा किए गए एसईपी के बड़े पोर्टफोलियो की

वैधता और अनिवार्यता को प्रदर्शित करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की है। इसने यह प्रदर्शित करने के लिए कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है कि इसके द्वारा दावा किए गए पेटेंट भी वैध और आवश्यक माने गए हैं। एरिक्सन का यह दायित्व है कि वह लाइसेंसधारियों को यह दिखाए कि उसके पेटेंट न केवल वैध हैं, बल्कि उसके दावे के आधार पर आवश्यक भी हैं कि वे वास्तव में मानकों से संबंधित हैं और उन्हें संतुष्ट करते हैं।

XXX XXX XXX

9.44 इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि एसईपी की वैधता, अनिवार्यता और अतिलंघन के संबंध में न्यायिक न्यायनिर्णयन के अभाव में, एसईपी धारक द्वारा आईपीआर प्रवर्तन नियमों के अंतर्गत अधिकारों का प्रयोग करने से भावी लाइसेंसधारी को विधि के अंतर्गत बचाव के उपयोग से वंचित होना पड़ता है, जैसे कि दावा किए गए पेटेंटों को अवैध करना और उनकी अनिवार्यता को चुनौती देना। गंभीर रूप से इसका प्रभाव लाइसेंस वार्ता की प्रक्रिया को अनावश्यक रूप से तीव्र करना है, जिससे लाइसेंसधारी को, और अंततः उपभोक्ता को नुकसान होता है।

XXX XXX XXX

9.47 यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि मोबाइल फोन जैसे अत्यधिक जटिल और तकनीकी उत्पाद अनेक पूरक (प्रतिस्थापनीय नहीं) मानक आवश्यक पेटेंटों के साथ काम करते हैं। इस प्रकार, बाजार से ऐसे उत्पादों का कोई भी बहिष्कार, तीसरे पक्षों के स्वामित्व वाले असंख्य वैध एसईपी के सापेक्ष महत्व और आवश्यकता को कम करता है। इसके अतिरिक्त, पेटेंट की वैधता

और अनिवार्यता का निर्धारण किए जाने से पहले ही बहिष्करण आदेश प्राप्त करने/प्रदान करने की कोई भी कार्रवाई, न केवल कंपनी को, बल्कि पूरे उद्योग को भारी नुकसान पहुँचाती है। बहिष्कार से एक शून्यता उत्पन्न होती है, जिसका प्रभाव सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। यह न केवल कथित अतिलंघनकारी उत्पाद को रोकता है, बल्कि संपूर्ण वितरण शृंखला, खुदरा विक्रेताओं और कंपनी के स्वामित्व वाली सुविधाओं/फ्रेंचाइजी के प्रवाह को भी रोकता है। यह किसी उत्पाद को बढ़ावा देने और लॉन्च करने के लिए विज्ञापन व्यय और मीडिया नियोजन व्यय के रूप में लाखों रुपए की बर्बादी करता है और विज्ञापित वस्तुओं के वितरण में कथित विफलता या उपकरणों की सार्वजनिक रूप से घोषित विक्रय तिथियों के कारण विक्रेता की प्रतिष्ठा को अपूरणीय क्षति पहुँचाता है। यह ग्राहकों को अपने उत्पादों से वंचित करता है और उनकी पसंद को सीमित करता है। इसके परिणामस्वरूप राज्य को राजस्व की हानि, बेरोजगारी आदि होती है। इस प्रकार बहिष्कार का उपभोक्ता की पसंद, उत्पाद की उपलब्धता, नवाचार आदि पर एक प्रागनुभविक प्रभाव पड़ता है।”

9. उपरोक्त के आलोक में, उन्होंने प्रतिवाद दिया कि विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा वादग्रस्त पेटेंट की अनिवार्यता और अतिलंघन के मुद्दे पर सीसीआई की सूचना पर भरोसा करना निराधार था।

10. उन्होंने आगे प्रतिवाद दिया कि भले ही एरिक्सन के पोर्टफोलियो में भारत में पंजीकृत आठ वादग्रस्त पेटेंट (अर्थात् आईएन203034, आईएन203036,

आईएन234157, आईएन203686, आईएन213723, आईएन229632, आईएन240471 और आईएन241747) वास्तव में आवश्यक थे, जिनका अभी तक न्यायालय में परीक्षण नहीं किया गया था, लेकिन केवल कुछ पेटेंट के पुनर्विलोकन के आधार पर तैंतीस हजार (33,000) पेटेंट के पूरे पोर्टफोलियो की अनिवार्यता की कोई उपधारणा नहीं बनाई जा सकती थी और एरिक्सन द्वारा दावा किए गए अन्य तैंतीस हजार (33,000) पेटेंट के संबंध में भुगतान करने का कोई निर्देश भी नहीं दिया जा सकता था, विशेषतः तब, जब वे भारत में पंजीकृत भी नहीं हैं।

11. इंटेक्स के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी प्रस्तुत किया कि वादग्रस्त पेटेंट की वैधता साबित करने का दायित्व एरिक्सन पर था क्योंकि पेटेंट की वैधता की कोई उपधारणा नहीं बनाई जा सकती है जैसा कि पेटेंट अधिनियम, 1970 (संक्षेप में 'अधिनियम') की धारा 13(4), 64 और 107 के संयुक्त पठन से स्पष्ट है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि आठ वादग्रस्त पेटेंट अधिनियम की धारा 8(1) और 8(2) के उल्लंघन के कारण अधिनियम की धारा 64(1)(ज) और (ड) के अंतर्गत प्रतिसंहरण के लिए संवेदनशील थे। उन्होंने कहा कि वादग्रस्त पेटेंट के दावे एरिक्सन के संबंधित यूएस पेटेंट के मूल रूप से दायर दावों के समरूप ही थे। उन्होंने अधिनियम की धारा 8 के गैर-अनुपालन के अपने प्रतिविरोध के समर्थन में आईएन 213723 का उदाहरण दिया। उन्होंने अनेक यूएस कार्यालय कार्रवाई रिपोर्टों पर भरोसा करने का प्रयास किया तथा दावा किया कि एरिक्सन के पेटेंट को

अस्वीकृत कर दिया गया तथा बाद में नवीनता और आविष्कारशील कदम के नाम पर अनेक अवसरों पर उनमें संशोधन किया गया। उनके अनुसार, इन संशोधनों का कुल परिणाम यह हुआ कि यूएस पेटेंट आवेदनों में व्यापक बदलाव किया गया तथा प्रत्येक पेटेंट का दायरा बहुत सीमित कर दिया गया। उन्होंने प्रतिवाद दिया कि यूएस पेटेंट और ट्रेडमार्क ऑफिस (संक्षेप में 'यूएसपीटीओ') द्वारा जारी की गई परीक्षण रिपोर्ट्स महत्वपूर्ण थीं, क्योंकि उद्धृत पूर्व कला और उसमें उठाई गई आपत्तियों को दूर करने के लिए, एरिक्सन ने काफी बड़े संशोधन किए। फिर भी, उन्होंने कहा कि इनमें से किसी भी परीक्षण रिपोर्ट या संशोधन को भारतीय पेटेंट कार्यालय के समक्ष विचारार्थ नहीं रखा गया। उनके अनुसार, इसका सीधा परिणाम यह हुआ कि एरिक्सन को भारत में पेटेंट प्राप्त करने में सफलता मिल गई, जो यूएस में मूल रूप से दायर दावों के समरूप ही थे, जिन पर यू.एस. पेटेंट कार्यालय ने आपत्ति जताई थी और बाद में कई संशोधनों के माध्यम से उन्हें सीमित कर दिया था।

12. उन्होंने अंत में कहा कि प्रत्येक वादग्रस्त पेटेंट के लिए अनेक पूर्व कला दस्तावेजों का उद्धरण देते हुए नवीनता और आविष्कारशील कदम की कमी के ठोस आधार पर इंटेक्स द्वारा वादग्रस्त पेटेंट को दी गई चुनौतियों पर आक्षेपित आदेश में कोई चर्चा नहीं की गई।

एरिक्सन की ओर से तर्क

13. इसके विपरीत, एरिक्सन के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा कि सीसीआई शिकायत में, इंटेक्स ने स्वीकार किया था कि उसे दूरसंचार प्रौद्योगिकी से संबंधित एरिक्सन के मानक आवश्यक पेटेंट के लिए लाइसेंस लेने की आवश्यकता थी क्योंकि कोई गैर-अतिलंघनकारी विकल्प उपलब्ध नहीं थे (सीसीआई शिकायत के पैराग्राफ 7.12-7.13, 8.4, 8.6-8.8)।

14. उन्होंने प्रतिवाद दिया कि सीसीआई के समक्ष दायर सूचना के पैराग्राफ 3.2 में एरिक्सन के पेटेंट की वैधता और अनिवार्यता को चुनौती देने वाला कोई प्रकथन नहीं था। उन्होंने बताया कि इंटेक्स ने सूचना के पैराग्राफ 9.18 में दोषपूर्ण ढंग से कहा है कि एरिक्सन ने अपने पेटेंट की वैधता और अनिवार्यता को प्रदर्शित करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। उन्होंने कहा कि एरिक्सन ने सीसीआई के समक्ष सूचना/शिकायत लगभग पाँच वर्षों की लंबी वार्ता के बाद ही दायर की थी, जिसके दौरान एरिक्सन ने इंटेक्स को अपने मानक आवश्यक पेटेंटों की एक सूची, अनिवार्यता दर्शाने के लिए दावा मानचित्रण चार्ट तथा अतिलंघन दर्शाने के लिए एक परीक्षण रिपोर्ट भी उपलब्ध कराई थी। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि वार्ता के दौरान, इंटेक्स ने भारतीय सेलुलर एसोसिएशन (आईसीए) को भेजे गए 13 अगस्त, 2012 के ईमेल के जवाब में, जिसमें परीक्षण रिपोर्ट शामिल थी, अपने तकनीकी दल से स्पष्ट रूप से पूछा था कि क्या एरिक्सन की प्रौद्योगिकी को

निष्क्रिय किया जा सकता है। उन्होंने प्रतिवाद दिया कि इस स्पष्ट स्वीकारोक्ति ने इसके विपरीत दिए गए सभी तर्कों को नकार दिया।

15. उन्होंने कहा कि इंटेक्स जैसी बड़ी और महत्वपूर्ण वाणिज्यिक इकाई होने के नाते, यदि उसे वादग्रस्त पेटेंट की अनिवार्यता के संबंध में कोई संदेह था, तो उसे एरिक्सन से लाइसेंस लेने की आवश्यकता के संबंध में अपने उपकरण निर्माताओं से आवश्यक स्पष्टीकरण लेना चाहिए था।

16. उन्होंने प्रस्तुत किया कि इंटेक्स द्वारा शिकायत के पैराग्राफ 6.11-6.12 में यूरोपीयन टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्ड्स इंस्टिट्यूट (संक्षेप में 'ईटीएसआई') बौद्धिक संपदा अधिकार नीति की व्याख्या त्रुटिपूर्ण थी, क्योंकि मूल्य उस प्रौद्योगिकी में था जो मानक का भाग थी और वादग्रस्त पेटेंट केवल उस प्रौद्योगिकी के प्रतिनिधि थे।

17. उन्होंने आगे प्रतिवाद दिया कि सीसीआई की शिकायत में मानक निर्धारण प्रक्रिया और मानक आवश्यक पेटेंट न्यायशास्त्र में देखी गई प्रवृत्तियों के संबंध में सामान्य प्रकथन शामिल थे। उन्होंने कहा कि सीसीआई की शिकायत के पैराग्राफ 6.10 में विभिन्न संस्थाओं के विरुद्ध विदेशों में लंबित उदाहरणात्मक मानक आवश्यक पेटेंट मामलों की प्रवृत्ति पर चर्चा की गई है। उन्होंने प्रतिवाद दिया कि उक्त पैराग्राफ में उल्लिखित "दावा किए गए पेटेंट" तीसरे पक्ष के मुकदमों से संबंधित हैं, न कि एरिक्सन से, क्योंकि सीसीआई की शिकायत वर्तमान वाद से पहले की है।

18. उन्होंने कहा कि *हुआवेई टेक्नोलॉजीज कंपनी लिमिटेड बनाम जेडटीई कॉर्प और जेडटीई डॉयचलैंड जीएमबीएच, दिनांक 16 जुलाई 2015, मामला संख्या सी-170/13* में कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑफ द यूरोपीयन यूनियन (सीजेईयू) के निर्णय के अंतर्गत निर्धारित एफआरएएनडी प्रोटोकॉल के अनुसार लाइसेंस लेने का दायित्व 'कथित अतिलंघनकर्ता' पर है, जो यह मानता है कि अनिवार्यता और वैधता का कोई न्यायनिर्णयन नहीं होना है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि *हुआवेई बनाम जेडटीई* (पूर्वोक्त) के पैराग्राफ 69 में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि कथित अतिलंघनकर्ता बाद के चरण में मानक आवश्यक पेटेंट की वैधता और अनिवार्यता को चुनौती देने का अपना अधिकार सुरक्षित रख सकता है।

19. उन्होंने कहा कि इंटेक्स ने स्वीकार किया है कि एरिक्सन के पास दूरसंचार प्रौद्योगिकियों के लिए तैंतीस हजार (33,000) पेटेंट हैं और उसके सभी पेटेंट की वैधता और अनिवार्यता पर निर्णय देना असंभव है। उनके अनुसार, यू.के. सुप्रीम कोर्ट ने *अनवायर्ड प्लैनेट बनाम हुआवेई* (पूर्वोक्त) में दर्ज किया कि बड़ी संख्या में बिना जाँचे-परखे गए पेटेंट का लाइसेंस लेने से, कार्यान्वयनकर्ता भी "निश्चितता खरीदता है।"

20. उन्होंने इस बात से इनकार किया कि एरिक्सन ने इंटेक्स को बाजार से बाहर करने की माँग की थी। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि एरिक्सन का तर्क यह था कि वह इन प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान एवं विकास में आवश्यक संसाधनों

का निवेश कर रहा है और उसे विधि के दायरे में इसके लिए उचित प्रतिकर मिलना चाहिए।

21. एरिक्सन के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि अधिनियम की धारा 8(1) का कोई गैर-अनुपालन नहीं हुआ था और इस संबंध में कोई गंभीर चुनौती नहीं उठाई गई थी। उन्होंने कहा कि गैर-अनुपालन का साक्ष्य दिखाए बिना, इंटेक्स ने अपनी अपील में अभिवाक् दिया था कि *"आठ वादग्रस्त पेटेंटों के संबंध में 33 विदेशी परीक्षण रिपोर्ट्स के प्रत्यर्थी द्वारा लगातार और बार-बार अवरुद्ध करने से दुर्भावना का अनुमान लगाया जाना चाहिए, और इन अवरोधों की महत्ता से हस्तक्षेप किया जाना चाहिए.... अपीलार्थी केवल महत्वपूर्ण और प्रतिकूल विदेशी परीक्षण रिपोर्ट्स को अवरुद्ध करने में प्रत्यर्थी के बार-बार आचरण से दुर्भावना का अनुमान लगा सकता है।"*

22. उनके अनुसार, उपरोक्त प्रस्तुतीकरण इस न्यायालय की खंड पीठ द्वारा *मर्क शार्प एंड डोहमे कॉर्पोरेशन एवं अन्य बनाम ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स, 2015 एससीसी ऑनलाइन दिल्ली 8227* में निर्धारित विधि के विपरीत है।

23. उन्होंने स्पष्ट किया कि यूएसपीटीओ द्वारा जारी परीक्षण रिपोर्ट्स को "गैर-अंतिम अस्वीकृति" कहा गया है, जिसका मतलब यह नहीं है कि पेटेंट को यूएसपीटीओ द्वारा खारिज कर दिया गया था, बल्कि इसका मतलब केवल यह था कि उनका परीक्षण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पेटेंटों के परीक्षण के दौरान

परीक्षकों द्वारा पूर्व कला दस्तावेजों के आधार पर आपत्तियाँ उठाना आम बात है, जिसका उद्देश्य दावा किए गए आविष्कार की नवीनता और आविष्कारशील कदम को चुनौती देना होता है और जिसे ठीक किया जा सकता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यद्यपि संबंधित यूएस पेटेंट के दावों में संशोधन किया गया है, लेकिन *बिथनाथ प्रसाद राधेश्याम बनाम हिंदुस्तान मेटल इंडस्ट्रीज; एआईआर 1982 एससी 1444* में दावा निर्माण पर स्थापित कानून यह है कि पेटेंटधारी के दावों को अलग से नहीं पढ़ा जाना चाहिए और इसके पूर्ण दायरे को समझने के लिए इसे संपूर्ण विनिर्देश के साथ पढ़ा जाना चाहिए।

24. उन्होंने कहा कि वर्तमान मामले में नियंत्रक की परीक्षण रिपोर्ट के जवाब में, एरिक्सन ने यूएसए और यूरोप में पेटेंट के लिए विधिवत दावे दायर किए थे, जिसके बाद कोई और आपत्ति नहीं उठाई गई। उनके अनुसार, इससे पता चलता है कि नियंत्रक इस बात से संतुष्ट था कि भारतीय दावे यूएस दावों के संबंध में शामिल किए गए थे और इसमें कोई महत्वपूर्ण विचलन नहीं था।

25. उन्होंने प्रतिवाद दिया कि उनके कार्यालय की कार्रवाइयों के जवाब में यूएस में आईएन'723 से संबंधित पेटेंट में किए गए सभी संशोधन, संपूर्ण विनिर्देशों के संदर्भ में समग्र रूप से पढ़े जाने पर भारत के पेटेंट द्वारा विधिवत शामिल किए गए थे। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि स्वीकृत दावे, यूरोपीयन पेटेंट (ईपी) में

स्वीकृत दावों के समान ही थे। उन्होंने कहा कि यह बात नीचे दिए गए रंग-बद्ध वर्गीकृत दावा तुलना चार्ट से स्पष्ट है:-

“स्वीकृत दावा 1 का तुलनात्मक चार्ट – यूएस 7124079, ईपी 1145222 सह आईएन 213723

यू.एस. 7124079 में दायर प्रारंभिक यू.एस. दावा	यू.एस. में जारी की गई कार्यालय कार्रवाईयाँ	यू.एस. में अंतिम स्वीकृत दावे (मूल दावा 1 को हटा दिया गया और नीचे दिए गए दावे द्वारा प्रतिस्थापित किया गया - परिवर्धन रेखांकित है)	संपूर्ण विनिर्देश में पाठ जो पेटेंट किए गए आविष्कार का विवरण देता है	स्वीकृत भारतीय दावा (प्रारंभिक यू.एस. दावे के अनुरूप)	स्वीकृत ई.पी. दावा (स्वीकृत ई.पी. दावे के अनुरूप)
संचार चैनल से वाणी और ध्वनि की जानकारी प्राप्त करने वाले स्पीच डिकोडर में आरामदायक ध्वनि उत्पन्न करने की एक विधि, जिसमें शामिल हैं: सामान्यतः आरामदायक ध्वनि उत्पन्न करने के लिए स्पीच डिकोडर द्वारा उपयोग किए जाने वाले आरामदायक ध्वनि मापदंड मानों की बहुलता प्रदान करना; परिवर्तनशीलता जानकारी में पृष्ठभूमि ध्वनि मापदंड की परिवर्तनशीलता का संकेत देने वाली	कार्यालय कार्रवाई 1: 13 फरवरी 2002 को जारी की गई। दावा 1 (अन्य के साथ) नवीनता के तहत खारिज कर दिया गया था (35 102) कार्यालय कार्रवाई 2: 11 सितंबर, 2002 को जारी की गई : दावा 1 (अन्य के	स्पीच डिकोडर में आरामदायक ध्वनि उत्पन्न करने की एक विधि में, जिसमें स्पीच डिकोडर एक संचार चैनल के माध्यम से एक एनकोडर से वाणी जानकारी और आरामदायक ध्वनि मापदंड मानों की बहुलता प्राप्त करता है, और डिकोडर आरामदायक ध्वनि मापदंड मानों की बहुलता को प्रक्षेपित करता है और प्रक्षेपित आरामदायक ध्वनि मापदंड मानों से आरामदायक आवाज उत्पन्न करता है, एक सुधार जिसमें शामिल है: स्पीच डिकोडर द्वारा, रिसीवर बफर से पृष्ठभूमि के ध्वनि	पूर्ण विनिर्देशों के संकलन का पृष्ठ 105 ".....एक पारंपरिक डिकोडर में, आरामदायक ध्वनि मापदंडों को प्राप्त और डिकोड किया जा सकता है जैसा कि चित्र 2 में दिखाया गया है। चूंकि डिकोडर नए आरामदायक ध्वनि मापदंडों को उतनी बार प्राप्त नहीं करता है जितनी बार वह सामान्य रूप से वाणी मापदंडों को प्राप्त करता है, आरामदायक ध्वनि मापदंडों को जो एसआईडी फ्रेम में प्राप्त होते हैं, उन्हें आम तौर पर 23 पर प्रक्षेपित किया जाता	एक संचार चैनल (95) से वाणी और ध्वनि की जानकारी प्राप्त करने वाले स्पीच डिकोडर (93) में आरामदायक ध्वनि उत्पन्न करने की एक विधि, जिसमें आरामदायक ध्वनि मापदंड मान (33) की बहुलता प्रदान करना शामिल है, जो सामान्य रूप से स्पीच डिकोडर (93) द्वारा आरामदायक ध्वनि उत्पन्न करने के लिए उपयोग किया जाता है, और इसकी विशेषता है: पृष्ठभूमि ध्वनि मापदंड (37) की परिवर्तनशीलता का संकेत देने वाली	एक संचार चैनल (95) से वाणी और ध्वनि की जानकारी प्राप्त करने वाले स्पीच डिकोडर (93) में आरामदायक ध्वनि उत्पन्न करने की एक विधि, जिसमें आरामदायक ध्वनि मापदंड मान (33) की बहुलता प्रदान करना शामिल है, जो सामान्य रूप से स्पीच डिकोडर (93) द्वारा आरामदायक ध्वनि उत्पन्न करने के लिए उपयोग किया जाता है, और इसकी विशेषता है: पृष्ठभूमि ध्वनि मापदंड (37) की परिवर्तनशीलता का संकेत देने वाली

<p>परिवर्तनशीलता जानकारी प्राप्त करना; आरामदायक ध्वनि मापदंड मानों को संशोधित करके संशोधित आरामदायक ध्वनि मापदंड मानों का उत्पादन करना, और आरामदायक ध्वनि उत्पन्न करने के लिए आरामदायक ध्वनि मापदंड मानों का उपयोग करना।</p>	<p>साथ) स्पष्टता के तहत खारिज कर दिया गया (35 103) कार्यालय कार्रवाई 3: 31 दिसंबर, 2002 को जारी की गई। कार्यालय कार्रवाई 4: 28 मई, 2003 को जारी की गई। दावा 1 (अन्य के साथ) को स्पष्टता के आधार पर खारिज कर दिया गया (35 103) कार्यालय कार्रवाई 5: 18 दिसंबर, 2003 को जारी की गई। दावा 1 (अन्य के साथ) को स्पष्टता के आधार पर खारिज कर दी गई (35</p>	<p>मापदंड मान प्राप्त करना, उक्त पृष्ठभूमि ध्वनि मापदंड मान वास्तविक पृष्ठभूमि ध्वनि का प्रतिनिधित्व करते हैं; स्पीच डिकोडर पर एक समयावधि में पृष्ठभूमि ध्वनि मापदंड मानों के औसत मान की गणना करना; स्पीच डिकोडर पर परिवर्तनशीलता सूचना की गणना करना जो यह संकेत देती है कि पृष्ठभूमि ध्वनि मापदंड मान, पृष्ठभूमि ध्वनि मापदंड मान के परिकलित औसत मान के सापेक्ष किस प्रकार भिन्न होते हैं; परिवर्तनशीलता की जानकारी के जवाब में, उद्विग्न आरामदायक ध्वनि मापदंड मानों का उत्पादन करने के लिए स्पीच डिकोडर द्वारा प्रक्षेपित आरामदायक ध्वनि मापदंड मानों को उद्विग्न करना; और स्पीच डिकोडर द्वारा चयन, उद्विग्न आरामदायक आवाज़ उत्पन्न करने में उपयोग के लिए कम से कम कुछ उद्विग्न आरामदायक ध्वनि</p>	<p>है ताकि आरामदायक ध्वनि संश्लेषण में मापदंडों का सुचारु विकास हो सके। आविष्कार के अनुसार, पारंपरिक रूप से उत्पन्न आरामदायक ध्वनि मापदंडों को एनकोडर पर अनुभव किए गए वास्तविक पृष्ठभूमि ध्वनि के गुणों के आधार पर परिवर्तित किया जाता है..... पूर्ण विनिर्देशों के संकलन का पृष्ठ 107 परिवर्तक 30, 31 पर प्राप्त पृष्ठभूमि ध्वनि मापदंडों के आधार पर प्राप्त आरामदायक ध्वनि मापदंडों को परिवर्तित करता है, जिससे 35 पर परिवर्तित आरामदायक ध्वनि मापदंड उत्पन्न होते हैं.....परिवर्तक में एक परिवर्तनशीलता अनुमानक 41 शामिल है जो पृष्ठभूमि ध्वनि के स्पेक्ट्रम और ऊर्जा मापदंडों को प्राप्त करने के लिए इनपुट 31 से जुड़ा हुआ है। परिवर्तनशीलता अनुमानक 41 पृष्ठभूमि आवाज़ मापदंडों की परिवर्तनशीलता विशेषताओं का अनुमान लगाता है,</p>	<p>परिवर्तनशीलता जानकारी (31) प्राप्त करना; परिवर्तनशीलता सूचना के जवाब में, आरामदायक ध्वनि मापदंड, मान (33) को परिवर्तित करके (30) परिवर्तित आरामदायक ध्वनि मापदंड (35) उत्पन्न करना; और आरामदायक ध्वनि (25) उत्पन्न करने के लिए परिवर्तित आरामदायक ध्वनि मापदंड मान (35) का उपयोग करना, जिसमें परिवर्तनशीलता सूचना यह दर्शाती है कि पृष्ठभूमि ध्वनि मापदंड समय और पृष्ठभूमि ध्वनि मापदंड के औसत मान में से कम से कम एक के संबंध में कैसे भिन्न होता है।</p>	<p>परिवर्तनशीलता जानकारी (31) प्राप्त करना; परिवर्तनशीलता सूचना के जवाब में, आरामदायक ध्वनि मापदंड, मान (33) को परिवर्तित करके (30) परिवर्तित आरामदायक ध्वनि मापदंड मान (35) उत्पन्न करना; और आरामदायक ध्वनि (25) उत्पन्न करने के लिए परिवर्तित आरामदायक ध्वनि मापदंड मान (35) का उपयोग करना, जिसमें परिवर्तनशीलता सूचना यह दर्शाती है कि पृष्ठभूमि ध्वनि मापदंड समय और पृष्ठभूमि ध्वनि मापदंड के औसत मान में से कम से कम एक के संबंध में कैसे भिन्न होता है।</p>
--	--	---	---	---	---

	<p>103) कार्यालय कार्रवाई 6: 7 जून, 2004 को जारी की गई। दावा 1 (अन्य के साथ) को स्पष्टता के आधार पर खारिज कर दिया गया (35 103) कार्यालय कार्रवाई 7: 17 दिसंबर, 2004 को जारी की गई। दावा 1 (अन्य के साथ) को स्पष्टता के आधार पर खारिज कर दिया गया (35 103) कार्यालय कार्रवाई 8: 9 सितंबर, 2005 को जारी की गई: दावा 1 (अन्य के साथ) समर्थन के अभाव में</p>	<p><u>मापदंड मान।</u></p>	<p>और 43 पर पृष्ठभूमि ध्वनि मापदंडों की परिवर्तनशीलता के संकेतात्मक सूचना का आउटपुट देता है। परिवर्तनशीलता सूचना परिवर्तनशीलता मापदंडों को उनके औसत मूल्य के बारे में चिह्नित कर सकती है, उदाहरण के लिए मापदंडों का विचरण या उनके औसत मूल्य से मापदंड का अधिकतम विचलन.....</p> <p>पूर्ण विनिर्देशों के संकलन का पृष्ठ 110</p> <p>चित्र 4 का संयोजक प्रवर्धित आउटपुट एक्सपी(के) को पारंपरिक आरामदायक ध्वनि मापदंडों के साथ संयोजित करने के लिए संचालित होता है.....चित्र 5 का प्रवर्धित आउटपुट एक्सपी(के) इस प्रकार एक उद्विग्न करने वाला संकेत माना जा सकता है जिसका उपयोग संयोजक 45 द्वारा 33 पर प्राप्त पारंपरिक आरामदायक आवाज़ मापदंडों को उद्विग्न करने के लिए किया जाता है ताकि आरामदायक ध्वनि</p>		
--	--	---------------------------	--	--	--

	<p>खारिज कर दी गई (35 112)</p>		<p>संश्लेषण अनुभाग 25 में इनपुट किए जाने वाले परिवर्तित (या उद्विग्न) आरामदायक ध्वनि मापदंडों का उत्पादन किया जा सके (चित्र 2-4 देखें) पारंपरिक आरामदायक ध्वनि संश्लेषण अनुभाग 25 पारंपरिक तरीके से उद्विग्न आरामदायक ध्वनि मापदंडों का उपयोग कर सकता है। पारंपरिक मापदंडों में गड़बड़ी के कारण, उत्पन्न आरामदायक ध्वनि में अर्ध-परिवर्तनशीलता होगी जो अधिक परिवर्तनशील पृष्ठभूमि जैसे बड़बड़ाहट और सड़क की आवाज़ के साथ-साथ कार की आवाज़ के लिए अनुभव की गई गुणवत्ता को काफी बढ़ा देती है.....</p>		
--	--------------------------------	--	---	--	--

26. उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि अधिनियम की धारा 8(2) के अंतर्गत दायित्व न तो स्वैच्छिक है, न ही आवधिक है क्योंकि इसके अंतर्गत नियंत्रक को प्रासंगिक समझी जाने वाली सूचना को माँगना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि नियंत्रक द्वारा उठाए गए प्रश्नों के जवाब में एरिक्सन ने सभी प्रासंगिक सामग्री दाखिल कर दी थी, जिसके प्राप्त होने के बाद उस पर कोई और माँग नहीं की गई तथा पेटेंट

विधिवत प्रदान कर दिए गए। इस प्रकार, अधिनियम की धारा 8(2) के अंतर्गत की गई माँगों की उचित संतुष्टि के बाद ही नियंत्रक ने एरिक्सन के पेटेंट प्रदान करने की कार्यवाही की।

27. उन्होंने प्रतिवाद दिया कि प्रपत्र 3 में प्रासंगिक पेटेंट आवेदन संख्याओं के प्रकटीकरण पर, संबंधित आवेदनों के अभियोजन इतिहास तक पहुँचने के लिए नियंत्रक के पास पर्याप्त विवरण उपलब्ध थे। बार-बार कार्यालय कार्रवाई रिपोर्ट उपलब्ध कराने के भारी दायित्व को स्वीकार करते हुए उन्होंने कहा कि पेटेंट कार्यालय ने 12 मार्च, 2018 के अपने परिपत्र के माध्यम से नियंत्रकों को निर्देश दिया है कि वे संबंधित पेटेंटों के आवेदन संख्याएँ उन्हें उपलब्ध करा दिए जाने के बाद स्वयं ही पेटेंटों के अभियोजन विवरण तक पहुँच प्राप्त कर लें।

28. उन्होंने यह भी प्रतिवाद दिया कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने इंटेक्स द्वारा लगाए गए पूर्व कला के आरोप का विस्तार से परीक्षण किया था। उन्होंने कहा कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने पैराग्राफ 127 में दर्ज किया था कि पेटेंट प्रथम दृष्टया वैध थे। आक्षेपित निर्णय का उक्त पैराग्राफ नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:-

"127. प्रतिवादी द्वारा उठाई गई आपत्ति पर विचार करने के बाद, जिसका वादी द्वारा उचित उत्तर दिया गया है, तथा उस पर विचार करने के पश्चात, यह न्यायालय इस राय पर पहुँचा है कि पेटेंट के अतिलंघन के वाद में अंतरिम स्तर पर वादग्रस्त पेटेंट के विषय-वस्तु के सभी दावों का सूक्ष्मता से परीक्षण नहीं किया जा सकता है या उनकी सूक्ष्म रूप से व्याख्या नहीं की जा सकती है। अधिकरण के

समक्ष लंबित प्रतिसंहरण याचिकाओं को ध्यान में रखते हुए पेटेंट की वैधता का मुद्दा इस स्तर पर अंतिम रूप से निर्धारित नहीं किया जा सकता है। वर्तमान में मामले का केवल प्रथम दृष्टया परीक्षण किया जाना है कि क्या प्रतिसंहरण याचिका में लिए गए आधार मान्य हैं या नहीं। प्रतिवादी द्वारा उठाई गई आपत्तियों और वादी द्वारा दिए गए उत्तर पर विचार करने के बाद, प्रथम दृष्टया वाद के पेटेंट वैध प्रतीत होते हैं और न्यायालय को प्रतिवादी द्वारा उठाए गए विश्वसनीय बचाव का कोई उचित मामला नहीं लगता है। प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत तर्क को वर्तमान में स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि ऐसे कई अन्य कारण हैं जो वादग्रस्त पेटेंट की वैधता के बारे में प्रतिवादी के तर्कों को नकारते हैं। इस तरह के विवरण मेरे निर्णय के बाद के पैराग्राफ में दिए गए हैं।”

29. एरिक्सन के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि इस न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा **नोकिया बनाम ओप्पो** (पूर्वोक्त) के मामले में पारित दिनांक 17 नवम्बर, 2022 के निर्णय का वर्तमान मामले पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि यह नोकिया द्वारा प्रस्तुत सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (संक्षेप में 'सि.प्र.सं.') के आदेश XXXIX नियम 10 के अंतर्गत आवेदन से संबंधित था। उन्होंने बताया कि उक्त निर्णय के पैराग्राफ 9 में यह उल्लेख किया गया था कि आदेश XXXIX नियम 1 और 2 सि.प्र.सं. के अंतर्गत एक अंतरिम व्यादेश आवेदन मामले में अलग से लंबित था। इस प्रकार, उन्होंने कहा कि उक्त मामले में नोकिया द्वारा माँगी गई राहतें आदेश XXXIX नियम 1 और 2 सि.प्र.सं. के अंतर्गत माँगी गई राहतों से पहले की थीं।

30. वैकल्पिक रूप से, उन्होंने प्रस्तुत किया कि, यदि **नोकिया बनाम ओप्पो** (पूर्वोक्त) के पैराग्राफ 77 को अंतरिम व्यादेश प्रदान करने के लिए सिद्धांत निर्धारित

करने वाला माना जाता है, तो यह मानक आवश्यक पेटेंट व्यवस्था के संबंध में त्रुटिपूर्ण था, क्योंकि *नोकिया बनाम ओप्पो* (पूर्वोक्त) के पैराग्राफ 77 के निष्कर्ष *अनवायर्ड प्लैनेट बनाम हुआवेई* (पूर्वोक्त) के गलत और सीमित पठन पर आधारित थे। उन्होंने प्रस्तुत किया कि *अनवायर्ड प्लैनेट बनाम हुआवेई* (पूर्वोक्त), विशेष रूप से इसके पैराग्राफ 60-61 और 64 को उचित रूप से पढ़ने से पता चलता है कि *नोकिया बनाम ओप्पो* (पूर्वोक्त) के पैराग्राफ 77 में दिए गए निष्कर्ष *अनवायर्ड प्लैनेट बनाम हुआवेई* (पूर्वोक्त) का सटीक सारांश नहीं थे। उन्होंने कहा कि यह निम्नलिखित से भी स्पष्ट है:-

क. यह साबित करने की आवश्यकता कि "दावा किए गए" वादग्रस्त पेटेंट मानक आवश्यक पेटेंट थे और उनका अतिलंघन किया गया था [नोकिया बनाम ओप्पो (पूर्वोक्त) के अनुसार] *अनवायर्ड प्लैनेट बनाम हुआवेई* (पूर्वोक्त) के निष्कर्षों के पूरी तरह से विपरीत था, जिसमें यह स्पष्ट किया गया था कि:

- मानक आवश्यक पेटेंट के स्वामी और कार्यान्वयनकर्ता किसी मानक में शामिल सभी पेटेंटों की वैधता और अतिलंघन का परीक्षण व्यावहारिक रूप से नहीं कर सकते थे, जो कि एक बड़ा पोर्टफोलियो था (पैराग्राफ 60);
- मानक आवश्यक पेटेंट स्वामी न केवल उन पेटेंट में प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के अधिकार के लिए भुगतान करने का हकदार था, जिन्हें वैध और अतिलंघन के रूप में स्थापित किया गया था [*अनवायर्ड प्लैनेट*

बनाम हुआवेई (पूर्वोक्त) का पैराग्राफ 61]; लेकिन व्यावहारिक समाधान यह था कि मानक आवश्यक पेटेंट स्वामी अपने "घोषित" मानक आवश्यक पेटेंट (पैराग्राफ 60) के पूरे पोर्टफोलियो का लाइसेंस प्रदान करे;

- सामान्यतः अपरीक्षित पेटेंटों के एक अंतरराष्ट्रीय पोर्टफोलियो का लाइसेंस उस मूल्य पर लेकर, जो पोर्टफोलियो में पेटेंटों की अपरीक्षित प्रकृति को प्रतिबिंबित करता है, कार्यान्वयनकर्ता ने निश्चितता खरीदी है (पैराग्राफ 60)।

ख. *नोकिया बनाम ओप्पो* (पूर्वोक्त) में विद्वान एकल न्यायाधीश ने "लाइसेंस के अनुदान" के मुद्दे से संबंधित निर्णय को केवल "दावा किए गए" पेटेंटों तक सीमित करने में गलती की, क्योंकि *अनवायर्ड प्लैनेट बनाम हुआवेई* (पूर्वोक्त) ने यह स्पष्ट कर दिया कि मानक आवश्यक पेटेंट के स्वामी के लिए मानक आवश्यक पेटेंट के अपने संपूर्ण "घोषित" पोर्टफोलियो के लिए स्वामिस्व का दावा करना पूरी तरह से वैध था;

ग. "घोषित मानक आवश्यक पेटेंट" शब्द के प्रयोग ने इस प्रतिवाद को और बल दिया कि मानक आवश्यक पेटेंट की वैधता और अतिलंघन अंतरिम जमा के निर्धारण के लिए प्रासंगिक नहीं थे। यह *हुआवेई बनाम जेडटीई* (पूर्वोक्त) के मामले में निर्णय के अनुरूप था, जिसे *अनवायर्ड प्लैनेट बनाम हुआवेई* (पूर्वोक्त) में यूके सुप्रीम कोर्ट द्वारा विशेष रूप से अनुमोदित किया गया था;

घ. इसके अतिरिक्त, *नोकिया बनाम ओप्पो* (पूर्वोक्त) के पैराग्राफ 77 में उल्लिखित कारक (iii) और (iv) के लिए एफआरएएनडी निर्धारण की आवश्यकता थी, जिसके लिए आर्थिक विशेषज्ञों के बयान के साथ एक पूर्ण

परीक्षण की भी आवश्यकता थी, और यह एक ऐसा कार्य था जिसे अंतरिम/अंतरिम चरण में नहीं किया जा सकता था।

ड. किसी भी सिविल विचारण में अंतरिम राहत का उद्देश्य पक्षकारगण के हितों की रक्षा करना है, जब तक कि प्रतिवादी पक्षकारगण के अधिकारों और दायित्वों पर अनिश्चितता बनी रहे। इसलिए, भुगतान जैसे अंतरिम राहत का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि जब तक न्यायालय मामले पर अंतिम निर्णय नहीं दे देता, तब तक इक्विटी संतुलित रहे। हालाँकि, *नोकिया बनाम ओप्यो* (पूर्वोक्त) के कारक (iii) और (iv) से ऐसा प्रतीत होता है कि अंतरिम राहत पारित करने के लिए भी, न्यायालय को पक्षकारगण द्वारा किए गए प्रस्तावों और प्रति-प्रस्तावों की एफआरएनडी प्रकृति पर निर्णायक रूप से निश्चित होने की आवश्यकता थी। ऐसा दृष्टिकोण न केवल मानक आवश्यक पेटेंट और एफआरएनडी मामलों के संदर्भ में विश्व स्तर पर विकसित न्यायशास्त्र के विपरीत होगा, बल्कि अंतरिम राहत देने या न देने को विनियमित करने वाले इस देश के न्यायशास्त्र के भी विपरीत होगा, जिसके अनुसार न्यायालयों को तब भी अंतरिम राहत देने का अधिकार है, जब पक्षकारगण के अधिकार अनिश्चित रहते हैं।

च. *नोकिया बनाम ओप्यो* (पूर्वोक्त) में पैराग्राफ 77 में "लाइसेंस" शब्द का उपयोग यह दर्शाता है कि विद्वान एकल न्यायाधीश के अनुसार भी, एक अंतरिम आदेश उसके निर्णय के दायरे से बाहर था क्योंकि न्यायालय के आदेश के तत्वावधान में तय की गई अंतरिम व्यवस्था पक्षकारगण के बीच लाइसेंस के समान नहीं हो सकती थी।

31. उन्होंने अंत में कहा कि एरिक्सन की क्रॉस-अपील आक्षेपित आदेश के पैराग्राफ 161 में दिए गए निष्कर्ष को चुनौती देने तक सीमित है, जिसके अंतर्गत विद्वान एकल न्यायाधीश ने निर्देश दिया था कि इंटेक्स द्वारा देय 50% अंतरिम स्वामिस्व इस न्यायालय के महा निबंधक के पक्ष में बैंक गारंटी के रूप में प्रस्तुत की जाए। उन्होंने प्रतिवाद दिया कि एरिक्सन अन्य अतिलंघनकर्ताओं के विरुद्ध दायर मामलों में पारित आदेशों के अनुरूप पूरी राशि नकद जमा कराने का आदेश चाहता है।

इंटेक्स की ओर से प्रत्युत्तर तर्क

32. प्रत्युत्तर में, इंटेक्स के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत वैधता की धारणा की कमी को एरिक्सन के कहने पर केवल इसलिए कम नहीं किया जा सकता क्योंकि उसने दावा किया था कि कथित वादग्रस्त पेटेंट मानक आवश्यक पेटेंट थे। उन्होंने दोहराया कि अधिनियम में मानक आवश्यक पेटेंट की अवधारणा को मान्यता नहीं दी गई है, और इसलिए, अधिनियम में निहित स्पष्ट प्रावधान को किसी विशेष प्रकार के पेटेंट के लिए कमजोर नहीं किया जा सकता। उन्होंने प्रस्तुत किया कि अधिनियम की धारा 13(4) की व्याख्या और उसे लागू करने के संबंध में इस न्यायालय की खंडपीठों द्वारा दिए गए कई ऐतिहासिक निर्णयों में, यह लगातार अभिनिर्धारित किया गया है कि अंतरिम व्यादेश के लिए पेटेंटधारी की प्रार्थना पर विचार करते समय,

न्यायालय को गुणागुण के आधार पर इंटेक्स द्वारा उठाए गए कथित पेटेंट की वैधता को चुनौती की विश्वसनीयता पर विचार करना चाहिए। उन्होंने प्रस्तुत किया कि *एफ.हॉफमैन-एलए रोश लिमिटेड बनाम सिप्ला लिमिटेड, 2009 एससीसी ऑनलाइन दिल्ली 1074* में, यह अभिनिर्धारित किया गया है कि भले ही कोई पेटेंट अनुदान-पूर्व विरोध या अनुदान-पश्चात विरोध को सफलतापूर्वक झेल लेता है, तो भी उसे प्रकल्पित वैधता प्रदान नहीं की जाती है।

33. वैकल्पिक रूप से, उन्होंने प्रस्तुत किया कि यदि कोई पेटेंट आवश्यक भी हो, तो यह मानने का कोई कारण नहीं है कि पेटेंट वैध है, क्योंकि वैधता और अनिवार्यता दो अलग-अलग पहलू/मुद्दे हैं। उनके अनुसार, अनिवार्यता का संबंध पेटेंट के अतिलंघन के मुद्दे से है, जबकि वैधता का संबंध इस बात से है कि क्या पेटेंट को प्रदान किया जाना चाहिए था। इसलिए, आक्षेपित निर्णय वैधानिक ढाँचे और सामान्य ज्ञान के विरुद्ध गया क्योंकि इसने वैधता चुनौती की गुणवत्ता का परीक्षण किए बिना ही, भले ही प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता हो, कथित अनिवार्यता के आधार पर पेटेंट को लागू करने की कार्यवाही की। उन्होंने प्रस्तुत किया कि अधिनियम की धारा 107 के अंतर्गत प्रतिवादी को अतिलंघन के आरोप के बचाव के रूप में अवैधता का मुद्दा उठाने का अधिकार है। दूसरे शब्दों में, उन्होंने कहा कि भले ही इंटेक्स ने पेटेंट के अतिलंघन को स्वीकार किया हो, लेकिन वह अतिलंघन के बचाव के रूप में पेटेंट की अवैधता को उठाने का हकदार

था। उनके अनुसार, पेटेंट की भाषा में इसे सामान्यतः जिलेट बचाव के रूप में जाना जाता था, जो *जिलेट सेफ्टी रेजर बनाम एंग्लो-अमेरिकन ट्रेडिंग कंपनी, (1913) 30 आरपीसी 465* (हाउस ऑफ लॉर्ड्स) में दिए गए निर्णय पर आधारित था। उन्होंने प्रस्तुत किया कि पूर्वोक्त को ध्यान में रखते हुए, पेटेंट अतिलंघन के वाद में पूछताछ के दायरे को, जहाँ अवैधता के प्रति दावे लंबित हैं, अनिवार्यता/अतिलंघन की एकल बिंदु पूछताछ तक सीमित करना, अधिनियम के ढाँचे के साथ अन्याय होगा।

आ.प्र.अ. (मू.प.) (वाणि.) 297/2018 में एरिक्सन की ओर से प्रत्युत्तर तर्क

34. प्रत्युत्तर में, एरिक्सन के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि चूँकि इंटेक्स ने एरिक्सन के पेटेंट को मानक आवश्यक पेटेंट के रूप में स्वीकार किया था, इसलिए इंटेक्स द्वारा एरिक्सन से लाइसेंस लेना आवश्यक था और मानक आवश्यक पेटेंट के लाइसेंस के रूप में एरिक्सन द्वारा इंटेक्स को इसकी विधिवत पेशकश की गई थी। उन्होंने प्रस्तुत किया कि इंटेक्स की कार्रवाइयों से पता चलता है कि वह इच्छुक लाइसेंसधारी नहीं था और उसकी ओर से गैर-अनुपालन पूरी तरह से जानबूझकर किया गया था। इसके अतिरिक्त, पेटेंट प्रदान करने से पहले एरिक्सन द्वारा नियंत्रक के समक्ष बताए गए तथ्य उसके पक्ष में हैं। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि इंटेक्स का वादग्रस्त पेटेंट की अवैधता का अभिवाक् निरर्थक है, क्योंकि एरिक्सन के पेटेंट आठ वर्ष से अधिक पुराने हैं और *टेलीमेकैनिक् एंड*

कंट्रोल्स (आई) लिमिटेड बनाम श्राइडर इलेक्ट्रिक इंडस्ट्रीज, 2001 एससीसी ऑनलाइन दिल्ली 1227 पर भरोसा करते हुए उन्होंने प्रतिवाद दिया कि एरिक्सन के पक्ष में वैधता की उपधारणा थी। इसके अतिरिक्त, पेटेंट के संबंध में इंटेक्स द्वारा न तो अनुदान-पूर्व कोई विरोध किया गया और न ही अनुदान-पश्चात चरण में कोई चुनौती दी गई तथा वर्षों की लंबी वार्ता के बाद 2013 में ही इंटेक्स ने पहली बार अवैधता का अभिवाक् दिया। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि इंटेक्स ने विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष अपनी चुनौती की विश्वसनीयता को प्रदर्शित करने के लिए कोई भी भौतिक साक्ष्य/विशेषज्ञ प्रस्तुत नहीं किए, जबकि ऐसा करना उसके लिए आवश्यक था। इसके अतिरिक्त, इंटेक्स द्वारा लाइसेंस शुल्क का भुगतान न करने के कारण, इसने बाजार में अन्य निर्माताओं, जिन्होंने लाइसेंस शुल्क का भुगतान किया है, पर बढत बना ली है।

न्यायालय के तर्क

बौद्धिक संपदा विधियों पर प्रौद्योगिकी के तीव्र विकास का प्रभाव

35. न्यायालय का मानना है कि आज प्रौद्योगिकी न केवल बहुत तेजी से विकसित हो रही है, बल्कि यह आम जनता तक और यहाँ तक कि दुनिया के दूरदराज के कोनों में रहने वाले लोगों तक भी इतनी तेजी से पहुँच रही है, जिसकी पहले कभी कल्पना भी नहीं की गई थी।

36. नई प्रौद्योगिकी ने राष्ट्रीय सीमाओं को धुंधला कर दिया है तथा अंतरराष्ट्रीय व्यापार के साथ-साथ अतिलंघन को भी बढ़ावा दिया है।

37. बौद्धिक संपदा विधियों को हमेशा से ही प्रादेशिक माना गया है, लेकिन आज की दुनिया में जहाँ देशों की सीमाओं का व्यापारिक उद्देश्यों के लिए कोई महत्व नहीं रह गया है, पेटेंट अधिकारों और न्यायालयी आदेशों को लागू करना एक चुनौती बन गया है।

38. भारतीय न्यायालय जहाँ भी आवश्यक हुआ है, विदेशी निर्णयों को लागू करते रहे हैं और कई अवसरों पर किसी विषय पर न्यायशास्त्र को आकार देते समय विदेशी निर्णयों में परिभाषित सिद्धांतों पर निर्भर रहे हैं। वास्तव में, वैश्विक सैद्धांतिक अंतरनिर्भरता, अर्थात् विदेशी न्यायालयों के निर्णयों का संदर्भ देना, विधियों के मूल सिद्धांतों के सामंजस्य को सुगम बनाने का एक प्रभावी और व्यावहारिक तरीका है, विशेष तौर पर तब जब राष्ट्रीय विधियों में कोई विपरीत बात न हो।

मानकों की श्रेणियाँ और उनका महत्व

39. चूँकि मानक आवश्यक पेटेंट एक अपेक्षाकृत नई किस्म का पेटेंट है, इसलिए इसे परिभाषित करना तथा ऐसे मामलों में अतिलंघन के परीक्षण का प्रतिपादन करना तथा मानकों के महत्व को स्पष्ट करना आवश्यक है।

40. सरल शब्दों में, मानक किसी विशेष प्रौद्योगिकी के संबंध में विशेषताओं या तकनीकी विनिर्देशों की एक निर्धारित सूची है। मानक का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि मानक के अनुसार निर्मित प्रत्येक उत्पाद में कुछ सामान्य डिजाइन/विशेषताएँ हों, ताकि उपकरणों/उत्पादों की अनुकूलता और अंतर-संचालनशीलता सुनिश्चित की जा सके।

41. मानक हमारे चारों ओर हैं और विभिन्न आकार और रूपों में आते हैं - माप की मीट्रिक प्रणाली से लेकर, रेलवे पटरियों के आकार, बिजली के प्लग के आकार से लेकर आईसीटी (सूचना और संचार प्रौद्योगिकी) क्षेत्र में जटिल तकनीकी अंतर-संचालन मानकों जैसे कि वाई-फाई, ब्लूटूथ, 3जी, 4जी, 5जी संचार मानक, पीडीएफ सॉफ्टवेयर मानक आदि।

42. आधुनिक अर्थव्यवस्था में मानक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे नवाचार को बढ़ावा देते हैं, उत्पादों की गुणवत्ता और व्यवहार्यता बढ़ाते हैं, रोजगार और विकास प्रदान करते हैं तथा वैश्विक मूल्य शृंखला को समर्थन प्रदान करते हैं। मानक नवीन उत्पादों और सेवाओं को बाजार में शीघ्र अपनाने की अनुमति देते हैं, कंपनियों के लिए उत्पादों का उत्पादन कम खर्चीला बनाते हैं तथा उपभोक्ताओं के लिए अधिक मूल्यवान बनाते हैं।

43. इसके अतिरिक्त, जैसा कि ऊपर बताया गया है, मानक विभिन्न निर्माताओं की प्रौद्योगिकियों और उत्पादों के बीच अंतरसंचालनीयता या अनुकूलता को एक

मंच पर एक साथ काम करने की अनुमति देते हैं। उदाहरण के लिए, तकनीकी अंतर-संचालनशील मानक सेल फोन उपयोगकर्ताओं को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अर्थात् नई दिल्ली, न्यूयॉर्क, लंदन और केपटाउन में एक ही स्मार्टफोन का उपयोग करने के साथ-साथ विभिन्न निर्माताओं के स्मार्टफोन से कॉल करने और प्राप्त करने की अनुमति देते हैं। इसके अतिरिक्त, अंतर-संचालनशीलता से "नेटवर्क प्रभाव" बढ़ता है, जहाँ उपयोगकर्ताओं की संख्या बढ़ने पर उत्पाद अधिक मूल्यवान होते हैं। अध्ययनों से पता चलता है कि मानक पूरी अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक लाभ उत्पन्न करते हैं।

44. मोटे तौर पर मानकों की दो श्रेणियाँ हैं:

(i) स्रोत के आधार पर मानक।

(ii) बौद्धिक संपदा अधिकारों तक पहुँच या विकास प्रक्रिया में खुलेपन (खुले और बंद मानकों) के आधार पर मानक।

45. स्रोत के आधार पर विभिन्न प्रकार के मानक होते हैं। उदाहरण के लिए, मानक बाजार की शक्तियों, सरकारों या उद्योग के आधार पर निर्धारित किए जा सकते हैं।

46. बाजार की शक्तियों द्वारा निर्धारित मानक, जैसे कि किसी संस्थागत ढाँचे के बाहर एक या कई फर्मों का एक साथ काम करना, जिनके उत्पाद या समाधान

बाजार में व्यापक रूप से स्वीकार किए जाते हैं। इन्हें वास्तविक मानक कहा जाता है, उदाहरण के लिए, माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम।

47. कई बार, कंपनियाँ सहयोगात्मक या औपचारिक मानकों के माध्यम से नए तकनीकी समाधान विकसित करने के लिए उद्योग-व्यापी आधार पर एकजुट होने का निर्णय लेती हैं। अधिकांश और सबसे महत्वपूर्ण मानक सहयोगात्मक होते हैं। उदाहरणों में 3जी, 4जी, 5जी संचार मानक आदि शामिल हैं।

48. सरकारी मानक वे होते हैं जिन्हें सरकार अपनाती है, जिनका विधि द्वारा अनुपालन आवश्यक होता है। इन्हें विधि सम्मत मानक भी कहा जाता है। उदाहरणों में वाहन उत्सर्जन पर भारत स्टेज (बीएस) मानक, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 11(1)(ख)(झ) और (फ) के साथ धारा 36 के अंतर्गत जारी भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (टीआरएआई) की अधिसूचनाएँ शामिल हैं, जो दूरसंचार के संबंध में मानक जारी करती हैं। उदाहरण के लिए, 14 मई, 2012 की टीआरएआई की अधिसूचना डिजिटल केबल टीवी सिस्टम के संबंध में ईटीएसआई द्वारा निर्धारित एक विशेष मानक को विधिक बल प्रदान करती है। डिजिटल एट्रेसेबल केबल टीवी सिस्टम के संबंध में 14 मई, 2012 की राजपत्र अधिसूचना का प्रासंगिक भाग नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:-

“भारत के राजपत्र में प्रकाशित करने हेतु

असाधारण, भाग III, धारा 4

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 मई, 2012

एफ. सं. 16- 2/2012- बीएंडसीएस ---- भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) की धारा 11 की उपधारा (1) के खंड (ख) के उपखंड (i) और (v) के साथ धारा 36 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (दूरसंचार विभाग) की अधिसूचना सं. 39 के साथ पठित,.....

सेवा की गुणवत्ता के मानक
(डिजिटल एड्रसेबल केबल टीवी सिस्टम) विनियम, 2012
(2012 का 12).....

अध्याय VIII
तकनीकी मानक

18. तकनीकी मानक—(1) प्रत्येक प्रसारक को डिजिटल वीडियो प्रसारण द्वारा डीवीबी-एस या डीवीबी-एस2 मानकों के लिए निर्धारित मानकों के अनुसार सिग्नलों के तकनीकी मानकों को बनाए रखना होगा, जैसा भी मामला हो, और यह भी सुनिश्चित करना होगा कि मल्टी-सिस्टम ऑपरेटर के हेडएंड पर आपूर्ति किए गए सिग्नलों की गुणवत्ता निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करती है :-

क्रम	मापदंड	मान
1	सिग्नल से शोर अनुपात (एसएनआर)	जैसा कि डीवीबी-एस (ईटीएसआई ईएन 300421) या डीवीबी-एस2 (ईटीएसआई ईएन 302307) द्वारा निर्दिष्ट किया गया है, जैसा लागू हो
2	ऑपरेटिंग मार्जिन (शोर मार्जिन)	4 डीबी से अधिक।

(4) तकनीकी लेखा, डिजिटल वीडियो ब्रॉडकास्टिंग द्वारा यूरोपीय दूरसंचार मानक संस्थान ईटीएसआई टीआर 101 290 वी 1.2.1 (2001-05) में निर्दिष्ट माप दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाएगा और चित्र गुणवत्ता माप, अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ (आईटीयू) द्वारा अनुशंसा में दिए गए टेलीविजन चित्रों की गुणवत्ता के व्यक्तिपरक मूल्यांकन के लिए पद्धति के अनुसार किया जाएगा।

स्पष्टीकरण: इस उप-विनियमन के प्रयोजन के लिए:

(i) आईटीयू के अनुशंसा "आईटीयू-आर बीटी 500-11 टेलीविजन चित्रों की गुणवत्ता के व्यक्तिपरक मूल्यांकन के लिए कार्यप्रणाली" के अनुसार है"....."

49. अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ ('आईटीयू-टी') खुले मानक को ऐसे मानक के रूप में परिभाषित करता है जो सहयोगात्मक और सर्वसम्मति से संचालित प्रक्रिया के माध्यम से आम जनता के लिए उपलब्ध हो। खुले मानक के तत्वों में एक संतुलित प्रक्रिया शामिल होती है जिसमें बौद्धिक संपदा नीतियों वाले किसी भी हित समूह का वर्चस्व नहीं होता है, जिसमें आवश्यक बौद्धिक संपदा के प्रकटीकरण की आवश्यकता होती है और एफआरएएनडी शर्तों पर मानक को लागू करने की इच्छा रखने वाली किसी भी फर्म को लाइसेंस देने की प्रतिबद्धता होती है।

50. इसके विपरीत, बंद मानक एक या एक से अधिक कंपनियों द्वारा बंद वातावरण में विकसित किया जाता है, जहाँ मानक तक पहुँच व्यापक रूप से उपलब्ध नहीं होती है। वे यह चुनने के लिए स्वतंत्र हैं कि वे मानक को लाइसेंस देना चाहते हैं या नहीं और किन शर्तों के अंतर्गत।

51. मानक विकास संगठन ('एसडीओ') स्वैच्छिक और गैर-लाभकारी संगठन हैं जो मानकों के विकास का समन्वय करते हैं। आम भाषा में, सभी प्रकार के एसएसओ होते हैं।

52. वास्तव में एसएसओ/एसडीओ ऐसे संघ/संगठन हैं, जो सामान्यतः अंतरराष्ट्रीय स्तर के होते हैं तथा संबंधित उद्योग के विभिन्न हितधारक इनके सदस्य होते हैं। उदाहरण के लिए, दूरसंचार के क्षेत्र में, एक एसएसओ/एसडीओ में मोबाइल प्रौद्योगिकी उपयोगकर्ता, अर्थात् फोन निर्माता (जैसे एप्पल, सैमसंग, आदि), प्रौद्योगिकी डेवलपर्स (जैसे नोकिया, फिलिप्स, आदि) शामिल हो सकते हैं, तथा इसके सदस्य के रूप में विश्वविद्यालय/शैक्षणिक संस्थान, नेटवर्क ऑपरेटर, सरकारी नियामक निकाय आदि भी शामिल हो सकते हैं। एसएसओ/एसडीओ की भूमिका शोधकर्ताओं, कंपनियों, शैक्षणिक संस्थानों आदि जैसे विभिन्न हितधारकों की सक्रिय भागीदारी और संलिप्तता के साथ मानक निर्धारण/विकास प्रक्रिया का समन्वय और सुविधा प्रदान करना है।

53. कुछ प्रसिद्ध एसडीओ में ईटीएसआई (यूरोप); एटीआईएस (यूएसए); टीटीए (कोरिया); टीटीसी (जापान); टीएसडीएसआई (भारत); आईईईई (इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स); आईएसओ (अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन); आईटीयू-टी और आईईसी (अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन) आदि शामिल हैं।

54. दुनिया में सबसे व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त एसएसओ/एसडीओ में से एक ईटीएसआई है। यह अपनी आईपीआर नीति के अनुच्छेद 15(6) में "आवश्यक" को इस प्रकार परिभाषित करता है:

"6. आईपीआर पर लागू "आवश्यक" का अर्थ है कि तकनीकी (लेकिन वाणिज्यिक नहीं) आधार पर, सामान्य तकनीकी अभ्यास और मानकीकरण के समय आम तौर पर उपलब्ध अत्याधुनिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए, उस आईपीआर का अतिलंघन किए बिना मानक के अनुरूप उपकरण या विधियों को बनाना, विक्रय, पट्टे पर देना, अन्यथा निपटाना, मरम्मत करना, उपयोग करना या संचालित करना संभव नहीं है। असाधारण मामलों में संदेह से बचने के लिए, जहाँ किसी मानक को केवल तकनीकी समाधानों द्वारा ही क्रियान्वित किया जा सकता है, जो सभी आईपीआर का अतिलंघन हैं, ऐसे सभी आईपीआर को आवश्यक माना जाएगा।"

(जोर दिया गया)

55. 'मानक' शब्द को ईटीएसआई बौद्धिक संपदा अधिकार नीति के अनुच्छेद 15(11) में निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:

"11. "मानक" का अर्थ ईटीएसआई द्वारा अपनाए गए किसी भी मानक से होगा, जिसमें उसके विकल्प या संशोधित संस्करण शामिल हैं और इसमें यूरोपीय मानक (ईएन), ईटीएसआई मानक (ईएस), सामान्य तकनीकी विनियम (सीटीआर) शामिल होंगे, जो ईएन से लिए गए हैं और जिनमें पूर्वोक्त में से किसी का प्रारूप शामिल है, और पिछले नामकरण के अंतर्गत बनाए गए दस्तावेज, जिनमें ईटीएस, आई-ईटीएस, एनईटी और टीबीआर के हिस्से शामिल हैं, जिनकी तकनीकी विशिष्टताएँ सभी सदस्यों के लिए उपलब्ध हैं, लेकिन इसमें ईटीएसआई द्वारा नहीं बनाए गए कोई भी मानक या उसके हिस्से शामिल नहीं हैं।"

जिस तिथि को इस नीति के प्रयोजनों के लिए **ES** द्वारा किसी मानक को अपनाया गया माना जाएगा, वह वह तिथि होगी जिस दिन उस मानक की तकनीकी सामग्री सभी सदस्यों के लिए उपलब्ध थी।”

56. किसी भी उत्पाद में, जो किसी मानक के अंतर्गत निर्धारित प्रौद्योगिकी के अनुरूप होने का दावा करता है, आवश्यक रूप से उसके सभी तत्वों को शामिल किया जाएगा, जिसमें मानक का पेटेंट प्राप्त भाग भी शामिल होगा। तदनुसार, किसी व्यक्तिगत पेटेंट स्वामी द्वारा मानकों को बंधक बनाए जाने से संबंधित चिंताओं को एआरएनडी प्रतिबद्धता की अवधारणा को विकसित करके संबोधित किया गया, जो कि पेटेंटधारक द्वारा स्वैच्छिक घोषणा के माध्यम से की जाती है। इस प्रकार, मानक आवश्यक पेटेंट स्वामी की संविदात्मक प्रतिबद्धता, संबंधित मानक के विकास के समय एसएसओ/एसडीओ को की गई स्वैच्छिक घोषणाओं (जिन्हें एफआरएनडी घोषणाएँ कहा जाता है) से उत्पन्न होती है। उदाहरण के तौर पर, ईटीएसआई और आईएसओ/आईईसी की बौद्धिक संपदा अधिकार नीतियों को नीचे उद्धृत किया गया है:

आईपीआर नीति का खंड 6.1

“6.1 जब किसी विशेष मानक या तकनीकी विनिर्देश से संबंधित एक आवश्यक आईपीआर ईटीएसआई के ध्यान में लाया जाता है, तो ईटीएसआई के महानिदेशक तुरंत स्वामी से तीन महीने के भीतर लिखित रूप में एक अपरिवर्तनीय परिवचन देने का अनुरोध करेंगे कि वह कम से कम निम्नलिखित सीमा तक ऐसे आईपीआर के अंतर्गत निष्पक्ष, उचित और गैर-भेदभावपूर्ण (“एफआरएनडी”) नियमों और शर्तों पर अपरिवर्तनीय लाइसेंस देने के लिए तैयार है:

- विनिर्माण, जिसमें विनिर्माण में उपयोग के लिए लाइसेंसधारी के स्वयं के डिजाइन के अनुसार अनुकूलित घटकों और उप-प्रणालियों को बनाने या बनवाने का अधिकार शामिल है;
 - इस प्रकार निर्मित उपकरणों का विक्रय करना, पट्टे पर देना या अन्यथा निपटान करना;
 - उपकरण की मरम्मत, उपयोग या संचालन; और
 - उपयोग की विधियाँ
- उपर्युक्त परिवचन इस शर्त के अधीन दिया जा सकता है कि लाइसेंस चाहने वाले लोग पारस्परिक रूप से ऐसा करने के लिए सहमत होंगे।"

आईएसओ/आईईसी की आईपीआर नीति के अंतर्गत की जाने वाली घोषणा

"2.2 पेटेंटधारी अन्य पक्षकारगण के साथ गैर-भेदभावपूर्ण आधार पर उचित नियमों और शर्तों पर लाइसेंस के लिए बातचीत करने को तैयार है। इस तरह की वार्ता संबंधित पक्षकारगण पर छोड़ दी जाती है और आईटीयू-टी/आईटीयूआर/आईएसओ/आईईसी के बाहर की जाती है।

57. यदि कोई पेटेंटधारी ऐसी स्वैच्छिक घोषणाएँ देने से इनकार करता है, तो एसएसओ/एसडीओ ऐसी प्रौद्योगिकी को मानक से बाहर करने के लिए सचेत कदम उठाते हैं।

58. उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि मानक आवश्यक पेटेंट स्वामी द्वारा की गई स्वैच्छिक घोषणाएँ संविदात्मक प्रतिबद्धताएँ हैं और संबंधित एसएसओ/एसडीओ की बौद्धिक संपदा अधिकार नीति के अनुसार शासित और व्याख्या की जाती हैं। उदाहरण के लिए, ईटीएसआई और आईएसओ/आईईसी के नीतिगत उद्देश्य निम्नानुसार हैं:

"ईटीएसआई का नीतिगत उद्देश्य निम्नानुसार प्रावधान करता है:

"3. नीतिगत उद्देश्य

3.1 ईटीएसआई का उद्देश्य ऐसे मानक और तकनीकी विनिर्देश तैयार करना है जो ऐसे समाधानों पर आधारित हों जो यूरोपीय दूरसंचार क्षेत्र के तकनीकी उद्देश्यों को सर्वोत्तम रूप से पूरा करते हों, जैसा कि महासभा द्वारा परिभाषित किया गया है। इस उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए ईटीएसआई आईपीआर नीति ईटीएसआई, सदस्यों और ईटीएस मानकों और तकनीकी विशिष्टताओं को लागू करने वाले अन्य लोगों के लिए जोखिम को कम करने का प्रयास करती है, कि मानकों की तैयारी, अपनाने और आवेदन में निवेश, मानक या तकनीकी विशिष्टताओं के लिए आवश्यक आईपीआर उपलब्ध न होने के परिणामस्वरूप बर्बाद हो सकता है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने में, ईटीएसआई आईपीआर नीति दूरसंचार के क्षेत्र में सार्वजनिक उपयोग के लिए मानकीकरण की आवश्यकताओं और आईपीआर के स्वामियों के अधिकारों के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास करती है।

3.2 आईपीआर धारकों को, चाहे वे ईटीएसआई के सदस्य हों या उनके सहयोगी या तीसरे पक्ष, मानकों और तकनीकी विशिष्टताओं के कार्यान्वयन में उनके आईपीआर के उपयोग के लिए पर्याप्त और उचित रूप से पुरस्कृत किया जाना चाहिए।

ईटीएसआई, जहाँ तक संभव हो, यह सुनिश्चित करने के लिए उचित उपाय करेगा कि इसकी गतिविधियाँ, जो मानकों और तकनीकी विनिर्देशों की तैयारी, अपनाने और आवेदन से संबंधित हैं, मानकीकरण के सामान्य सिद्धांतों के अनुसार संभावित उपयोगकर्ताओं के लिए मानकों और तकनीकी विनिर्देशों को उपलब्ध कराने में सक्षम हों।

"ईटीएसओ/आईईसी के नीतिगत उद्देश्य निम्नानुसार हैं:

"अनुशंसा/प्रदेय गैर-बाध्यकारी हैं; उनका उद्देश्य विश्वव्यापी आधार पर प्रौद्योगिकियों और प्रणालियों की अनुकूलता सुनिश्चित करना है। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए, जो कि भाग लेने वाले सभी लोगों के सामान्य हितों में है, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुशंसा/प्रदेय, उनके अनुप्रयोग, उपयोग आदि सभी के लिए सुलभ हों।

इसलिए, इसका अर्थ यह है कि किसी अनुशंसा/प्रदेय में पूर्णतः या आंशिक रूप से शामिल पेटेंट बिना किसी अनावश्यक बाधा के सभी के लिए सुलभ होना चाहिए। इस आवश्यकता को सामान्य रूप से पूरा करना ही आचार संहिता का एकमात्र

उद्देश्य है। पेटेंट (लाइसेंस देना, स्वामिस्व, आदि) से उत्पन्न होने वाली विस्तृत व्यवस्थाएँ संबंधित पक्षों पर छोड़ दी जाती हैं, क्योंकि ये व्यवस्थाएँ मामले दर मामले अलग-अलग हो सकती हैं।

इस आचार संहिता का सारांश इस प्रकार दिया जा सकता है:

1. आईटीयू दूरसंचार मानकीकरण ब्यूरो (टीएसबी), आईटीयू रेडियो संचार ब्यूरो (बीआर) और आईएसओ और आईईसी के सीईओ के कार्यालय पेटेंट या इसी तरह के अधिकारों के साक्ष्य, वैधता या दायरे के बारे में आधिकारिक या व्यापक जानकारी देने की स्थिति में नहीं हैं, लेकिन यह वांछनीय है कि पूरी उपलब्ध जानकारी का प्रकटीकरण किया जाना चाहिए। इसलिए, आईटीयू, आईएसओ या आईईसी के कार्य में भाग लेने वाले किसी भी पक्ष को शुरू से ही आईटीयू-टीएसबी के निदेशक का ध्यान आकर्षित करना चाहिए। आईटीयू-बीआर के निदेशक, या आईएसओ या आईईसी के सीईओ के कार्यालय, किसी भी ज्ञात पेटेंट या किसी भी ज्ञात लंबित पेटेंट आवेदन के संबंध में कोई भी सूचना प्रदान नहीं करेंगे, चाहे वह उनकी अपनी हो या अन्य संगठनों की, हालाँकि आईटीयू, आईएसओ या आईईसी ऐसी किसी भी सूचना की वैधता को सत्यापित करने में असमर्थ हैं।

2. यदि कोई अनुशंसा/प्रदेय विकसित किया गया है और पैराग्राफ 1 में संदर्भित सूचना का प्रकटीकरण किया गया है, तो तीन अलग-अलग स्थितियाँ उत्पन्न हो सकती हैं:

2.1 पेटेंटधारी अन्य पक्षकारगण के साथ बिना किसी भेदभाव के उचित नियमों और शर्तों पर निःशुल्क लाइसेंस के लिए वार्ता करने को तैयार है। ऐसी वार्ता संबंधित पक्षकारगण पर छोड़ दी जाती है और आईटीयूटी/आईटीयू-आर/आईएसओ/आईईसी के बाहर की जाती है।

2.2 पेटेंटधारी अन्य पक्षकारगण के साथ बिना किसी भेदभाव के उचित नियमों और शर्तों पर लाइसेंस के लिए वार्ता करने को तैयार है। ऐसी वार्ता संबंधित पक्षकारगण पर छोड़ दी जाती है और आईटीयू-टी/आईटीयू-आर/आईएसओ/आईईसी के बाहर की जाती है।

2.3 पेटेंटधारी पैराग्राफ 2.1 या पैराग्राफ 2.2 के प्रावधानों का अनुपालन करने के लिए इच्छुक नहीं है; ऐसे मामले में, अनुशंसा/प्रदाय में पेटेंट पर निर्भर उपबंध शामिल नहीं होंगे।

3. जो भी मामला लागू हो (2.1, 2.2 या 2.3), पेटेंटधारी को उपयुक्त "पेटेंट विवरण और लाइसेंस संबंधी घोषणा" प्रपत्र का उपयोग करके क्रमशः आईटीयू-टीएसबी, आईटीयू-बीआर या आईएसओ या आईईसी के सीईओ के कार्यालयों में दायर करने के लिए एक लिखित विवरण प्रदान करना होगा। इस विवरण में प्रपत्र के संबंधित बक्से में प्रत्येक मामले के लिए दिए गए प्रावधान से अधिक अतिरिक्त उपबंध, शर्तें या कोई अन्य बहिष्करण खंड शामिल नहीं होना चाहिए।"

59. तदनुसार, एसएसओ का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पेटेंटधारी को उसके योगदान/नवाचार के लिए एफआरएएनडी दरों पर पर्याप्त रूप से पुरस्कृत किया जाए, साथ ही यह सुनिश्चित किया जाए कि नवीनतम अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी दुनिया भर के कार्यान्वयनकर्ताओं को उपलब्ध हो, भले ही ऐसे कार्यान्वयनकर्ता अनुसंधान और विकास में शामिल न हों।

मानक आवश्यक पेटेंट क्या है और ऐसे पेटेंट धारकों के दायित्व क्या हैं

60. उपरोक्त तथ्यों के साथ-साथ इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि टीआरएआई ने दूरसंचार कंपनियों को ईटीएसआई मानकों का अनुपालन करने का निर्देश दिया है, यह न्यायालय इस बात पर विचार करता है कि वर्तमान मामले के तथ्यों में 'आवश्यक' शब्द का अर्थ है कि एक पेटेंट एक मानक के लिए आवश्यक है, अर्थात् पेटेंट का अतिलंघन किए बिना मानक का अनुपालन करना तकनीकी आधार पर संभव नहीं है। इस न्यायालय का मत है कि यह सरल परिभाषा वर्तमान जैसी कई परिस्थितियों में पर्याप्त है, किन्तु सभी में नहीं। परिणामस्वरूप,

एक मानक आवश्यक पेटेंट "एक पेटेंट दावा करने वाली तकनीक है जो उद्योग मानक के उपयोग के लिए आवश्यक है।"

61. मानक आवश्यक पेटेंटों को गैर-मानक आवश्यक पेटेंटों से अलग माना जाता है - कम से कम एक मामले में, अर्थात्, मानक आवश्यक पेटेंट के मामले में पेटेंटधारी के अधिकार, एसएसओ/एसडीओ के साथ किए गए अनुबंधात्मक प्रतिबद्धता द्वारा सीमित होते हैं, जिसके अंतर्गत पेटेंट की अवधि के दौरान उन सभी इच्छुक लाइसेंसधारकों को पेटेंट उपलब्ध कराया जाता है। परिणामस्वरूप, एसडीओ की बौद्धिक संपदा अधिकार नीतियाँ आमतौर पर मानक आवश्यक पेटेंट धारकों पर कम से कम निम्नलिखित दायित्व अधिरोपित करती हैं:

- (i) प्रासंगिक पेटेंटों को मानक आवश्यक पेटेंट के रूप में प्रकट करने का कर्तव्य।
- (ii) मानक आवश्यक पेटेंट को उन सभी लोगों के लिए उपलब्ध कराने का कर्तव्य, जो इसका उपयोग करने के इच्छुक हैं, तथा उन तक पहुँच को रोकना नहीं चाहिए।
- (iii) सभी इच्छुक लाइसेंसधारियों को एफआरएएनडी शर्तों पर लाइसेंस प्रदान करने का कर्तव्य।

62. इसलिए, एक मानक आवश्यक पेटेंट धारक, पेटेंट की अवधि के दौरान नुकसान में रहता है, क्योंकि वह निम्न से वंचित रहता है:

- क. यह तय करने की स्वतंत्रता कि किसे लाइसेंस देना है।
- ख. लाइसेंस की शर्तों को तय करने की स्वतंत्रता, क्योंकि यह एफआरएएनडी शर्तों पर आधारित होगी।

ग. किसी अतिलंघनकर्ता के विरुद्ध बिना किसी पूर्व वार्ता के व्यादेश का दावा करने की स्वतंत्रता।

एफआरएनडी मानक आवश्यक पेटेंट धारकों और कार्यान्वयनकर्ताओं दोनों पर दायित्व अधिरोपित करता है

63. विधिक विशेषज्ञों का मानना है कि एफआरएनडी शर्तों पर मानक आवश्यक पेटेंट की लाइसेंस प्रक्रिया से संबंधित बौद्धिक संपदा अधिकार नीतियों को पूरी तरह सफल बनाने के लिए, दो विशेष संभावित बुराइयाँ हैं, जिनसे बचना आवश्यक है। हालाँकि शब्दावली पूरी तरह से सुसंगत नहीं है, लेकिन इन बुराइयों को आम तौर पर "रोक" और "प्रतिरोध" के रूप में जाना जाता है।

64. सरल शब्दों में, "रोक" तब होती है जब पेटेंटधारी यह सुनिश्चित करने में सक्षम होता है कि मानक आवश्यक पेटेंट को मानक में शामिल किया गया है और कार्यान्वयनकर्ताओं द्वारा ऐसी परिस्थितियों में कार्यान्वित किया गया है जो पेटेंटधारी को लाइसेंस शर्तों को निकालने के लिए अतिलंघन को रोकने के लिए व्यादेश के खतरे का उपयोग करने में सक्षम बनाता है, और विशेष रूप से स्वामिस्व दरें, जो पेटेंट किए गए आविष्कार के लाइसेंस के उचित बाजार मूल्य से अधिक होती हैं (अर्थात् मानक आवश्यक पेटेंट को भूमि की "फिरौती पट्टी" के समान माना जाता है)।

65. "प्रतिरोध करना" तब होता है जब कोई कार्यान्वयनकर्ता किसी लाइसेंस (या शायद किसी भी चीज़) के लिए उचित बाजार मूल्य का भुगतान किए बिना मानक आवश्यक पेटेंट द्वारा शामिल किए गए तकनीकी समाधान को लागू करने में सक्षम होता है। इस बात की विवेचना की जानी चाहिए कि एफआरएएनडी परिवचन कार्यान्वयनकर्ता को अतिलंघन के दावे के लिए बचाव प्रदान करके और इस प्रकार व्यादेश प्राप्त करके 'रोक' को रोकने के लिए तैयार किया गया है, जबकि पेटेंटधारी की बिना लाइसेंस वाले मानक आवश्यक पेटेंट के अतिलंघन को रोकने के लिए व्यादेश प्राप्त करने की क्षमता 'प्रतिरोध' को रोकती है। (देखें: *ऑप्टिस सेलुलर टेक्नोलॉजी एलएलसी और अन्य बनाम एप्पल रिटेल यूके लिमिटेड और अन्य; (2022) ईडब्ल्यूसीए सीआईवी 1411*)

66. *हुआवेई बनाम जेडटीई* (पूर्वोक्त) का मौलिक निर्णय एफआरएएनडी प्रोटोकॉल को स्पष्ट करता है। उक्त निर्णय का प्रासंगिक अंश नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:-

"60. तदनुसार, किसी एसईपी का स्वामी, जो यह समझता है कि एसईपी अतिलंघन का विषय है, अनुच्छेद 102 टीएफईयू का अतिलंघन किए बिना, कथित अतिलंघनकर्ता के विरुद्ध बिना नोटिस दिए या कथित अतिलंघनकर्ता से पूर्व परामर्श किए, निषेधात्मक व्यादेश या उत्पादों को वापस लेने के लिए कार्रवाई नहीं कर सकता है, भले ही एसईपी का उपयोग कथित अतिलंघनकर्ता द्वारा पहले ही किया जा चुका हो।

61. इस प्रकार की कार्यवाही से पहले, संबंधित एसईपी के स्वामी को सर्वप्रथम कथित अतिलंघनकर्ता को शिकायत किए गए अतिलंघन के बारे

में सचेत करना चाहिए, इसके लिए एसईपी को नामित करना चाहिए तथा यह निर्दिष्ट करना चाहिए कि अतिलंघन किस प्रकार किया गया है।

62. जैसा कि महाधिवक्ता ने अपनी राय के बिंदु 81 में कहा है, मुख्य कार्यवाही में जिस मानक पर विचार किया जा रहा है, उसे बनाने वाले एसईपी की बड़ी संख्या को देखते हुए, यह निश्चित नहीं है कि उन एसईपी में से किसी एक का उल्लंघन करने वाले को आवश्यक रूप से पता होगा कि वह एक ऐसे एसईपी के शिक्षण का उपयोग कर रहा है जो एक मानक के लिए वैध और आवश्यक दोनों हैं।

63. दूसरे, जब कथित अतिलंघनकर्ता ने एफआरएएनडी शर्तों पर लाइसेंस संबंधी अनुबंध करने की अपनी इच्छा व्यक्त कर दी है, तो यह एसईपी के स्वामी का काम है कि वह कथित अतिलंघनकर्ता को एफआरएएनडी शर्तों पर लाइसेंस के लिए एक विशिष्ट, लिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करे, जो मानकीकरण निकाय को दिए गए परिवचन के अनुसार हो, जिसमें विशेष रूप से स्वामिस्व की राशि और स्वामिस्व की गणना करने का तरीका निर्दिष्ट किया गया हो।

64. जैसा कि महाधिवक्ता ने अपनी राय के बिंदु 86 में कहा है, जहाँ एसईपी के स्वामी ने मानकीकरण निकाय को एफआरएएनडी शर्तों पर लाइसेंस देने का परिवचन दिया है, वहाँ यह उम्मीद की जा सकती है कि वह ऐसा प्रस्ताव देगा। इसके अतिरिक्त, सार्वजनिक मानक लाइसेंस संबंधी अनुबंध के अभाव में, और जहाँ अन्य प्रतिस्पर्धियों के साथ पहले से ही किए गए लाइसेंस संबंधी अनुबंधों को सार्वजनिक नहीं किया गया है, वहाँ एसईपी के स्वामी के लिए कथित अतिलंघनकर्ता की तुलना में यह जाँचना बेहतर है कि उसका प्रस्ताव गैर-भेदभाव की शर्त का अनुपालन करता है या नहीं।

65. इसके विपरीत, यह कथित अतिलंघनकर्ता पर निर्भर है कि वह उस प्रस्ताव का क्षेत्र में मान्यता प्राप्त वाणिज्यिक प्रथाओं के अनुसार तथा

सद्भावनापूर्वक तत्परता से जवाब दे, यह एक ऐसा बिन्दु है जिसे वस्तुनिष्ठ कारकों के आधार पर स्थापित किया जाना चाहिए तथा जिसका विशेष रूप से तात्पर्य यह है कि इसमें विलंब करने की कोई रणनीति नहीं है।

66. यदि कथित अतिलंघनकर्ता उसके समक्ष प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करता है, तो वह निषेधात्मक व्यादेश या उत्पादों को वापस मँगाने के लिए कार्रवाई की अपमानजनक प्रकृति पर तभी निर्भर हो सकता है, जब उसने संबंधित एसईपी के स्वामी को तत्काल और लिखित रूप में एक विशिष्ट प्रति-प्रस्ताव प्रस्तुत किया हो, जो एफआरएएनडी शर्तों के अनुरूप हो।

67. इसके अतिरिक्त, जहाँ कथित अतिलंघनकर्ता लाइसेंस संबंधी अनुबंध के संपन्न होने से पहले एसईपी की शिक्षाओं का उपयोग कर रहा है, तो उस कथित अतिलंघनकर्ता को, जिस समय से उसका प्रति-प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ है, उस समय से, क्षेत्र में मान्यता प्राप्त वाणिज्यिक प्रथाओं के अनुसार, उचित सुरक्षा प्रदान करना आवश्यक है, उदाहरण के लिए बैंक गारंटी प्रदान करके या आवश्यक राशि जमा करके। उस सुरक्षा की गणना में, अन्य बातों के साथ-साथ, एसईपी के उपयोग के पिछले कृत्यों की संख्या शामिल होनी चाहिए, और कथित अतिलंघनकर्ता को उन उपयोग के कृत्यों के संबंध में एक लेखा-जोखा प्रस्तुत करने में सक्षम होना चाहिए।

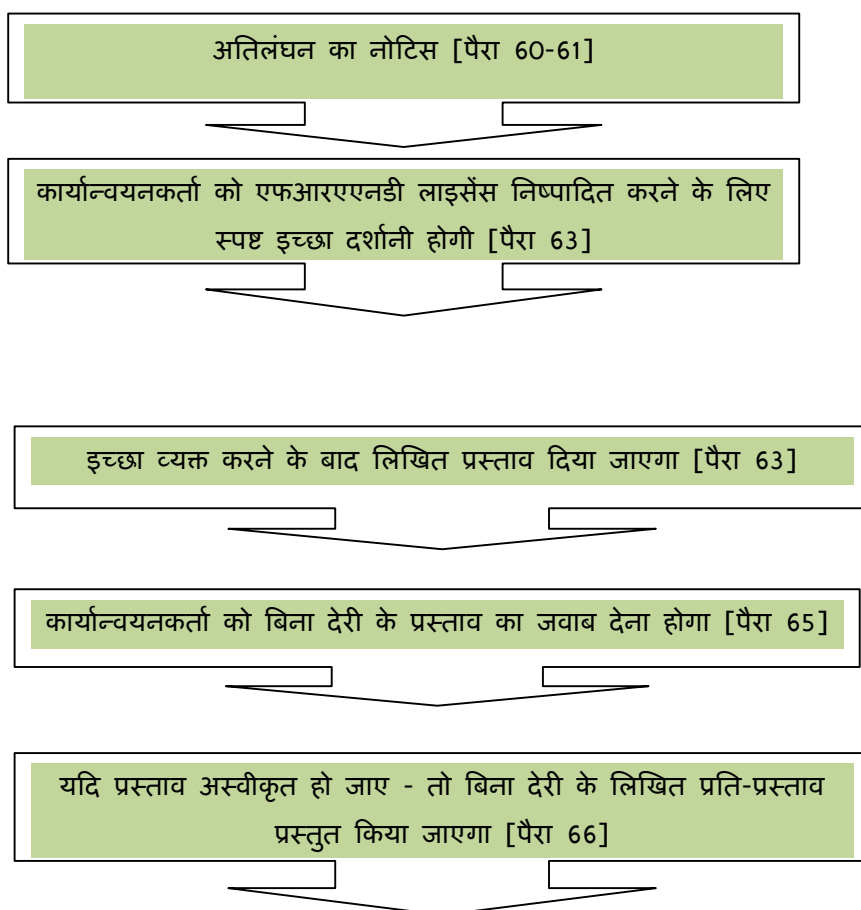
68. इसके अतिरिक्त, जहाँ कथित अतिलंघनकर्ता द्वारा प्रति-प्रस्ताव के बाद एफआरएएनडी शर्तों के विवरण पर कोई अनुबंध नहीं हो पाता है, वहाँ पक्षकारगण आम सहमति से अनुरोध कर सकते हैं कि स्वामिस्व की राशि बिना किसी देरी के निर्णय द्वारा एक स्वतंत्र तीसरे पक्ष द्वारा निर्धारित की जाए।

69. अंत में, सबसे पहले, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि एक मानकीकरण निकाय जैसे कि जिसने मुख्य कार्यवाही में विचाराधीन मानक विकसित किया है, वह यह जाँच नहीं करता है कि पेटेंट वैध हैं या उस

मानक के लिए आवश्यक हैं जिसमें उन्हें मानकीकरण प्रक्रिया के दौरान शामिल किया गया है, और, दूसरे, चार्टर के अनुच्छेद 47 द्वारा गारंटीकृत प्रभावी न्यायिक संरक्षण के अधिकार के लिए, एक कथित अतिलंघनकर्ता की आलोचना या तो लाइसेंस प्रदान करने से संबंधित वार्ता के समानांतर, उन पेटेंट की वैधता और/या उन पेटेंट की आवश्यक प्रकृति को चुनौती देने के लिए नहीं की जा सकती है जिसमें वे शामिल हैं और/या उनका वास्तविक उपयोग, या भविष्य में ऐसा करने का अधिकार सुरक्षित रखने के लिए।”

(जोर दिया गया)

67. एफआरएएनडी प्रोटोकॉल के अंतर्गत पेटेंट धारकों और कार्यान्वयनकर्ताओं द्वारा अपनाई जाने वाली चरणबद्ध प्रक्रिया, जैसा कि **हुआवेई बनाम जेडटीई** (पूर्वोक्त) निर्णय में व्याख्या की गई है, को निम्नलिखित प्रवाह चित्र में भी समझाया जा सकता है:-



जब एसईपी स्वामी प्रति-प्रस्ताव को अस्वीकार कर देता है - कार्यान्वयनकर्ता सुरक्षा प्रदान करने के लिए बाध्य है [पैरा 67]

68. तदनुसार, मानक आवश्यक पेटेंट व्यवस्था में इच्छुक लाइसेंसदाता (पेटेंटधारी) और इच्छुक लाइसेंसधारक (कार्यान्वयनकर्ता) के बीच स्पष्ट और पारदर्शी वार्ता की परिकल्पना की गई है।

69. किसी लाइसेंसदाता को इच्छुक लाइसेंसदाता तभी माना जाएगा जब वह एफआरएएनडी प्रस्ताव दे और कुछ स्थितियों में, गोपनीयता अनुबंध के अधीन, लाइसेंसधारी को प्रस्ताव का मूल्यांकन करने के लिए आवश्यक जानकारी प्रदान करे (एफआरएएनडी के 'एनडी' भाग से संबंधित)। यदि लाइसेंसदाता पूर्वोक्त-एफआरएएनडी प्रस्ताव अर्थात् अत्यधिक स्वामिस्व दरें प्रदान करता है, तो उसे इच्छुक लाइसेंसदाता नहीं माना जाएगा।

70. इसी तरह, इस स्तर पर कार्यान्वयनकर्ता को चुप रहने या निष्क्रिय रहने का कोई अधिकार नहीं है। यह सुझाव देना सही नहीं है कि पेटेंटधारी द्वारा निष्पादित अन्य अनुबंधों तक पहुँच के बिना कोई प्रति-प्रस्ताव नहीं दिया जा सकता है। आम तौर पर, कार्यान्वयनकर्ता अन्य मानक आवश्यक पेटेंट स्वामियों/लाइसेंसदाताओं के साथ निष्पादित अपने स्वयं के लाइसेंस अनुबंधों का सहारा ले सकता है, ताकि वह उचित एफआरएएनडी दर निर्धारित कर सके जिसे वह भुगतान करने के लिए तैयार

होगा या यह निर्धारित कर सके कि मानक आवश्यक पेटेंट स्वामी द्वारा प्रस्तावित दर एफआरएनडी है या नहीं। यह कोनिंक्लिजके फिलिप्स एन.वी. बनाम विको एसएस [मामला संख्या 200.219.487/01 दिनांक 02.07.2019 को निर्णीत] में डच कोर्ट ऑफ अपील के निर्णय से स्पष्ट है, जिसमें इसे निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया है:-

"4.37. विको ने बताया कि उसके पास लाइसेंस अनुबंध नहीं हैं जो फिलिप्स ने उसी पेटेंट पोर्टफोलियो के लिए अन्य पक्षकारगण के साथ किए थे, इसलिए विको यह दर्शाने में असमर्थ है कि फिलिप्स का प्रस्ताव एफआरएनडी नहीं है। इस तथ्य के अतिरिक्त कि उपरोक्त निष्कर्षों के अनुसार, विको अपने तर्कों को पुष्ट करने और अपने तर्कों के साक्ष्य प्रस्तुत करने में कई बिंदुओं पर विफल रहा और इस आधार पर उसका बचाव पहले ही विफल हो जाना चाहिए था, यह दृष्टिकोण सही नहीं है, विको ने क्वालकॉम, हुआवेई और नोकिया के साथ यूएमटीएस और एलटीई पोर्टफोलियो के लिए लाइसेंस अनुबंध किए। उन पक्षकारगण द्वारा धारित एसईपी (के मूल्य) के संबंध में उन पक्षकारगण के साथ सहमत हुए शुल्क और शर्तों के बारे में जानकारी प्रदान करके, विको इस कथित तथ्य (संदेह) को प्रमाणित कर सकता था कि फिलिप्स का प्रस्ताव एफआरएनडी नहीं था और यह कथित तथ्य कि उसका अपना प्रति-प्रस्ताव एफआरएनडी था; हालाँकि, विको ऐसा करने में विफल रहा। इन परिस्थितियों में, कोर्ट ऑफ अपील को सबूत के बोझ को उलटने या फिलिप्स के लिए तथ्यों और परिस्थितियों का तर्क देने के लिए बड़े हुए कर्तव्य को ग्रहण करने का कोई कारण नहीं दिखता है, जैसा कि विको ने तर्क दिया है।

(जोर दिया गया)

71. उपरोक्त निर्णय की पुष्टि डच सुप्रीम कोर्ट ने की है और इसे अंतिम रूप दिया गया है। इस प्रकार, यह सच नहीं है कि कार्यान्वयनकर्ता, जो अक्सर एक बड़ी वाणिज्यिक इकाई होती है जिसकी वैश्विक व्यावसायिक उपस्थिति होती है, पेटेंटधारी के साथ किसी भी तरह की वार्ता 'आँख बंद करके' करता है।

72. इसके अतिरिक्त, कार्यान्वयनकर्ता को अपनी प्रामाणिकता साबित करने के लिए लाइसेंसदाता के प्रस्ताव को स्वीकार करना होगा या उसके अनुसार उचित सुरक्षा के साथ प्रति प्रस्ताव देना होगा, क्योंकि इस अंतराल में वह ऐसे मानक आवश्यक पेटेंट का उपयोग करके अपने उपकरणों का स्वतंत्र रूप से विक्रय नहीं सकता है। यदि अंतराल के दौरान कोई तदर्थ स्वामिस्व का भुगतान नहीं किया जाता है, तो ऐसे पक्ष को अन्य इच्छुक लाइसेंसधारियों के नुकसान के लिए लाभ होता है, और बाजार में अनुचित प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त मिलती है।

73. तदनुसार, एफआरएएनडी दायित्वों की व्याख्या न केवल मानक आवश्यक पेटेंट धारकों पर बल्कि कार्यान्वयनकर्ताओं पर भी बोझ डालने के रूप में की गई है। मानक आवश्यक पेटेंट व्यवस्था में आवश्यक पेटेंट धारक और कार्यान्वयनकर्ता दोनों पर पारस्परिक दायित्व शामिल हैं। यह कोई 'एकतरफा रास्ता' नहीं है, जहाँ दायित्व केवल आवश्यक पेटेंट धारक पर ही डाला जाता है। परिणामस्वरूप, मानक आवश्यक पेटेंट व्यवस्था पेटेंटधारी और कार्यान्वयनकर्ता के बीच समानता को संतुलित करती है तथा समान अवसर सुनिश्चित करती है। न्यायालय का यह भी मानना है कि वार्ता के दौरान पक्षकारगण का आचरण एक महत्वपूर्ण कारक है जिसे यह आकलन करते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए कि संभावित लाइसेंसदाता और लाइसेंसधारी इच्छुक लाइसेंसदाता या इच्छुक लाइसेंसधारी थे। उक्त निष्कर्ष आम तौर पर तथ्य संवेदी होता है।

मानक आवश्यक पेटेंट की अवधारणा भारतीय विधि के लिए अज्ञात नहीं है

74. हालाँकि, पेटेंट अधिनियम, 1970 में मानक आवश्यक पेटेंट की बात नहीं की गई है, लेकिन इस न्यायालय के निर्णयों ने लंबे समय से इस अवधारणा को मान्यता दी है, और अतिलंघन, सुरक्षा और क्षति आदि के दावों पर न्यायनिर्णयन दिया है। [देखें: *टेलीफोनेक्टिबलगेट एलएम एरिक्सन (पब्लिक) बनाम लावा इंटरनेशनल लिमिटेड, सि.वा. (मू.प.) 764/2015; कोनिकलिजके फिलिप्स एन.वी. बनाम भागीरथी इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य, सि.वा. (वाणि) 436/2017, दिनांक 12 जुलाई 2018*]

75. दिल्ली उच्च न्यायालय के पेटेंट वादों को नियंत्रित करने वाले नियम 2022 ने मानक आवश्यक पेटेंट और उनके निर्णय में शामिल विभिन्न विधिक परीक्षणों को औपचारिक रूप से मान्यता दी है। मानक आवश्यक पेटेंट के लिए विशिष्ट कुछ नियम नीचे पुनः प्रस्तुत किए गए हैं:-

"

" 2. परिभाषाएँ...

इ. 'अतिलंघन संक्षिप्त' - '.... मानक आवश्यक पेटेंट (एसईपी) के मामले में, अतिलंघन विवरण में दावा चार्ट शामिल होंगे, जो पेटेंट दावों को मानकों के साथ उल्लिखित करेंगे, तथा जिस तरीके से प्रतिवादी उनका अतिलंघन करता है, उसका विवरण देंगे'

च. 'गैर-अतिलंघन संक्षिप्त' - '...एसईपी के मामले में भी, प्रतिवादी को यह प्रकट करना होगा कि उसके उत्पाद मानक या

उसके द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे वैकल्पिक प्रौद्योगिकी/पेटेंट का अनुपालन करते हैं या नहीं। उक्त पक्षकार, यदि चाहे तो, गैर-अतिलंघन के अभिवाक् का समर्थन करने के लिए अपना दावा निर्माण संक्षिप्त विवरण या दावा मानचित्रण प्रस्तुत करने के लिए भी स्वतंत्र है।

3. अभिवाकों की सामग्री

क. वादपत्र - अतिलंघन मामले में शिकायत में, यथासंभव, निम्नलिखित पहलू शामिल होंगे:

(IX) "सटीक दावे बनाम उत्पाद (या प्रक्रिया) चार्ट मानचित्रण, या एसईपी के मामले में, मानकों के माध्यम से दावा चार्ट मानचित्रण"

ख. लिखित बयान- अतिलंघन कार्रवाई में लिखित बयान में, यथासंभव, निम्नलिखित पहलुओं को शामिल किया जाएगा:....

(V) यदि प्रतिवादी गैर-अतिलंघन का मामला उठाता है, तो प्रतिवादी द्वारा उपयोग किए जा रहे उत्पाद/प्रक्रिया/प्रौद्योगिकी को भी निर्दिष्ट किया जाएगा। हालाँकि, अतिलंघन साबित करने का दायित्व अधिनियम की धारा 104क के अनुसार होगा;

4. किसी भी पक्ष द्वारा दायर किए जाने वाले दस्तावेज...

ग. किसी भी पक्ष द्वारा दायर किए जाने वाले कोई अन्य दस्तावेज...

(ii) लाइसेंसधारियों, स्वामिस्व, एफआरएएनडी मूल्य निर्धारण का विवरण (मुहरबंद लिफाफे में) दायर किया जाएगा।

5. वाद की पहली सुनवाई.....

(V) प्रथम दृष्टया अतिलंघन सिद्ध होने पर, न्यायालय असाधारण परिस्थितियों में व्यादेश के स्थान पर मौद्रिक भुगतान के लिए निर्देश

पारित कर सकता है, तथा ऐसी शर्तों और नियमों पर, जिन्हें न्यायालय उचित समझे।”

यदि अतिलंघनकर्ता/कार्यान्वयनकर्ता एक अनिच्छुक लाइसेंसधारी है तो मानक आवश्यक पेटेंट स्वामी व्यादेश राहत की माँग कर सकते हैं

76. इंटेक्स की ओर से यह तर्क कि न्यायालय को व्यादेश नहीं देना चाहिए या भुगतान करने का निर्देश नहीं देना चाहिए, क्योंकि मानक आवश्यकता पेटेंट स्वामी का एकमात्र हित उचित स्वामिस्व प्राप्त करने में है, एक ऐसा हित जिसे विचारण के अंत में क्षतिपूर्ति के पुरस्कार द्वारा पूरी तरह मान्यता दी जा सकती है, विधि में असमर्थनीय है।

77. यू.के. सुप्रीम कोर्ट के अनुसार *अनवायर्ड प्लैनेट बनाम हुआवेई* (पूर्वोक्त) में “.... यदि पेटेंट धारक को मौद्रिक उपाय तक सीमित कर दिया जाता है, तो पेटेंट का अतिलंघन करने वाले कार्यान्वयनकर्ताओं को तब तक अतिलंघन जारी रखने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा, जब तक कि पेटेंट दर पेटेंट और देश दर देश उन्हें स्वामिस्व का भुगतान करने के लिए बाध्य न कर दिया जाए। उनके लिए स्वेच्छा से एफआरएएनडी लाइसेंस में प्रवेश करना आर्थिक रूप से समझदारी नहीं होगी। व्यवहार में, उस आधार पर पेटेंट अधिकारों का प्रवर्तन अव्यावहारिक हो सकता है.....” (पैरा 167)।

78. इसके विपरीत, अंतरिम अवधि में स्वामिस्व का भुगतान करने का आदेश या निर्देश अधिक प्रभावी उपाय हो सकता है, क्योंकि इससे न केवल पेटेंट का अतिलंघन करने वाले उत्पादों की लागत में मामूली वृद्धि होगी, बल्कि अतिलंघन पर पूर्ण प्रतिबंध भी लगेगा।

79. इसके अतिरिक्त, एफआरएनडी सिद्धांत, जो मानक आवश्यक पेटेंट स्वामियों को व्यादेश राहत प्राप्त करने से रोकता है, को यूरोपीय संघ के न्यायालय ('ईयू'), यूके सुप्रीम कोर्ट और संघीय सर्किट के लिए यूएस कोर्ट ऑफ अपील द्वारा खारिज कर दिया गया है।

80. *हुआवेई बनाम जेडटीई* (पूर्वोक्त) में, सीजेईयू ने अभिनिर्धारित किया है कि एक मानक आवश्यक पेटेंट स्वामी एक कार्यान्वयनकर्ता द्वारा चल रहे अतिलंघन के विरुद्ध व्यादेश की माँग कर सकता है जब तक कि कार्यान्वयनकर्ता एक निर्दिष्ट एफआरएनडी-अनुपालन प्रति-प्रस्ताव प्रस्तुत करके मानक आवश्यक पेटेंट स्वामी के स्वामिस्व प्रस्ताव का जवाब नहीं देता है और विवाद के समाधान तक उचित सुरक्षा प्रदान नहीं करता है।

81. *हुआवेई बनाम जेडटीईआई* (पूर्वोक्त) में 2015 के निर्णय के बाद, यूके हाई कोर्ट ऑफ जस्टिस और यूके सुप्रीम कोर्ट ने मानक आवश्यक पेटेंट स्वामियों के अधिकार की पुष्टि की, ताकि वे किसी ऐसे "अनिच्छुक लाइसेंसधारी" के सामने व्यादेश प्राप्त कर सकें, जो पारंपरिक टालमटोल की रणनीति अपनाता है। [देखें:

अनवायर्ड प्लैनेट इंटरनेशनल लिमिटेड और अन्य बनाम हुआवेई टेक्नोलॉजीज (यूके) कंपनी लिमिटेड और अन्य, [2020] यूकेएससी; अनवायर्ड प्लैनेट इंटरनेशनल लिमिटेड और अन्य बनाम हुआवेई टेक्नोलॉजीज (यूके) कंपनी लिमिटेड और अन्य, [2017] ईडब्ल्यूएचसी 2988 (पेटेंट)]

82. डच और जर्मन राष्ट्रीय न्यायालयों ने भी मानक आवश्यक पेटेंट स्वामियों को व्यादेश जारी की है, इस आधार पर कि अतिलंघनकर्ता ने "प्रतिरोधक" व्यवहार किया था। [देखें: *कोनिंक्लीजके फिलिप्स एन.वी. बनाम असुसटेक कंप्यूटर्स इंकांर्पोरेशन, द हेग में कोर्ट ऑफ अपील, मामला सं. 200.221.250/01 (7 मई, 2019); टैगिवन (एमपीईजी एलए) बनाम हुआवेई, डसेलडोर्फ का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, मामला सं. 4ए ओ 17/17 (15 नवंबर, 2018)]*

83. इसी तरह के दृष्टिकोण को दर्शाते हुए, फेडरल सर्किट के लिए यूएस कोर्ट ऑफ अपील ने अभिनिर्धारित किया गया है कि "एक व्यादेश [एक मानक आवश्यक पेटेंट स्वामी के लिए] उचित हो सकता है, जब अतिलंघनकर्ता एकतरफा रूप से एफआरएएनडी स्वामिस्व से इनकार करता है या उसी प्रभाव के लिए अनुचित रूप से वार्ता में देरी करता है।" [देखें: *एप्पल इंक बनाम मोटोरोला इंक, 757 एफ.3डी 1286, 1332 (फेडरल सर्किट 2014)]*

84. यह तर्क गलत है कि यू.के. सुप्रीम कोर्ट ने *अनवायर्ड प्लैनेट बनाम हुआवेई* (पूर्वोक्त) मामले में यह आदेश दिया है कि मानक आवश्यक पेटेंट विवादों में

अंतरिम राहत नहीं मिलनी चाहिए। उक्त निर्णय में यह माना गया है कि मानक आवश्यक पेटेंट विवादों को प्रत्येक अधिकार क्षेत्र के अलग-अलग विधिक मानकों और प्रथाओं के अनुसार तय किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, यह विभिन्न विधिक प्रथाओं के बीच निम्नानुसार अंतर करता है:

(i) जर्मनी - अतिलंघन की सुनवाई करते समय न्यायालय वैधता का निर्णय नहीं करते। वैधता की सुनवाई एक अलग न्यायालय में की जाती है, और इस प्रकार, वैधता पर निर्णय लिए बिना अतिलंघनकर्ता को रोका जा सकता है।

(ii) यूरोपीय संघ के न्यायालय - यूरोपीय संघ के कई न्यायालय एफआरएएनडी या अनिच्छा पर विचार ही नहीं करते, तथापि मानक आवश्यक पेटेंट विवादों में व्यादेश प्रदान कर देते हैं।

(iii) यूके - यू.के. के न्यायालयों की यह परंपरा है कि वे वैधता, अतिलंघन और एफआरएएनडी पहलुओं पर निर्णय लिए बिना अंतिम व्यादेश नहीं देते। इस पहलू पर यू.के. सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का पैराग्राफ 151 नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:-

"यह भी स्पष्ट है कि न्यायालय को कुछ हद तक लचीलापन अपनाना चाहिए था, क्योंकि तथ्यात्मक स्थितियों की विविधता ऐसी थी जिसमें यह मुद्दा उठ सकता था, तथा यह तथ्य भी कि विभिन्न विधिक प्रणालियाँ एसईपी स्वामी के व्यादेश आवेदन के लिए बहुत अलग प्रक्रियात्मक संदर्भ प्रदान करेंगी। उदाहरण के लिए, जर्मनी में, जैसा कि हमने पहले देखा, वैधता और अतिलंघन पर अलग-अलग सुनवाई की जाती है, जिससे कथित अतिलंघनकर्ता को यह जोखिम रहता है कि एसईपी स्वामी वैधता

निर्धारित किए बिना ही उसके विरुद्ध अंतिम व्यादेश प्राप्त कर सकता है, तथा कुछ सदस्य राज्यों में, एफआरएनडी दर निर्धारित किए जाने से पहले ही व्यादेश प्रदान की जा सकती है। इसके विपरीत, यूनाइटेड किंगडम में, अंतिम व्यादेश देने की प्रथा नहीं है, जब तक कि न्यायालय इस बात से संतुष्ट न हो जाए कि पेटेंट वैध है और उसका अतिलंघन हुआ है, तथा उसने एफआरएनडी दर निर्धारित कर दी है।”

(ज़ोर दिया गया)

85. परिणामस्वरूप, हालाँकि **अनवायर्ड प्लैनेट बनाम हुआवेई** (पूर्वोक्त) मामले में, यूके सुप्रीम कोर्ट ने एफआरएनडी विचारण के बाद तक व्यादेश नहीं दिया था, फिर भी इस न्यायालय का विचार है कि न्यायालयों को विचारण से पहले ऐसा करना चाहिए और ऐसा कर सकते हैं।

86. हाल ही में, **इंटरडिजिटल बनाम लेनोवो 2023 ईडब्ल्यूएचसी 539 (पेटेंट)** में यूके हाई कोर्ट ने अभिनिर्धारित किया है कि एक कार्यान्वयनकर्ता का 'मन परिवर्तन' हो सकता है और वह न्यायालय द्वारा निर्धारित एफआरएनडी दरों पर एफआरएनडी लाइसेंस लेने की अपनी इच्छा व्यक्त कर सकता है, भले ही न्यायालय ने तकनीकी विचारण के बाद अतिलंघन का निष्कर्ष दिया हो और यदि वह ऐसा करता है तो कार्यान्वयनकर्ता के विरुद्ध कोई व्यादेश आदेश पारित नहीं किया जाएगा।

87. हालाँकि, इस न्यायालय का विचार है कि उक्त निर्णय वर्तमान मामले में लागू नहीं होता है क्योंकि यह पाँच तकनीकी विचारणों के पूरा होने के बाद एफआरएनडी विचारण में सुनाया गया था, न कि अंतरिम चरण में। इसके

अतिरिक्त, उक्त निर्णय के पैराग्राफ 6 और 16 में रेखांकित मुख्य मुद्दे यह निर्धारित करने में सहायक थे कि एफआरएएनडी की शर्तें क्या थीं और उचित उपाय क्या था। इसके अतिरिक्त, *इंटरडिजिटल बनाम लेनोवो* (पूर्वोक्त) मामले में भी, कार्यान्वयनकर्ता ने अपनी इच्छा प्रदर्शित करने के लिए पेटेंटधारी को बैंक गारंटी के रूप में सुरक्षा प्रदान की थी (पैरा 203 और 936)।

88. इसके अतिरिक्त, *इंटरडिजिटल बनाम लेनोवो* (पूर्वोक्त) मामले में अधिकांश पैराग्राफ अंग्रेजी न्यायालयों में अपनाई गई विशिष्ट प्रथा के लिए प्रासंगिक हैं, जो अतिलंघन के निष्कर्ष और एफआरएएनडी विचारण के बीच अंतराल की परिकल्पना करता है। वास्तव में, *ऑप्टिस सेलुलर टेक्नोलॉजी एलएलसी बनाम एप्पल रिटेल यू.के. लिमिटेड* (पूर्वोक्त) मामले में यू.के. कोर्ट ऑफ अपील द्वारा वर्तमान यू.के. अभ्यास की आलोचना की गई है, तथा कहा गया है कि यह मानक आवश्यक पेटेंट/एफआरएएनडी विवादों के निर्धारण की प्रणाली की 'अकार्यात्मक स्थिति' है। उक्त निर्णय का प्रासंगिक अंश नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:-

“115. ये अपीलें एक बार फिर एसईपी/एफआरएएनडी विवादों के निर्धारण हेतु वर्तमान प्रणाली की अक्रियाशील स्थिति को दर्शाती हैं। ईपी744 का अतिलंघन करने के आरोप में न्यायालय द्वारा निर्धारित लाइसेंस लेने से इनकार करने के एप्पल के व्यवहार और उनकी अपील के अनुसरण को प्रतिरोध करने का एक रूप माना जा सकता है (क्या एप्पल वास्तव में प्रतिरोध का दोषी है, यह विचारण ई का मुद्दा है); जबकि ऑप्टिस का यह प्रतिवाद कि बिना शर्त के व्यादेश प्रदान किया जाना चाहिए, रोका का द्वार खोल देगा। प्रत्येक पक्ष ने व्यवस्था को अपने पक्ष में करने के प्रयास में अपनी स्थिति अपनाई है। इस तरह के व्यवहार को रोकने का एकमात्र तरीका यह है कि

ईटीएसआई जैसे एसडीओ ऐसे विवादों के विधिक रूप से लागू मध्यस्थता को अपनी आईपीआर नीतियों का हिस्सा बनाएँ।”

(जोर दिया गया)

89. विधिक शिक्षाविदों, अर्थशास्त्रियों और पूर्व संयुक्त राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा 9 मई, 2022 को दायर एक पत्र के अनुसार, विभिन्न न्यायालयों में न्यायिक राय की यह एकरूपता, प्रभाव आकलन के लिए साक्ष्य के लिए यूरोपीय आयोग के आह्वान के जवाब में, सामान्य ज्ञान को दर्शाती है। उक्त दस्तावेज के अनुसार, यदि मानक आवश्यक पेटेंट स्वामियों को व्यागेश माँगने से स्पष्ट रूप से रोक दिया जाता है, तो अतिलंघनकर्ताओं के पास मानक आवश्यक पेटेंट स्वामियों के साथ लाइसेंस के लिए सहमत होने या सद्भावनापूर्वक बातचीत करने का कोई कारण नहीं होगा। एक अच्छी तरह से संसाधन संपन्न अतिलंघनकर्ता किसी भी लाइसेंस प्रस्ताव को तर्कसंगत रूप से अस्वीकार कर देगा और मानक आवश्यक पेटेंट स्वामी को मुकदमेबाजी में प्रवेश करने के लिए विवश करेगा, जिसके लिए आमतौर पर दुनिया भर के कई स्थानों पर विधिक व्यय में लाखों डॉलर की आवश्यकता होती है। सबसे खराब स्थिति में, अतिलंघनकर्ता को मौद्रिक क्षतिपूर्ति का भुगतान करने के लिए विवश किया जाएगा, जिसकी गणना आम तौर पर वार्ता के माध्यम से लाइसेंस संबंधी लेनदेन में दर की नकल करने के लिए तैयार की गई पद्धति का उपयोग करके की जाती है। यहाँ तक कि वर्तमान विधिक व्यवस्था के अंतर्गत भी, जिसमें व्यादेश राहत यथोचित रूप से उपलब्ध हो सकती है, लेकिन

केवल विलंबित और महंगी मुकदमेबाजी प्रक्रिया के बाद, अच्छी तरह से संसाधन संपन्न कार्यान्वयनकर्ता नियमित रूप से मानक आवश्यक पेटेंट स्वामियों के साथ बातचीत के शुरू में लाइसेंस लेने से इनकार कर देते हैं, जिससे दोनों पक्षकारगण को कई अधिकार क्षेत्रों में मुकदमेबाजी पर लाखों डॉलर और हजारों कामकाजी घंटे खर्च करने के लिए विवश होना पड़ता है। उन संसाधनों को उन्नत प्रौद्योगिकियों के लिए अनुसंधान एवं विकास की दिशा में अधिक उत्पादकतापूर्वक निर्देशित किया जा सकता है।

90. न्यायालय का यह भी मानना है कि भारतीय वास्तविकताओं को ध्यान में रखते हुए मानक आवश्यक पेटेंट के संबंध में विदेशी न्यायशास्त्र को अपनाना होगा, विशेष रूप से यह तथ्य कि इस देश में न्यायाधीश-जनसंख्या अनुपात अत्यंत खराब है और अन्य वादों के मूल्य पर पेटेंट वादों के शीघ्र निपटान की उम्मीद नहीं की जा सकती। इस तथ्य को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है कि विधिक व्यवस्थाएँ जो मानक आवश्यक पेटेंट मुकदमों में अतिलंघनकर्ताओं के विरुद्ध व्यादेश राहत की उचित उम्मीद को संरक्षित नहीं करती हैं, उनका एक प्रतिकूल "दूरगामी प्रभाव" होगा जो सभी मानक आवश्यक पेटेंट लाइसेंस संबंधी वार्ताओं में कार्यान्वयनकर्ताओं के लिए सौदेबाजी का लाभ स्थानांतरित कर देगा, मौजूदा पेटेंट-संरक्षित प्रौद्योगिकियों का अवमूल्यन करेगा और नई प्रौद्योगिकियों को विकसित करने से फर्मों को हतोत्साहित करेगा। उचित समयावधि के भीतर व्यादेश की

किसी वास्तविक संभावना के अभाव में, कार्यान्वयनकर्ता को नवप्रवर्तक की प्रौद्योगिकी तक पहुँच प्राप्त होती है, तथा वह उस प्रौद्योगिकी को मूर्त रूप देने वाले उत्पादों और सेवाओं से राजस्व प्राप्त करता है, जबकि, वार्ता और मुकदमेबाजी के दौरान, नवप्रवर्तक को उसी प्रौद्योगिकी से कुछ भी प्राप्त नहीं होता है, जिसे उसने बहुत अधिक लागत और जोखिम के साथ विकसित किया है। इस विषमता के कारण निपटान राशि या, मुकदमेबाजी के अभाव में, वार्ता के आधार पर तय किए गए स्वामिस्व की संभावना बढ़ जाती है, जो नवप्रवर्तक की प्रौद्योगिकी का कम मूल्यांकन करती है। इससे प्रभावी रूप से उन फर्मों से धन हस्तांतरित होता है जो प्रौद्योगिकियों के विकास में विशेषज्ञता रखती हैं, उन फर्मों को (जिनमें दुनिया की कुछ सबसे मूल्यवान कंपनियां भी शामिल हैं) जो उपभोक्ताओं को बेचे जाने वाले ब्रांडेड उपकरणों/उत्पादों में उन प्रौद्योगिकियों का उपयोग करने और उन्हें एकीकृत करने में विशेषज्ञता रखती हैं।

91. उपर्युक्त बातों के साथ-साथ इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि भारतीय विधि में मानक आवश्यक पेटेंटधारी के विरुद्ध व्यादेश माँगने पर कोई प्रतिबंध नहीं है, इस न्यायालय का विचार है कि मानक आवश्यक पेटेंट स्वामी जो वाद दायर करते हैं, वे अंतरिम और अंतिम व्यादेश राहत के लिए प्रार्थना कर सकते हैं यदि अतिलंघनकर्ता को न्यायालय द्वारा "अनिच्छुक लाइसेंसधारक" माना जाता है, जैसा

कि अक्सर "विलंब" और अन्य अवसरवादी सौदेबाजी और मुकदमेबाजी रणनीति के उपयोग से संकेत मिलता है।

मानक आवश्यक पेटेंट मामले में अतिलंघन की कसौटी क्या है?

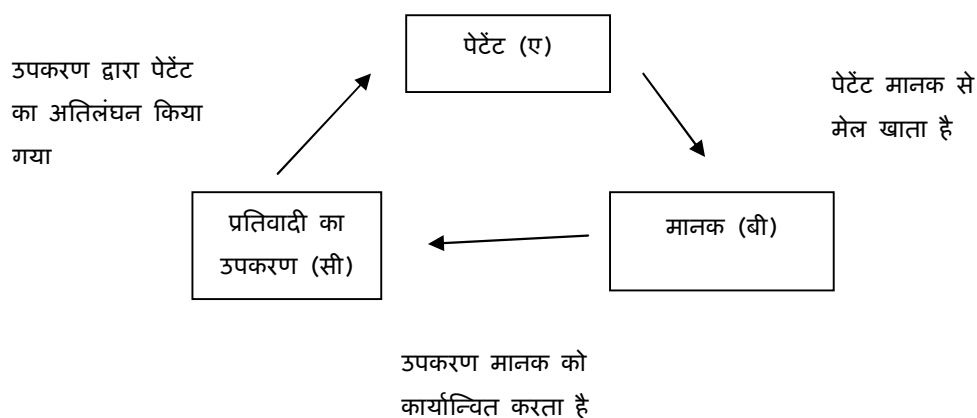
92. चूँकि एसएसओ यह नहीं जाँचते कि कौन से पेटेंट वास्तव में आवश्यक हैं और घोषणाकर्ता अनिवार्यता का कोई सबूत नहीं देते हैं, इसलिए बहुत सारी अस्पष्ट घोषणाएँ किए जाने की संभावना है जो भ्रामक हो सकती हैं। परिणामस्वरूप, मानक आवश्यक पेटेंट के अनिच्छुक लाइसेंसधारी के मामले में अतिलंघन के लिए परीक्षण को प्रथम दृष्टया चरण में संतुष्ट करना होगा।

93. अतिलंघन का प्रत्यक्ष परीक्षण सभी मानक पेटेंट मामलों में लागू होता है। दूसरा अप्रत्यक्ष तरीका है जिसमें निम्नलिखित चरणों को साबित करना शामिल है:

- (i) पेटेंटधारक के पेटेंट को मानक के साथ मानचित्रित करना, यह दर्शाने के लिए कि पेटेंट एक मानक आवश्यक पेटेंट है।
- (ii) यह दर्शाता है कि कार्यान्वयनकर्ता का उपकरण भी मानक से मेल खाता है।

94. यह परिवर्तनशीलता के नियम के समान है, अर्थात यदि ए=बी और बी=सी, तो ए=सी, जहाँ

ए = पेटेंट; बी = मानक ; सी = प्रतिवादी का उपकरण



95. यह दर्शाने के लिए कि पेटेंट मानक (ए=बी) से मेल खाता है, न्यायालय "दावा चार्ट" पर विचार करती हैं, जो यह दर्शाता है कि पेटेंट के दावे मानक की तकनीकी विशेषताओं में भी मौजूद हैं।

96. यह दर्शाने के लिए कि कार्यान्वयनकर्ता का उपकरण मानक (बी=सी) के अनुरूप है, न्यायालय या तो परीक्षण रिपोर्ट जैसे प्रामाणिक स्रोतों पर विचार कर सकते हैं जो दर्शाते हैं कि उपकरण मानक के अनुरूप है। हालाँकि, यह एक आवश्यक आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अधिकांश उपकरण किसी दिए गए मानक के

साथ अपने अनुपालन की घोषणा करते हैं। उदाहरण के लिए, सभी मोबाइल फोन घोषणा करते हैं कि वे 3जी/4जी/5जी के अनुरूप हैं।

97. मानक आवश्यक पेटेंट अतिलंघन को साबित करने के लिए अप्रत्यक्ष परीक्षण दशकों पुराना है। उदाहरण के लिए, *फुजित्सु लिमिटेड बनाम नेटगियर इंकाॅर्पोरेशन* (620 एफ.3डी 1321) में फेडरल सर्किट के लिए यूएस कोर्ट ऑफ अपील ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है:

"हमारा मानना है कि अतिलंघन का विश्लेषण करने में जिला न्यायालय उद्योग मानक पर भरोसा कर सकता है। यदि जिला न्यायालय दावों की व्याख्या करता है और पाता है कि दावों की पहुँच में कोई ऐसा उपकरण शामिल है जो किसी मानक का पालन करता है, तो यह अतिलंघन का पता लगाने के लिए पर्याप्त हो सकता है। हम सहमत हैं कि अतिलंघन का निर्धारण करने के लिए दावों की तुलना अभियुक्त उत्पाद से की जानी चाहिए। हालाँकि, यदि कोई अभियुक्त उत्पाद किसी मानक के अनुसार काम करता है, तो उस मानक के साथ दावों की तुलना करना, दावों की अभियुक्त उत्पाद से तुलना करने के समान है।"

(जोर दिया गया)

98. इस न्यायालय की राय है कि दिल्ली उच्च न्यायालय के पेटेंट नियम और अंतरराष्ट्रीय न्यायशास्त्र इस बात पर एकमत हैं कि "अप्रत्यक्ष" विधि मानक आवश्यक पेटेंट अतिलंघन और अनिवार्यता को साबित करने का एक सुनिश्चित और बेहतर तरीका है।

यदि प्रथम दृष्टया एक पेटेंट का अतिलंघन सिद्ध हो जाए तो भी व्यादेश दिया जा सकता है

99. इस न्यायालय का विचार है कि व्यादेश प्राप्त किया जा सकता है, भले ही एक पेटेंट का अतिलंघन प्रथम दृष्टया या अंतिम चरण में सिद्ध हो जाए।

100. यह सिद्धांत यूएसए से आने वाले मानक आवश्यक पेटेंट न्यायशास्त्र में भी स्थापित है। *माइक्रोसॉफ्ट बनाम मोटोरोला [मामला सं. सी10-1823जेएलआर (डब्ल्यू.डी. वाशिंगटन, 25 अप्रैल, 2013)]* के प्रसिद्ध मामले में, सिएटल में वाशिंगटन के पश्चिमी जिले के यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने संपूर्ण मानक आवश्यक पेटेंट पोर्टफोलियो के लिए देय उचित स्वामिस्व निर्धारित करने के लिए मुट्ठी भर प्रतिनिधि पेटेंट का मूल्यांकन करने की प्रथा को बरकरार रखा।

101. इसी प्रकार, *इवनकॉम बनाम सोनी (2015, सं. 1194, सिविल प्रथम दृष्टया निर्णय)* में बीजिंग हाई कोर्ट ने पोर्टफोलियो दर (आरएमबी 1/यूनिट) के आधार पर क्षतिपूर्ति के दावे को बरकरार रखा, तथा अभिनिर्धारित किया कि वाद में दावा किया गया एकमात्र पेटेंट - जो पेटेंटों के बड़े पोर्टफोलियो के लिए महत्वपूर्ण था - का अतिलंघन किया गया था।

102. विभिन्न देशों के उद्योग अभ्यास के निर्णयों का अध्ययन, निम्नलिखित सर्वसम्मत दृष्टिकोण को प्रदर्शित करता है:

- (i) पेटेंट अतिलंघन के वाद में, मानक आवश्यक पेटेंट धारक केवल मुट्ठी भर प्रतिनिधि पेटेंटों का दावा करते हैं, भले ही उनके पोर्टफोलियो में सैकड़ों या हजारों मानक आवश्यक पेटेंट हों।
- (ii) मानक आवश्यक पेटेंट धारक द्वारा एक (1) पेटेंट का अतिलंघन स्थापित करने पर उपकरणों के विक्रय पर रोक लगाने का व्यादेश दिया जाता है।
- (iii) संपूर्ण पोर्टफोलियो के लिए एफआरएएनडी स्वामित्व दर का निर्धारण भी वाद में प्रस्तुत प्रतिनिधि पेटेंटों के मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है।
- (iv) पेटेंट-दर-पेटेंट आधार पर एफआरएएनडी दर का लाइसेंस देना या मूल्यांकन करना अव्यावहारिक है और उद्योग अभ्यास के विपरीत है।

103. तदनुसार, इस न्यायालय का मानना है कि यदि पेटेंटधारी यह दर्शाता है कि किसी उत्पाद में भले ही एक पेटेंट का अतिलंघन हुआ हो, तो कार्यान्वयनकर्ता के उत्पाद का विक्रय नहीं जा सकता और उसमें मौजूद हजारों पेटेंट कार्यान्वयनकर्ता के लिए किसी काम के नहीं रहेंगे। तदनुसार, यदि अतिलंघन का मामला बनता है, भले ही एक पेटेंट के संबंध में, तो यह पेटेंटधारी के लिए "संपूर्ण समस्या के एक समाधान" की तरह होगा।

104. परिणामस्वरूप, किसी अतिलंघनकारी उपकरण को रोकने के लिए, किसी मानक आवश्यक पेटेंट धारक को उस उत्पाद में अपने स्वामित्व का दावा करने वाले हजारों पेटेंटों में से प्रत्येक के आधार पर मुकदमा करने की आवश्यकता नहीं होती; वह ऐसा यह दर्शाकर मुकदमा कर सकता है कि एक या कुछ प्रतिनिधि पेटेंटों का अतिलंघन किया गया है।

क्या एक मानक आवश्यक पेटेंटधारी विवादित या संभावित रूप से विवादित विदेशी पेटेंट से संबंधित लाइसेंस सहित पोर्टफोलियो लाइसेंस की पेशकश कर सकता है?

105. मुद्दा यह है कि क्या एक मानक आवश्यक पेटेंट स्वामी, जिसने एफआरएएनडी प्रतिबद्धता की थी, को व्यक्तिगत एकल-पेटेंट एफआरएएनडी लाइसेंस (अर्थात किसी विशेष क्षेत्र में किसी विशेष पेटेंट तक सीमित लाइसेंस) की पेशकश करने की आवश्यकता थी, या क्या वह पोर्टफोलियो / क्लस्टर लाइसेंस की पेशकश करके अपने एफआरएएनडी दायित्वों का पालन कर सकता था, यह लंबे समय से चल रहे *अनवायर्ड प्लैनेट बनाम हुआवेई* (पूर्वोक्त) मुकदमे में प्राथमिक प्रश्न था। विचारण न्यायाधीश (न्या. बिर्स) और कोर्ट ऑफ अपील दोनों ने अभिनिर्धारित किया कि पेटेंटधारी को व्यक्तिगत पेटेंट लाइसेंस या देश विशिष्ट लाइसेंस देने की आवश्यकता नहीं है और वैश्विक पोर्टफोलियो लाइसेंस एफआरएएनडी होने में सक्षम हैं।

106. कोर्ट ऑफ अपील ने अभिनिर्धारित किया कि खंड 6.1 के अनुसार ईटीएसआई को दिया गया परिवचन अंतरराष्ट्रीय प्रभाव रखता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ईटीएसआई परिवचन द्वारा समर्थित मानक स्वयं अंतरराष्ट्रीय प्रभाव रखते हैं, ताकि व्यवसाय करने वाला व्यक्ति उन उत्पादों का निर्माण और आपूर्ति कर सके तथा जनता के सदस्य उन उत्पादों का उपयोग पूरी दुनिया में कर सकें जो मानक का अनुपालन करते हैं। इस संबंध में ईटीएसआई आईपीआर नीति के खंड

6.2 में यह प्रावधान है कि किसी पेटेंट परिवार के सदस्य के संबंध में खंड 6.1 के अनुसार दिया गया परिवचन उस पेटेंट परिवार के सभी विद्यमान और भावी आवश्यक बौद्धिक संपदा अधिकारों पर लागू होगा, जब तक कि परिवचन दिए जाने के समय निर्दिष्ट बौद्धिक संपदा अधिकारों का स्पष्ट लिखित बहिष्कार न हो। यह कार्यान्वयनकर्ताओं की सुरक्षा के लिए भी आवश्यक है, जिनके उपकरण कई अलग-अलग अधिकार क्षेत्रों में विक्रय किए जा सकते हैं और फिर जनता द्वारा उपयोग किए जा सकते हैं, जो उस उपकरण के साथ एक अधिकार क्षेत्र से दूसरे अधिकार क्षेत्र में यात्रा कर सकते हैं। मानकों के अंतरराष्ट्रीय होने के अतिरिक्त, कई पेटेंट पोर्टफोलियो भी अंतरराष्ट्रीय हैं, तथा कई कार्यान्वयनकर्ताओं का व्यवसाय भी अंतरराष्ट्रीय है। अंत में, मुकदमेबाजी प्रक्रिया के बाहर, मानक आवश्यक पेटेंट के स्वामी और कार्यान्वयनकर्ता अक्सर एक लाइसेंस के लिए बातचीत करेंगे जो एफआरएएनडी सिद्धांतों के अनुसार उनकी संबंधित आवश्यकताओं के लिए सबसे उपयुक्त होगा और यह लाइसेंस अक्सर वैश्विक होगा या कम से कम कई अलग-अलग क्षेत्रों को शामिल करेगा। किसी मानक आवश्यक पेटेंट स्वामी के लिए देश-दर-देश अपने पेटेंट अधिकारों के लिए लाइसेंस प्राप्त करना या बातचीत करना पूरी तरह से अव्यावहारिक हो सकता है, ठीक उसी तरह जैसे उसके लिए प्रत्येक देश में मुकदमा करके उन अधिकारों को लागू करने का प्रयास करना अत्यधिक महंगा हो सकता है। इन सभी कारणों से, यूके न्यायालयों ने अभिनिर्धारित किया है कि ये

विचार इस निष्कर्ष की ओर दृढ़ता से इंगित करते हैं कि एक मानक आवश्यक पेटेंट स्वामी और कार्यान्वयनकर्ता के बीच एक वैश्विक पोर्टफोलियो लाइसेंस एफआरएएनडी हो सकता है। किसी भी मामले में ऐसा होगा या नहीं, यह सभी प्रासंगिक परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। यूके सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईटीएसआई बौद्धिक संपदा अधिकार नीति का उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय प्रभाव डालना है और यूके के निचले न्यायालयों का यह अनुमान सही था कि अपनी बौद्धिक संपदा अधिकार नीति तैयार करते समय ईटीएसआई का इरादा था कि पक्षकारगण और न्यायालयों को वास्तविक दुनिया में वाणिज्यिक प्रथाओं को देखना चाहिए और उनसे सीख लेनी चाहिए।

107. वास्तव में, यूके सुप्रीम कोर्ट ने एक पेटेंट-दर-पेटेंट के आधार पर अतिलंघनकर्ता के विरुद्ध एफआरएएनडी राहत की माँग करने की अव्यवहारिकता को मान्यता देते हुए, अनवायर्ड प्लैनेट बनाम हुआवेई (पूर्वोक्त) में अभिनिर्धारित किया है, "यह निर्णय लेते हुए कि एक विश्वव्यापी लाइसेंस एफआरएएनडी था, न्या. बिर्स ने पोर्टफोलियो लाइसेंसों पर सहमति देने के लिए दूरसंचार उद्योग में अभ्यास को ध्यान में रखा था और टिप्पणी की कि प्रत्येक पेटेंट लाइसेंस जो पक्षकारगण ने विचारण बंडलों में प्रस्तुत किया था, एक विश्वव्यापी पोर्टफोलियो अनुबंध था, हालाँकि कुछ लाइसेंसों ने बाकी दुनिया को लाइसेंस देते समय एक विशेष क्षेत्र बनाया था (पैराग्राफ 524-534)। अनवायर्ड के पोर्टफोलियो में 42 देश

शामिल थे और यह इतना बड़ा था कि प्रत्येक पेटेंट के लिए लड़ना व्यावहारिक नहीं होगा। ऐसे पोर्टफोलियो का इच्छुक लाइसेंसदाता और वैश्विक बिक्री के साथ हुआवेई जैसा इच्छुक लाइसेंसधारी विश्वव्यापी लाइसेंस पर सहमत होंगे (पैराग्राफ 538-543)। *उन्होंने अभिलिखित किया कि यह आम बात थी कि उद्योग ने एक परिवार के भीतर व्यक्तिगत पेटेंट के बजाय पेटेंट परिवारों का मूल्यांकन किया (पैराग्राफ 546)। इस प्रकार उन्होंने यह निर्णय लेने में उद्योग अभ्यास का सहारा लिया कि एफआरएएनडी लाइसेंस एक विश्वव्यापी लाइसेंस होगा।*

108. यूके सुप्रीम कोर्ट ने भी पैराग्राफ 63 में कोर्ट ऑफ अपील के निर्णय को बरकरार रखा कि अंग्रेजी न्यायालयों के पास विवादित विदेशी पेटेंट की एफआरएएनडी शर्तों को निर्धारित करने का अधिकार क्षेत्र है। इसने अभिनिर्धारित किया, *“अब हम [...] प्रस्तुति पर आते हैं कि विवादित या संभावित रूप से विवादित विदेशी पेटेंट से जुड़े लाइसेंस की शर्तों को निर्धारित करने का अंग्रेजी न्यायालयों के पास कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। हम इससे असहमत हैं। अगर अंग्रेजी न्यायालयों के निर्णय किसी विदेशी पेटेंट की वैधता या अतिलंघन पर निर्णय करने के लिए होते, तो यह वास्तव में उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर होता। लेकिन न्या. बिर्स और कोर्ट ऑफ अपील ने ऐसा नहीं किया है। इसके बजाय, उन्होंने उद्योग में पेटेंट के पोर्टफोलियो का लाइसेंस लेने के लिए सहमत होने की व्यावसायिक प्रथा को देखा, भले ही प्रत्येक पेटेंट वैध था या नहीं या मानक में*

प्रासंगिक प्रौद्योगिकी के उपयोग से उसका अतिलंघन किया गया था, और आईपीआर नीति को उस व्यवहार को बढ़ावा देने के रूप में व्याख्यायित किया।”

109. यहाँ तक कि, 'टेरेल ऑन द लॉ ऑफ़ पेटेंट्स' के अनुसार, *अनवायर्ड प्लैनेट बनाम हुआवेई* (पूर्वोक्त) में यूके सुप्रीम कोर्ट ने अभिनिर्धारित किया कि: (क) न्यायालय के लिए यह अनुचित नहीं होगा कि वह किसी कार्यान्वयनकर्ता को यूके के बाजार से बाहर कर दे जब तक कि वह केवल इसलिए वैश्विक लाइसेंस में प्रवेश नहीं करता है क्योंकि उसने यूके के एक पेटेंट का अतिलंघन किया है, क्योंकि कार्यान्वयनकर्ता विधिक रूप से उन उत्पादों का निर्माण और विक्रय करने की क्षमता तक पहुँच बनाएगा जो विश्वव्यापी आधार पर मानक का अनुपालन करते हैं; और (ख) यह दो कारणों से असंगत नहीं था कि एक कार्यान्वयनकर्ता केवल उस क्षति के लिए क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी होना चाहिए जो एक मानक आवश्यक पेटेंट स्वामी अपने एक या अधिक यूके पेटेंट के अतिलंघन के माध्यम से उठाता है यदि कार्यान्वयनकर्ता विश्वव्यापी लाइसेंस में प्रवेश करने के बजाय यूके के बाजार से हटना चुनता है, लेकिन यदि कार्यान्वयनकर्ता यूके में अपने उत्पादों का विपणन करना चाहता है, तो उसे वैश्विक स्वामिस्व का भुगतान करना होगा। प्रथम, न्यायालय द्वारा किए जाने वाले कार्य: (i) क्षतिपूर्ति प्रदान करना, तथा (ii) लाइसेंस की शर्तों का निर्धारण, प्रकृति में भिन्न होते हैं तथा क्षतिपूर्ति प्रदान करने को संविदात्मक लाइसेंस के अंतर्गत भुगतान किए गए स्वामिस्व के समतुल्य

नहीं माना जाना चाहिए। दूसरा, विश्वव्यापी लाइसेंस प्राप्त करने पर कार्यान्वयनकर्ता को विश्वव्यापी आधार पर मानक-अनुरूप उत्पादों का निर्माण और विक्रय करने की विधिक क्षमता प्राप्त होती है।

110. इसके अतिरिक्त, *अनवायर्ड प्लैनेट बनाम हुआवेई* (पूर्वोक्त) मामले में, यूके सुप्रीम कोर्ट ने अन्य अधिकार क्षेत्रों (यूएस, जर्मनी, चीन, जापान और यूरोपीय आयोग के समीक्षा प्राधिकारियों) के न्यायालयों के दृष्टिकोण पर विचार किया और निष्कर्ष निकाला कि उस मामले में निचले न्यायालयों द्वारा अपनाया गया दृष्टिकोण अधिकांश महत्वपूर्ण अधिकार क्षेत्रों के न्यायालयों के दृष्टिकोण से अलग नहीं था।

111. परिणामस्वरूप, चूँकि मूल्य उस प्रौद्योगिकी में है जो मानक का एक भाग बनती है और वादग्रस्त पेटेंट केवल उस प्रौद्योगिकी का प्रतिनिधि है, इसलिए एरिक्सन को व्यक्तिगत पेटेंट लाइसेंस या देश विशिष्ट लाइसेंस प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है और वैश्विक पोर्टफोलियो लाइसेंस एफआरएएनडी होने में सक्षम हैं।

नोकिया बनाम ओप्पो (पूर्वोक्त) मामले में चौगुना परीक्षण विधि के विपरीत है

112. इसके अतिरिक्त, हालाँकि *नोकिया बनाम ओप्पो* (पूर्वोक्त) में चौगुना परीक्षण निर्धारित करते समय, विद्वान एकल न्यायाधीश ने *अनवायर्ड प्लैनेट बनाम हुआवेई* (पूर्वोक्त) के पैराग्राफ 1 से 14 पर भरोसा किया है, फिर भी ऐसा लगता है कि विद्वान एकल न्यायाधीश का ध्यान उक्त निर्णय के बाद के पैराग्राफों, विशेष रूप से

इसके पैराग्राफ 60, 61 और 64 की ओर आकर्षित नहीं हुआ। पैराग्राफ 14, 60, 61 और 64 नीचे पुनः प्रस्तुत किए गए हैं:-

“14. आईपीआर नीति के संदर्भ में इसकी संक्षिप्त पुनर्विलोकन से ऐसा प्रतीत होता है कि निम्नलिखित निष्कर्ष पर पहुँचा जा सकता है। प्रथम, पेटेंट की सामान्य विधि में संविदात्मक संशोधन, एसईपी स्वामियों और कार्यान्वयनकर्ताओं के हितों के बीच उचित संतुलन प्राप्त करने के लिए तैयार किए गए हैं, जिसके अंतर्गत कार्यान्वयनकर्ताओं को एसईपी द्वारा संरक्षित प्रौद्योगिकी तक पहुँच प्रदान की गई है, तथा एसईपी स्वामियों को उनके एकाधिकार अधिकारों के उपयोग के लिए लाइसेंस के माध्यम से उचित पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। दूसरा, एसईपी स्वामी का परिवचन, जिसे कार्यान्वयनकर्ता लागू कर सकता है, एफआरएएनडी शर्तों पर कार्यान्वयनकर्ता को लाइसेंस प्रदान करना, सामान्य विधि के अंतर्गत एसईपी स्वामी के अपने पेटेंट के अतिलंघन को रोकने के लिए व्यादेश प्राप्त करने के अधिकार का एक संविदात्मक अल्पीकरण है। तीसरा, एसईपी स्वामियों से परिवचन प्राप्त करना अक्सर उस समय होगा जब प्रासंगिक मानक तैयार किया जा रहा हो और इससे पहले कि कोई यह जान सके कि (क) क्या विचाराधीन पेटेंट वास्तव में आवश्यक है, या मानक विकसित होने के साथ ही आवश्यक हो सकता है, इस अर्थ में कि पेटेंट का उपयोग किए बिना मानक को कार्यान्वित करना असंभव होगा और (ख) क्या पेटेंट स्वयं वैध है। चौथा, एकमात्र तरीका जिससे कार्यान्वयनकर्ता किसी मानक को कार्यान्वित करते समय एसईपी का अतिलंघन करने से बच सकता है और इस प्रकार प्रासंगिक पेटेंट अधिकारों को नियंत्रित करने वाले अधिकार क्षेत्र की सामान्य विधि के अंतर्गत एसईपी स्वामी के लिए उपलब्ध विधिक उपायों के प्रति स्वयं को उजागर कर सकता है, वह है एसईपी स्वामी पर उस संविदात्मक दायित्व को लागू करके एसईपी स्वामी से लाइसेंस का अनुरोध करना। पाँचवाँ, केवल खंड 6.2 के अनुसार दर्ज किए गए स्पष्ट आरक्षण के अधीन, परिवचन देना, जिसे एसईपी स्वामी अपनी ओर से तथा

अपने सहयोगियों के लिए देता है, घोषित एसईपी के समान पेटेंट परिवार के पेटेंटों तक विस्तारित होता है, जिससे कार्यान्वयनकर्ता को कई अधिकार क्षेत्रों को शामिल करने वाली प्रौद्योगिकी के लिए लाइसेंस प्राप्त करने का अधिकार मिल जाता है। अंततः, आईपीआर नीति में यह परिकल्पना की गई है कि एसईपी स्वामी और कार्यान्वयनकर्ता एफआरएएनडी शर्तों पर लाइसेंस के लिए वार्ता करेंगे। यह उन पक्षकारगण को किसी विशेष पेटेंट की वैधता से संबंधित किसी भी विवाद को अनुबंध के माध्यम से या राष्ट्रीय न्यायालयों के माध्यम से सुलझाने की जिम्मेदारी देता है।

XXX

XXX

XXX

60. प्रस्तुत प्रस्तुति में उस बाह्य संदर्भ को भी पर्याप्त रूप से ध्यान में नहीं रखा गया है जिस पर हमने चर्चा की है। दूरसंचार उद्योग में संचालकों या उनके समनुदेशितियों के पास सैकड़ों या हजारों पेटेंटों का पोर्टफोलियो हो सकता है, जो किसी मानक के लिए प्रासंगिक होंगे। दोनों पक्षकारगण ने स्वीकार किया कि एसईपी के स्वामी और कार्यान्वयनकर्ता, किसी मानक में सम्मिलित सभी पेटेंटों की वैधता और अतिलंघन का परीक्षण नहीं कर सकते, जो कि एक बड़े पोर्टफोलियो में शामिल हैं। कार्यान्वयनकर्ता की रुचि मानक स्थापित होने के बाद यथाशीघ्र अपने उत्पाद को बाजार में लाने में होती है, तथा ऐसा करने के लिए उसे मानक में छोड़े गए सभी पेटेंट प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए प्राधिकरण की आवश्यकता होती है। कार्यान्वयनकर्ता को यह पता नहीं होता कि कौन से पेटेंट वैध हैं और मानक का उपयोग करने से कौन से पेटेंट का अतिलंघन होता है, लेकिन ऐसे पेटेंट द्वारा शामिल की गई प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए उसे शुरू से ही अधिकार की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार, एसईपी या एसईपी की घोषणा करने वाले स्वामी को इस समय यह पता नहीं होता कि उसके कथित एसईपी में से कौन से, यदि कोई हैं, वैध हैं और विकासशील मानक के अनुसार उपयोग द्वारा उनका अतिलंघन किया गया है या किया जाएगा। इसलिए व्यावहारिक समाधान यह है कि एसईपी स्वामी अपने

घोषित एसईपी के पोर्टफोलियो को लाइसेंस देने की पेशकश करे। यही कारण है कि दूरसंचार उद्योग में संचालकों के लिए पेटेंट के पोर्टफोलियो के वैश्विक लाइसेंस पर सहमति जताना आम बात है, बिना यह जाने कि लाइसेंस प्राप्त पेटेंट में से कितने वैध हैं या कितने का अतिलंघन किया गया है। यह अपरिहार्य अनिश्चितता से निपटने का एक समझदारी भरा तरीका है। किसी उद्योग में संचालकों के लिए यह संभव होना चाहिए कि वे इस संभावना को ध्यान में रखें कि लाइसेंस प्राप्त पेटेंटों में से कोई भी अवैध है या उसका अतिलंघन नहीं हुआ है, कम से कम "टॉप डाउन" (ऊपर से नीचे) पद्धति में कुल स्वामिस्व भार की गणना करते समय तो ऐसा ही होना चाहिए। आम तौर पर अप्रमाणित पेटेंट के एक अंतरराष्ट्रीय पोर्टफोलियो का लाइसेंस लेने से कार्यान्वयनकर्ता नए मानक तक पहुँच खरीदता है। यह एक ऐसी कीमत पर ऐसा करता है जो पोर्टफोलियो में कई पेटेंट की अप्रमाणित प्रकृति को प्रतिबिंबित करना चाहिए; ऐसा करने से यह निश्चितता खरीदता है। आईपीआर नीति उस पृष्ठभूमि के विरुद्ध सहमत हुई थी और एसईपी स्वामी से अपेक्षित परिवचन को भी उसी पृष्ठभूमि के विरुद्ध व्याख्या करने की आवश्यकता है।

61. इसलिए हम आईपीआर नीति का यह अर्थ नहीं लगाते हैं कि एसईपी स्वामी को केवल उन पेटेंटों में प्रौद्योगिकी के उपयोग के अधिकार के लिए भुगतान पाने का अधिकार है, जिन्हें वैध और अतिलंघन किए गए के रूप में स्थापित किया गया है। न ही हम आईपीआर नीति का अर्थ एसईपी स्वामी को उचित परिस्थितियों में राष्ट्रीय न्यायालय से व्यादेश प्राप्त करने से रोकने वाले के रूप में लगाते हैं, जहाँ यह स्थापित होता है कि कार्यान्वयनकर्ता उसके पेटेंट का अतिलंघन कर रहा है। इसके विपरीत, आईपीआर नीति पक्षकारगण को लाइसेंस की शर्तों पर सहमति बनाने तथा मुकदमेबाजी से बचने के लिए प्रोत्साहित करती है, जिसमें व्यादेश शामिल हो सकते हैं, जो कार्यान्वयनकर्ता को राष्ट्रीय बाजार से बाहर कर देंगे, जिससे अंतरराष्ट्रीय मानक के प्रभाव को नुकसान पहुँचेगा। इसमें यह माना गया है

कि यदि पेटेंट की वैधता या अतिलंघन के बारे में कोई विवाद है, जिन्हें हल करने की आवश्यकता है, तो पक्षकारगण को राष्ट्रीय न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र का उपयोग करके या मध्यस्थता का अवलंब लेकर उसे हल करना चाहिए। राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा व्यादेश दिए जाने की संभावना उस संतुलन का एक आवश्यक घटक है जिसे आईपीआर नीति स्थापित करना चाहती है, क्योंकि यह वह है जो यह सुनिश्चित करता है कि कार्यान्वयनकर्ता के पास स्वामी के एसईपी पोर्टफोलियो के उपयोग के लिए एफआरएएनडी शर्तों पर वार्ता करने और उन्हें स्वीकार करने के लिए एक मजबूत प्रोत्साहन है। ऐसी राहत प्राप्त करने की संभावना, चाहे वह स्पष्ट रूप से हो या आवश्यक निहितार्थ द्वारा। आईपीआर नीति एसईपी स्वामी की व्यादेश माँगने की क्षमता पर एक सीमा लगाती है, लेकिन वह सीमा एफआरएएनडी शर्तों पर प्रासंगिक प्रौद्योगिकी का लाइसेंस देने की अप्रतिसंहरणीय परिवचन है, जिसे यदि कार्यान्वयनकर्ता द्वारा स्वीकार और सम्मानित किया जाता है तो व्यादेश को बाहर रखा जाएगा।

XXX

XXX

XXX

64. हम पक्षकारगण से सहमत हैं कि आईपीआर नीति में एफआरएएनडी दायित्व उस प्रक्रिया की निष्पक्षता तक विस्तारित है जिसके द्वारा पक्षकारगण लाइसेंस के लिए वार्ता करते हैं। यदि किसी कार्यान्वयनकर्ता को किसी विशेष अधिकार क्षेत्र में विशेष रूप से महत्वपूर्ण पेटेंटों या पेटेंटों के समूह की वैधता और अतिलंघन के बारे में चिंता है, जिसका उस पर भुगतान की जाने वाले स्वामिस्व पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है, तो हमारे विचार में यह निष्पक्ष और उचित होगा कि कार्यान्वयनकर्ता उन पेटेंटों या उन पेटेंटों के नमूने को प्रासंगिक विदेशी न्यायालय में चुनौती देने का अधिकार सुरक्षित रखे और यह अपेक्षा रखे कि लाइसेंस में इसके परिणामस्वरूप स्वामिस्व दरों में परिवर्तन करने के लिए एक माध्यम उपलब्ध कराया जाए। कार्यान्वयनकर्ता के लिए यह भी निष्पक्ष और उचित हो सकता है कि वह लाइसेंस में उन पेटेंटों के लिए स्वामिस्व के रूप में

भुगतान की गई राशि को वसूलने का अधिकार शामिल करने की माँग करे, यदि संबंधित विदेशी न्यायालय ने उन्हें अवैध या अतिलंघन न किए जाने का निर्णय दिया हो, हालाँकि ऐसा प्रतीत होता है कि यह उद्योग जगत में सामान्य अभ्यास नहीं रहा है। हुआवेई का सुझाव है कि यूके के न्यायालय द्वारा वैश्विक लाइसेंस की शर्तों को तय करने से कोई लाभ नहीं होगा, बल्कि विदेशों में घोषित एसईपी को सफलतापूर्वक चुनौती दिए जाने की स्थिति में स्वामिस्व में परिवर्तन का प्रावधान करना उचित होगा। इसमें सुझाव दिया गया है कि इससे लाइसेंस अंतरिम लाइसेंस में बदल जाएगा। फिर से, हम असहमत हैं। एफआरएनडी प्रक्रिया के अंतर्गत कार्यान्वयनकर्ता उन पेटेंट की पहचान कर सकता है जिन्हें वह उचित आधार पर चुनौती देना चाहता है। उदाहरण के लिए, कन्वसेंट मामले में, हुआवेई या जेडटीई द्वारा विचारण के दौरान यह तर्क दिया जा सकता है कि निष्पक्षता और उचितता के दायित्व के लिए कन्वसेंट द्वारा दिए गए किसी भी वैश्विक लाइसेंस में हुआवेई या जेडटीई को कन्वसेंट के चीनी पेटेंट के नमूनों की वैधता और अतिलंघन का परीक्षण करने की अनुमति देने का उपबंध शामिल होना आवश्यक है, जिसमें एक बाजार और विनिर्माण स्थल के रूप में चीन के महत्व को देखते हुए स्वामिस्व दरों के परिणामी समायोजन की संभावना भी शामिल है। अन्य मामलों में, ऐसी चुनौतियों का तब तक कोई मतलब नहीं रह जाता, जब तक कि प्रासंगिक अनिश्चितता को समाप्त करने के संदर्भ में जो हासिल होने की संभावना है, उसके अनुपात में लागत पर, कार्यान्वयनकर्ता पर स्वामिस्व के बोझ में महत्वपूर्ण बदलाव होने की संभावना न हो।”

(जोर दिया गया)

113. परिणामस्वरूप, *नोकिया बनाम ओप्पो* (पूर्वोक्त) में तैयार किया गया परीक्षण कि जब तक इसमें उल्लिखित चार कारक पूरे नहीं होते हैं, तब तक किसी राशि का भुगतान नहीं किया जा सकता है, *अनवायर्ड प्लैनेट बनाम हुआवेई* (पूर्वोक्त) से

मेल नहीं खाता है और यह इसके पैराग्राफ 151 (इसके पहले उद्धृत) के भी विपरीत है, जो यह अभिनिर्धारित करता है कि मानक आवश्यक पेटेंट विवादों पर अंतरिम राहत विभिन्न अधिकार क्षेत्रों में विभिन्न विधिक व्यवस्थाओं के आधार पर दी जानी चाहिए।

114. इसके अतिरिक्त, *नोकिया बनाम ओप्पो* (पूर्वोक्त) में विद्वान एकल न्यायाधीश ने मानक आवश्यक पेटेंट एफआरएएनडी अतिलंघन के एक मामले में प्रवेश के लिए एक असंभव रूप से उच्च मानदंड निर्धारित किया है, अर्थात्, (i) वादग्रस्त पेटेंट की अनिवार्यता और वैधता (ii) उपयोग के तथ्य (iii) तथ्य पर एक स्पष्ट प्रवेश होना चाहिए कि इस तरह के उपयोग, देयता के भुगतान की अनुपस्थिति में अतिलंघन के बराबर होगा (iv) कि वादी द्वारा प्रस्तावित स्वामिस्व दर एफआरएएनडी थी। यदि सभी चार मामलों में स्पष्ट स्वीकृति होती, तो अतिलंघन के लिए वाद दायर करने की कोई आवश्यकता नहीं होती और अन्यथा भी, इसका अर्थ होता कि अंतरिम स्तर पर अंतिम डिक्री की माँग/पारित करनी ही पड़ती!

115. इस न्यायालय की राय में, चौगुना परीक्षण मानक आवश्यक पेटेंटधारी पर एक भारी बोझ डालता है और वह भी अंतरिम चरण में। वास्तव में, उक्त बोझ पेटेंट अधिकार क्षेत्र से पूरी तरह से अलग है और सामान्य पेटेंट वादों में भी लागू नहीं होता है।

116. यह उल्लेख करना भी उचित है कि *नोकिया बनाम ओप्पो* (पूर्वोक्त) निर्णय में विद्वान एकल न्यायाधीश ने पेटेंट वाद 2022 को नियंत्रित करने वाले दिल्ली उच्च न्यायालय के नियमों पर विचार या चर्चा नहीं की, भले ही उक्त नियम इस न्यायालय को सुनवाई की पहली तिथि को भी जमा आदेश पारित करने का विशेष अधिकार देते हैं।

117. इसके अतिरिक्त, यदि *नोकिया बनाम ओप्पो* (पूर्वोक्त) के पैराग्राफ 77 में निर्धारित चार-स्तरीय परीक्षण को लागू किया जाता है, तो प्रभावी रूप से मानक आवश्यक पेटेंट वादों में अस्थायी व्यादेश या जमा के सशर्त आदेश जैसा कोई अंतरिम आदेश नहीं होगा। न्यायालय की राय में, ऐसा दृष्टिकोण पेटेंट अधिनियम की धारा 48, सिविल प्रक्रिया संहिता के साथ-साथ मानक आवश्यक पेटेंट व्यवस्था के विपरीत होगा, जिसका उद्देश्य प्रौद्योगिकियों में एक समान मानक प्राप्त करना है। यदि चार-स्तरीय परीक्षण को स्वीकार कर लिया जाता है, तो नवाचार के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं होगा और इसका 'दूरगामी प्रभाव' होगा, जैसा कि ऊपर बताया गया है। परिणामस्वरूप, *नोकिया बनाम ओप्पो* (पूर्वोक्त) में चौगुना परीक्षण न तो आदेश 39 नियम 10 सि.प्र.सं. चरण पर लागू होता है और न ही आदेश 39 नियम 1 और 2 सि.प्र.सं. चरण पर।

एरिक्सन द्वारा अपने पेटेंट की अनिवार्यता और इंटेक्स द्वारा अतिलंघन के दावे स्वीकार किए गए तथ्य हैं।

118. परिणामस्वरूप, अंतरिम राहत माँगने के चरण में, न्यायालय को मामले में माँगी गई राहत पर प्रथम दृष्टया दृष्टिकोण से विचार करना चाहिए। इसका अर्थ है कि न्यायालय को यह आकलन करना चाहिए कि क्या प्रथम दृष्टया पेटेंट का अतिलंघन हुआ है। न्यायालय को यह भी आकलन करना चाहिए कि क्या कार्यान्वयनकर्ता एक अनिच्छुक लाइसेंसधारी है और/या क्या वादी द्वारा माँगा गया स्वामिस्व एफआरएनडी शर्तों पर है, अर्थात् क्या वैश्विक या स्थानीय स्तर पर समान कार्यान्वयनकर्ता पेटेंटधारी द्वारा सुझाई गई शर्तों के अनुसार स्वामिस्व का भुगतान कर रहे हैं।

119. वर्तमान मामले में, एरिक्सन द्वारा अपने पेटेंट की अनिवार्यता और इंटेक्स द्वारा अतिलंघन के दावे स्वीकार किए गए तथ्य हैं। सीसीआई के समक्ष इंटेक्स द्वारा दायर शिकायत के परिशीलन से पता चलता है कि इंटेक्स ने स्वीकार किया था कि एरिक्सन के वादग्रस्त पेटेंट को उद्योग मानक के रूप में स्वीकार कर लिया गया है और ईटीएसआई के लिए आवश्यक घोषित किया गया है। इंटेक्स ने सीसीआई में अपनी शिकायत में यह भी स्वीकार किया कि भारत सरकार के दूरसंचार विभाग ने ईटीएसआई द्वारा तैयार प्रौद्योगिकी मानक को औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया है और किसी भारतीय दूरसंचार कंपनी के लिए भारत में ईटीएसआई/3जीपीपी जीएसएम मानकों का अनुपालन करने का एकमात्र तरीका एरिक्सन से लाइसेंस प्राप्त करना था। इंटेक्स ने सीसीआई में अपनी शिकायत में

स्वीकार किया कि भारतीय जीएसएम बाजार में प्रत्येक कंपनी को एरिक्सन से लाइसेंस प्राप्त करना पड़ता है, क्योंकि कोई गैर-अतिलंघनकारी विकल्प उपलब्ध नहीं है और एरिक्सन के पास मानकों से संबंधित बड़ी संख्या में मानक आवश्यक पेटेंट हैं। सीसीआई शिकायत में इंटेक्स द्वारा की गई उपरोक्त स्वीकारोक्ति नीचे पुनः प्रस्तुत की गई है:-

"7.12 एरिक्सन के पेटेंट को ईटीएसआई द्वारा उद्योग मानक के रूप में स्वीकार किए जाने के अतिरिक्त, यह भी ध्यान देने योग्य है कि भारत में, दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने ईटीएसआई द्वारा तैयार किए गए प्रौद्योगिकी मानकों को औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया है। यह स्पष्ट रूप से "एकीकृत अभिगम सेवा लाइसेंस" अनुबंध (यूएसएल) से देखा जा सकता है, जो कि अनुलग्नक ड के रूप में संलग्न है, जिसे भारत में प्रत्येक दूरसंचार कंपनी को डीओटी के साथ दर्ज करना आवश्यक है

7.13 जीएसएम प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, ईटीएसआई मानक ही एकमात्र ऐसे मानक हैं जो प्रासंगिक हैं, अर्थात् ईटीएसआई मानक अन्य मानकों के विकल्प नहीं हैं। संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के वायरलेस योजना और समन्वय विंग (डब्ल्यूपीसीडब्ल्यू) के 3 अक्टूबर, 2008 के पत्र, जो अनुलग्नक ढ के रूप में संलग्न है, में यह अनिवार्य किया गया है कि आयात के लिए जीएसएम और सीडीएमए प्रौद्योगिकियों के लिए नेटवर्क उपकरण

3जीपीपी/3जीपीपी2/ईटीएसआई/आईईटीएफ/एएनएसआई/ईआईए/टीआईए/आईएस जैसे निकायों द्वारा प्रदान किए गए अंतरराष्ट्रीय मानकों का अनुपालन करना चाहिए।

XXX XXX XXX

8.4 एरिक्सन के पेटेंट को ईटीएसआई के लिए आवश्यक घोषित किए जाने के अतिरिक्त, यह भी ध्यान देने योग्य है कि भारत में, दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने ईटीएसआई द्वारा तैयार किए गए प्रौद्योगिकी मानकों को औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया है। यह "एकीकृत अभिगम सेवा लाइसेंस" अनुबंध (यूएसएल) से स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, जिसे भारत में प्रत्येक दूरसंचार कंपनी को डीओटी के साथ करना आवश्यक है।

इसलिए, भारत में, जीएसएम और संबंधित प्रौद्योगिकी के लिए डीओटी द्वारा ईटीएसआई मानकों को अनिवार्य किए जाने के कारण, एरिक्सन प्रासंगिक बाजार में एक प्रमुख कंपनी है, जैसा कि ऊपर वर्णित है।

XXX XXX XXX

8.6 इस प्रकार, यह प्रस्तुत किया गया है कि किसी भारतीय दूरसंचार कंपनी के लिए भारत में ईटीएसआई/3जीपीपी जीएसएम मानकों का अनुपालन करने का एकमात्र तरीका उन प्रत्येक पक्षों से लाइसेंस प्राप्त करना है, जो अपने पेटेंट को जीएसएम प्रौद्योगिकी मानक के लिए आवश्यक बताते हैं और एरिक्सन एक ऐसा ही पक्ष है, जो जीएसएम मानक से संबंधित 25-35% से अधिक एसईपी का स्वामित्व होने का दावा करता है। जैसा कि ऊपर बताया गया है, इसके कई एसईपी भारतीय पेटेंट विधि के अंतर्गत भी पंजीकृत हैं। इसलिए, जहाँ तक जीएसएम प्रौद्योगिकी मानक का संबंध है, जहाँ एरिक्सन के पेटेंट को "मानक आवश्यक" घोषित किया गया है, एरिक्सन संभावित लाइसेंसधारियों के साथ अपने जुड़ाव की शर्तों को निर्धारित करने की अपनी क्षमता से अप्रभावित रहता है। भारतीय जीएसएम बाजार में प्रत्येक कंपनी जिसमें हैंडसेट निर्माता और मोबाइल नेटवर्क संचालक शामिल हैं, जो जीएसएम क्षेत्र (2जी, 3जी और 4जी) में काम करते हैं, उन्हें एसईपी मानक आवश्यक पेटेंट के लिए एरिक्सन का लाइसेंस प्राप्त करना होगा।

8.7 मानक आवश्यक पेटेंट के अपने विशाल पोर्टफोलियो के परिणामस्वरूप, जिसके लिए कोई गैर-अतिलंघनकारी विकल्प नहीं हैं, कंपनी प्रासंगिक बाजार में किसी भी प्रतिस्पर्धी ताकतों/दबावों से स्वतंत्र रूप से काम करने की स्थिति में है। एसईपी के एक बड़े पूल पर अपने स्वामित्व की शक्ति के आधार पर, एरिक्सन बिना किसी बाधा के ग्राहकों को अपने एसईपी उपलब्ध कराने के लिए नियम और शर्तें निर्धारित करने की स्थिति में है और इस तरह बाजार को अपने पक्ष में बदल सकता है।

8.8 हालाँकि एरिक्सन का दावा है कि उसके पास जीएसएम और संबंधित प्रौद्योगिकियों के 25-35% एसईपी हैं, लेकिन सूचक का कई अध्ययनों के आधार पर मानना है कि एरिक्सन द्वारा दावा किए गए एसईपी, जिसका उसके स्वामित्व ढाँचे पर प्रभाव पड़ता है, वैध या आवश्यक या दोनों नहीं हो सकते हैं। हालाँकि, उपरोक्त के बाद

भी, इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि एरिक्सन के पास वास्तव में मानकों से संबंधित बड़ी संख्या में एसईपी हैं, यही कारण है कि सूचक ने एरिक्सन के साथ वार्ता की है ताकि उचित शर्तों पर लाइसेंस प्राप्त किया जा सके, बावजूद इसके कि सूचक द्वारा आयोजित मोबाइल उपकरणों के लिए लागू और आवश्यक समझे जाने वाले विशिष्ट पेटेंटों के संबंध में इन स्वतंत्र अध्ययनों या स्वयं एरिक्सन द्वारा निर्देशित नहीं किया गया है। यदि ऐसा नहीं होता, तो न तो सूचक और न ही कोई अन्य बाजार सहभागी एरिक्सन के स्वामित्व वाले एसईपी के लिए आवश्यक लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक समझता, ताकि बाजार में संचालन किया जा सके। इस प्रकार, बाजार सहभागी एरिक्सन को एक प्रमुख उद्यम के रूप में देखते हैं, इस तथ्य के आधार पर कि यह आवश्यक एसईपी का स्वामी है और प्रत्येक संभावित लाइसेंसधारी को इससे लाइसेंस प्राप्त करना होता है, जो इसे प्रासंगिक बाजार में संचालित किसी भी प्रतिस्पर्धी ताकतों से स्वतंत्र रूप से काम करने में सक्षम बनाता है और इस प्रकार उपभोक्ताओं और बाजार को अपने पक्ष में प्रभावित करता है।

(जोर दिया गया)

120. इसके अतिरिक्त, वार्ता के दौरान, इंटेक्स ने एरिक्सन को अपने किसी भी दावे-चार्ट को उपलब्ध नहीं कराया, जिसमें वैकल्पिक तकनीक के उपयोग या एरिक्सन के दावे-चार्ट पर विवाद का संकेत हो। इसके विपरीत, वार्ता के दौरान, इंटेक्स ने एरिक्सन की तकनीक को अक्षम करने का एक तरीका खोजने का प्रयास किया, जैसा कि इंटेक्स के 13 अगस्त, 2012 के अपने ईमेल से स्पष्ट है, जिसे नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:-

"प्रेषक: नेहा सतीजा (मेल: cs@intextedmdoj.es.com)

तिथि एवं समय: 13/08/2012 सुबह 10.30 बजे

प्रति: 'पुष्पेंद्र'

प्रतिलिपि: 'ललिता धामा'; सुधीर- विस्तारित नवीन; 'संजय कुमार कालीरोना'

विषय: अग्रोषित: परीक्षण रिपोर्ट - इंटेक्स

प्रिय सभी,

एरिक्सन के साथ चल रही चर्चा के अनुसरण में, हमें अब स्वतंत्र निकाय से परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त हुई है, कृपया जाँच करें और देखें, यदि हमारे अनुसार यह सही है और यह भी जाँचें कि क्या हम इस तकनीक को अक्षम कर सकते हैं जैसा कि हम पहले चर्चा कर रहे थे। परीक्षण रिपोर्ट गोपनीय है और इसे व्यापक तौर पर प्रसारित नहीं किया जाना चाहिए।

सादर अभिवादन

नेहा”

(जोर दिया गया)

121. इस न्यायालय का यह भी मानना है कि सीसीआई के अधिकार क्षेत्र का अवलंब लेना, जो एरिक्सन के पेटेंट की अनिवार्यता, कार्यान्वयन और प्रधानता की उपधारणा पर आधारित है, यह दर्शाता है कि इंटेक्स इस बात से अच्छी तरह से अवगत था कि वह वादग्रस्त पेटेंट का अतिलंघन कर रहा है।

122. इसके अतिरिक्त, यदि इंटेक्स का यह मानना था कि वह एरिक्सन के पेटेंट का अतिलंघन नहीं कर रहा है और यह अनावश्यक है, तो इंटेक्स को प्रधान स्थिति के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए सीसीआई के पास जाने के बजाय, अधिनियम की धारा 105 और 106 के अंतर्गत गैर-अतिलंघन या निराधार धमकी की घोषणा की माँग करनी चाहिए थी।

123. वास्तव में, इंटेक्स ने आक्षेपित आदेश पारित होने की तिथि तक एरिक्सन के दावा चार्ट पर विवाद करने और/या अनिवार्यता या अतिलंघन के आरोपों से

इनकार करने के लिए दावा चार्ट के साथ कोई जवाबी दावा या विशेषज्ञ साक्ष्य दायर नहीं किया था।

124. यहाँ तक कि, एरिक्सन द्वारा दायर रिट याचिका में दायर अपने प्रति-शपथपत्र में इंटेक्स ने *रि.या.(सि) सं. 1006/2014* में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि उसे एरिक्सन के आठ वादग्रस्त पेटेंट के संबंध में लाइसेंस की आवश्यकता है, जिसे उसने ईटीएसआई के साथ पंजीकृत मानक आवश्यक पेटेंट के रूप में वर्णित किया है। उक्त प्रति-शपथपत्र का प्रासंगिक अंश नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:-

"..... (V) यह भी स्पष्ट रूप से कहा गया कि याचिकाकर्ता 33,000 (लगभग) पेटेंटों का एक पूरा समूह पेश कर रहा था, जबकि वास्तव में प्रत्यर्थी सं. 2 को केवल ईटीएसआई के साथ पंजीकृत 8 मानक आवश्यक पेटेंटों की आवश्यकता थी, इस प्रकार वह बहुत अधिक और सम्मिलित लाइसेंस प्रक्रिया में लिस था।"

(जोर दिया गया)

125. किसी भी घटना में पाँच साल की लंबी अवधि (एफआरएएनडी बातचीत के संबंध में) के दौरान पक्षकारगण के बीच पत्राचार हुआ, जब इंटेक्स ने एरिक्सन के साथ अपने किसी भी दावा चार्ट को साझा नहीं किया, या तो वैकल्पिक तकनीक के उपयोग का संकेत दिया या एरिक्सन पेटेंट की अनिवार्यता पर विवाद किया या एरिक्सन के दावा चार्ट का विरोध किया और तथ्य यह है कि एरिक्सन ने पहले ही विभिन्न तीसरे पक्षकारगण को अपने विश्वव्यापी पेटेंट के लिए लगभग एक सौ

(100) लाइसेंस जारी किए थे; और यह तथ्य कि इंटेक्स ने 14 अप्रैल 2014 को अपने स्वयं के पत्र के माध्यम से एरिक्सन से लाइसेंस लेने का इच्छुक था, इस तथ्य के साथ कि विक्रेता अनुबंध का कोई प्रकटीकरण नहीं किया गया था, यह दर्शाने के लिए पर्याप्त थे कि न तो एरिक्सन पेटेंट की वैधता और न ही अनिवार्यता इंटेक्स द्वारा उठाए गए मुद्दे थे। वैसे भी, यदि एरिक्सन पेटेंट में कोई अनिवार्यता नहीं थी तो पाँच साल की लंबी अवधि के लिए वार्ता की कोई आवश्यकता नहीं थी। इसके अतिरिक्त, इंटेक्स ने कहीं भी यह दावा/ अभिवाक् नहीं दिया है कि उसके पास कोई वैकल्पिक तकनीक है जो किसी भी एरिक्सन पेटेंट का भाग नहीं है।

126. वास्तव में, पाँच वर्षों की अवधि के दौरान चली लंबी बातचीत, उस समय इंटेक्स द्वारा कोई आपत्ति न उठाना, 13 अगस्त, 2012 को जारी उसका ई-मेल, तथा उसके द्वारा की गई सीसीआई शिकायत, जिसमें उसने एरिक्सन के पेटेंट की आवश्यक प्रकृति तथा स्वयं के द्वारा उक्त पेटेंट के उपयोग को स्वीकार किया, इस बात के पर्याप्त प्रमाण थे कि इंटेक्स ने आठ वादग्रस्त पेटेंटों को मानक आवश्यक पेटेंट के रूप में मान्यता दी।

127. इंटेक्स द्वारा उपरोक्त स्वीकारोक्ति के साथ-साथ प्रथम दृष्टया संदेह उत्पन्न करने के लिए किसी भी सामग्री की कमी को देखते हुए, इस न्यायालय की राय है कि विद्वान एकल न्यायाधीश को इस बात का परीक्षण करने की कोई आवश्यकता

नहीं थी कि *फुजित्सु बनाम नेटगियर इंकोर्पोरेशन* (पूर्वोक्त) में निर्धारित अनिवार्यता और/या अतिलंघन का परीक्षण पूरा हुआ है या नहीं।

128. परिणामस्वरूप, यह न्यायालय पैराग्राफ 141 में विद्वान एकल न्यायाधीश के निष्कर्ष से सहमत है कि *"....सीसीआई के समक्ष इसने वादी के एसईपी की अनिवार्यता को स्वीकार किया है और उसी आधार पर, प्रतिवादी ने वादी की प्रधान स्थिति का मुख्य आधार उठाकर वादी के विरुद्ध जाँच का आदेश प्राप्त किया है।"*

केवल इसलिए कि इंटेक्स द्वारा एक प्रतिसंहरण याचिका दायर की गई थी, यह कोई उपधारणा नहीं हो सकती कि एरिक्सन के पेटेंट प्रथम दृष्टया अवैध हैं।

129. जहाँ तक वैधता के मुद्दे का संबंध है, इस न्यायालय का विचार है कि एक बार पेटेंट प्रदान कर दिए जाने के बाद, पंजीकृत पेटेंट की वैधता को चुनौती देने वाले व्यक्ति को विश्वसनीय चुनौती देनी चाहिए। हालाँकि, पेटेंट की वैधता के लिए कार्यान्वयनकर्ता द्वारा प्रस्तुत चुनौती ऐसी नहीं होनी चाहिए जिससे उसकी अवैधता निर्णायक रूप से सिद्ध हो जाए। यह पर्याप्त है कि यदि कार्यान्वयनकर्ता यह सिद्ध करने में सक्षम हो कि पेटेंट अधिनियम के अंतर्गत वादग्रस्त पेटेंट को प्रतिसंहरित किया जा सकता है। हालाँकि, इस कमजोरी को विश्वसनीय चुनौती के माध्यम से प्रदर्शित किया जाना चाहिए, न कि केवल इस आधार पर कि प्रतिसंहरण याचिका दायर की गई है और लंबित है। परिणामस्वरूप, इंटेक्स पर यह दायित्व था कि वह अपने द्वारा उठाई गई चुनौती की विश्वसनीयता स्थापित करे। चुनौती अविश्वसनीय,

काल्पनिक या दिखावटी नहीं हो सकती। आखिरकार, इस तथ्य को, कि एक आविष्कारक को, प्रारंभिक समीक्षा के बाद ही पेटेंट कार्यालय द्वारा पेटेंट प्रदान किया गया है, उचित महत्व दिया जाना चाहिए।

130. वर्तमान मामले में, इंटेक्स ने विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष प्रतिवाद दिया था कि चूँकि प्रतिसंहरण याचिकाएँ *“आईपीएबी जैसे एक मूल विशेषज्ञ मंच”* के समक्ष लंबित थीं, इसलिए विद्वान एकल न्यायाधीश को यह उपधारणा बनानी चाहिए कि एक विश्वसनीय चुनौती उठाई गई है।

131. इस न्यायालय ने पाया कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने पेटेंट की वैधता के संबंध में सही विधि लागू की है क्योंकि *उन्होंने स्ट्रिक्स लिमिटेड बनाम महाराजा एप्लायंसेज लिमिटेड, एमआईपीआर 2010 (1) 181* के निर्णय पर भरोसा किया है जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि *“यहाँ तक कि अंतर्वर्ती चरण में भी, प्रतिवादी को अभिलेख पर कुछ स्वीकार्य वैज्ञानिक सामग्री रखनी होगी, जो किसी विशेषज्ञ के साक्ष्य द्वारा समर्थित या स्पष्ट की गई हो कि वादी का पेटेंट प्रथम दृष्टया प्रतिसंहरण के लिए संवेदनशील है। प्रतिवादी पर बोझ इस तथ्य के कारण अधिक है कि वादी के पेटेंट के लिए, प्रदान करने पूर्व या प्रदान करने के बाद, कोई विरोध नहीं था। बीचम ग्रुप लिमिटेड बनाम ब्रिस्टल लैबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड (1967-68) 118 सीएलआर 618 और ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन बनाम ओ'नील (2006) 229 एएलआर 457 में यह अभिनिर्धारित किया गया कि*

अवैधता का आरोप लगाने वाले प्रतिवादी पर यह स्थापित करने का दायित्व है कि इसमें विचारण के लिए "एक गंभीर प्रश्न" मौजूद है। हेक्सल ऑस्ट्रेलिया प्राइवेट लिमिटेड बनाम रोश थैरेप्यूटिक्स इंकॉर्पोरेशन 66 आईपीआर 325 में यह अभिनिर्धारित किया गया कि जहाँ एक पेटेंट की वैधता को अंतर्वर्ती कार्यवाहियों में उठाया जाता है, "यह दिखाने का दायित्व अवैधता का दावा करने वाले पक्ष पर है कि यहाँ वैधता की कमी एक विचारणीय प्रश्न है।"

132. इसके अतिरिक्त, यह प्रस्तुति कि वादग्रस्त पेटेंट की वैधता साबित करने का दायित्व वादी पर है क्योंकि पेटेंट अधिनियम, 1970 की धारा 13(4), 64 और 107 के संयुक्त पठन को ध्यान में रखते हुए पेटेंट की वैधता की कोई उपधारणा नहीं बनाई जा सकती है, यह विधि की दृष्टि से असमर्थनीय है क्योंकि इस न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने 09.7.2015 को निर्णित सि.वा. (मू.प.) 442/2013 शीर्षक टीएलएम एरिक्सन (पब्लिक) बनाम मर्करी इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य में, ठीक ही अभिनिर्धारित किया है, जो निम्नानुसार है:

"2. प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री साईकृष्ण राजगोपाल इस बात पर बल देते हैं कि उपरोक्त मुद्दे को साबित करने का दायित्व वादी पर होना चाहिए क्योंकि पेटेंट की वैधता की कोई उपधारणा नहीं हो सकती है, जो पेटेंट अधिनियम, 1970 की धारा 13(4), 64 और 107 के संयुक्त पठन से स्पष्ट है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 की धारा 31 के विपरीत, जहाँ व्यापार चिह्न का पंजीकरण उसकी वैधता का प्रथम दृष्टया साक्ष्य है, पेटेंट अधिनियम में ऐसी किसी उपधारणा का प्रावधान नहीं है।

XXX

XXX

XXX

8. अभिवाकों से यह स्पष्ट है कि यह वाद पंजीकृत पेटेंट के आधार पर है। हालाँकि, प्रतिवादीगण ने अपने प्रति-दावे में पेटेंट अधिनियम की धारा 64 के अंतर्गत दिए गए विभिन्न आधारों पर वादग्रस्त पेटेंट को चुनौती देने की माँग की है। यदि साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत उपरोक्त उपबंधों और मुद्दों को तैयार करने वाले सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए वर्तमान मामले का परीक्षण किया जाता है, तो वादग्रस्त पेटेंट की अवैधता साबित करने का भार सीधे तौर पर प्रतिवादीगण पर आएगा।

9. न्यायालय का मानना है कि प्रतिवादीगण को वाद के पेटेंट की अवैधता साबित करने का भार स्वयं उठाना होगा, क्योंकि यह उनका दावा है। यह मानते हुए कि उक्त तर्क के संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया, प्रतिवादीगण हार जाएँगे। इसके अतिरिक्त, वादग्रस्त पेटेंट की अवैधता का अभिवाक कोई उपधारणा नहीं है, जिससे वादी पर भार पड़ेगा। इसके विपरीत, साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 के अनुसार, यहाँ वादग्रस्त पेटेंट की वैधता का उपधारणा है, जो सार्वजनिक व्यवसाय के सामान्य क्रम में हुआ है, अर्थात् पेटेंट अधिनियम के उपबंध के अंतर्गत पेटेंट प्रदान करना।

10. प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बिश्वनाथ (पूर्वोक्त) और टेन एक्ससी वायरलेस (पूर्वोक्त) पर भरोसा करना भी अनुचित है। वास्तव में, बिश्वनाथ का आधार पेटेंट अधिनियम की धारा 13(4) था, जिसके अनुसार किसी पेटेंट की वैधता की कोई उपधारणा केवल इस सीमा तक नहीं है कि पेटेंट प्रदान करने के संबंध में केंद्र सरकार या उसके किसी अन्य अधिकारी द्वारा कोई देयता नहीं ली जाएगी। टेन एक्ससी वायरलेस मामले में, पेटेंट के पक्ष में कोई उपधारणा केवल अंतरिम व्यादेश के प्रयोजन के लिए नहीं बनाई गई थी और न ही सबूत के दायित्व के लिए।

9. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, 07.07.2015 को तैयार किया गया मुद्दा सं. 7 सही है और इसे साबित करने का दायित्व प्रतिवादीगण पर होगा।”

(जोर दिया गया)

133. परिणामस्वरूप, यह न्यायालय विद्वान एकल न्यायाधीश के इस दृष्टिकोण से सहमत है कि केवल इसलिए कि आईपीएबी के समक्ष एक प्रतिसंहरण याचिका दायर की गई थी, यह उपधारणा नहीं बनाई जा सकती है कि इंटेक्स द्वारा वादग्रस्त पेटेंट की वैधता के संबंध में एक विश्वसनीय चुनौती उठाई गई थी।

134. आक्षेपित आदेश के परिशीलन मात्र से यह भी पता चलता है कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने वादग्रस्त पेटेंट की वैधता के संबंध में इंटेक्स द्वारा की गई अनेक स्वीकारोक्तियों के साथ-साथ *एफ. हॉफमैन ला रोशे बनाम सिप्ला* (पूर्वोक्त) में खंड पीठ के निर्णय पर भरोसा करते हुए यह निष्कर्ष निकाला कि इंटेक्स द्वारा कोई विश्वसनीय चुनौती नहीं उठाई गई थी।

135. इस न्यायालय का मानना है कि प्रतिसंहरण याचिका का समय महत्वपूर्ण है और विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा अपने आदेश में इस पर उचित टिप्पणी की गई है:-

"106. प्रतिवादी द्वारा उठाई गई आपत्ति के उत्तर पर विचार करने के पश्चात, प्रथम दृष्टया, यह न्यायालय इस एकमात्र आधार पर व्यादेश देने से इनकार करने के लिए इच्छुक नहीं है, क्योंकि प्रतिवादी ने वादग्रस्त पेटेंट की वैधता को कोई गंभीर चुनौती नहीं दी है, यह इस तथ्य से भी स्पष्ट है कि प्रतिवादी को दिसंबर 2008 में एरिक्सन के पेटेंट के बारे में सूचित किया गया था। इन पेटेंटों के बारे में इतने वर्षों से जानकारी होने के बाद भी प्रतिवादी ने कभी भी इन पेटेंटों की वैधता पर गंभीरता से प्रश्न नहीं उठाया या विवाद नहीं किया। जब वादी ने माइक्रोमैक्स, जियोनी आदि जैसे तीसरे पक्षकारगण के विरुद्ध पेटेंट के मामले में

अपने विधिक अधिकारों का दावा करना शुरू किया, तभी प्रतिवादी ने आईपीएबी के समक्ष प्रतिसंहरण याचिका दायर की।”

(जोर दिया गया)

136. न्यायालय का यह भी मानना है कि प्रधानता के दुरुपयोग का आरोप लगाने वाले पक्ष द्वारा यह दावा करना कि पेटेंट अवैध हैं, प्रति-सहज ज्ञान युक्त है, क्योंकि अवैध पेटेंट के मामले में प्रधानता नहीं हो सकती, उसका दुरुपयोग तो दूर की बात है।

137. तदनुसार, यह न्यायालय एरिक्सन के विद्वान अधिवक्ता के तर्क से सहमत है कि ऐसा कोई विधिक प्रतिबंध नहीं है जो न्यायालय को पक्षकारगण द्वारा की गई स्वीकारोक्तियों के आधार पर विश्वसनीय चुनौती के अभाव के निष्कर्ष पर पहुँचने से रोकता हो।

138. परिणामस्वरूप, केवल इसलिए कि इंटेक्स ने एक प्रतिसंहरण याचिका दायर की थी, इसका मतलब यह नहीं है कि यह उपधारणा बना ली जाए कि एरिक्सन के पेटेंट प्रथम दृष्टया अवैध हैं। केवल प्रतिसंहरण याचिका दायर करना ही अपने आप में पर्याप्त नहीं है।

अधिनियम की धारा 3 और 8 के अंतर्गत चुनौती नहीं दी गई है

139. किसी भी स्थिति में, इंटेक्स की वैधता चुनौती मुख्य रूप से अधिनियम की धारा 8 और 3(ट) तथा कथित नवाचार की कमी और एक आविष्कारशील कदम पर आधारित है। उक्त आधार प्रथम दृष्टया विद्वान एकल न्यायाधीश को स्वीकार्य

नहीं हुए। यह न्यायालय उपरोक्त प्रथम दृष्टया निष्कर्षों से सहमत है और उसका मानना है कि इंटेक्स यह दर्शाने में असफल रहा है कि एरिक्सन ने पेटेंट नियंत्रक से अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत प्रासंगिक कोई भी जानकारी जानबूझकर छिपाई है। *कम्युनिकेशन कंपोनेंट्स एंटीना इंकाॉर्पोरेशन बनाम ऐस टेक्नोलॉजीज कॉर्पोरेशन और अन्य (2019) (79) पीटीसी 270* में, यह अभिनिर्धारित किया गया है कि पेटेंट का परीक्षण व्यक्तिपरक है और संशोधन प्रकृति में स्पष्टीकरणात्मक हैं, यदि वे पेटेंट के दायरे में बदलाव नहीं करते हैं।

140. वास्तव में, विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष, इंटेक्स ने धारा 8 के गैर-अनुपालन के लिए सख्त दायित्व परीक्षण पर तर्क-वितर्क करने की माँग की थी, जिसमें *केमटुरा कॉर्पोरेशन बनाम भारत संघ, 2009 (41) पीटीसी 260 (दिल्ली)* पर भरोसा किया गया था, जैसा कि इसके लिखित बयान के पैराग्राफ 8 और 9 से स्पष्ट है। लिखित बयान से उक्त पैराग्राफ नीचे पुनः प्रस्तुत किए गए हैं:-

" 8. धारा 8 की दोनों उप-धाराओं का उद्देश्य पेटेंट नियंत्रक/भारतीय पेटेंट कार्यालय को आवेदक द्वारा विदेशी पेटेंट कार्यालयों के समक्ष रखी गई सामग्री तक पहुँच बनाने में सक्षम बनाना है, तथा उसी या मूलतः समान आविष्कार पर आवेदक के पेटेंट आवेदनों के संबंध में ऐसे विदेशी पेटेंट कार्यालयों द्वारा उठाई गई आपतियों तक पहुँच बनाना है। यह एक "स्पष्टवादिता का कर्तव्य" है जो पेटेंट आवेदक पर भारतीय नियंत्रक को सभी प्रासंगिक जानकारी/आपतियाँ प्रदान करने का दायित्व डालता है। इसका भारतीय पेटेंट प्रदान करने के संबंध में भारतीय नियंत्रक द्वारा विवेकाधिकार का प्रयोग करने के तरीके पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। इसलिए,

प्रासंगिक जानकारी उपलब्ध कराने में जानबूझकर या अन्याथा कोई भी विफलता पेटेंट अनुदान के लिए घातक है।

9. केमटुरा बनाम भारत संघ मामले में, इस माननीय उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ ने स्पष्ट रूप से निर्णय सुनाया है कि धारा 8 के अंतर्गत विवरण प्रस्तुत करने में चूक पेटेंट की वैधता पर असर डालती है, जिससे पेटेंट को अधिनियम की धारा 64(1)(ड) के अंतर्गत प्रतिसंहरित करने योग्य बनाया जा सकता है, इसके अतिरिक्त प्रतिनिधित्व के झूठे सुझाव पर पेटेंट प्राप्त करने के लिए धारा 64(1)(ट) के अंतर्गत भी इसे प्रतिसंहरित किया जा सकता है। इस माननीय न्यायालय और बौद्धिक संपदा अपीलीय बोर्ड (आईपीएबी) के कई निर्णयों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि धारा 8 के अंतर्गत दृष्टिकोण एक "सख्त दायित्व" दृष्टिकोण है। दूसरे शब्दों में, धारा 8 के अंतर्गत आवश्यक सूचना का प्रकटीकरण न करने के कारण कोई प्रतिकूल प्रभाव स्थापित करने की आवश्यकता नहीं है। सरल शब्दों में कहें तो, पेटेंट को प्रतिसंहरित करने के लिए केवल गैर-प्रकटीकरण ही पर्याप्त है..."

(जोर दिया गया)

141. हालाँकि, *मर्क शार्प एंड डोहमे कॉर्पोरेशन एंड अन्य बनाम ग्लेनमार्क* (पूर्वोक्त) में खंड पीठ ने *केमटुरा कॉर्पोरेशन बनाम भारत संघ* (पूर्वोक्त) में निर्णय पर विचार करने के बाद अभिनिर्धारित किया है कि प्रतिवादी यह प्रदर्शित करने के लिए बाध्य है कि धारा 8 के उपबंध का उल्लंघन कैसे "स्पष्ट और प्रत्यक्ष" है। ऐसे साक्ष्य के बिना, अधिनियम की धारा 8 के उल्लंघन को अंतरिम व्यादेश न दिए जाने का एकमात्र आधार नहीं बनाया जा सकता। *मर्क शार्प एंड डोहमे कॉर्पोरेशन एंड अन्य बनाम ग्लेनमार्क* (पूर्वोक्त) में खंड पीठ के प्रासंगिक अंश को नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:-

“इस चर्चा में एक महत्वपूर्ण तत्व यह है कि अंतर्वर्ती स्तर पर, जब न्यायालय मामले की प्रथम दृष्टया प्रकृति पर व्यापक दृष्टि डालता है, तो धारा 8 के गैर-प्रकटीकरण के संबंध में ऐसी प्रत्यक्ष समझ के आधार पर अस्थायी व्यादेश के दावे को अस्वीकार करना कठोर कदम होगा। इस संभावना को पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता है, उन मामलों में जहाँ प्रावधान का उल्लंघन स्पष्ट और प्रत्यक्ष है। अन्य मामलों में, धारा 8 के व्यक्ति क्रम के आधार पर अंतर्वर्ती राहत (पेटेंट अतिलंघन विचारण की लंबाई को देखते हुए एक शक्तिशाली अंतरिम आदेश) न देने का निर्णय पूरी तरह से कठोर हो सकता है - संभवतः अपने आप में अपूरणीय क्षति भी पहुँचा सकता है। इस प्रकार, इस न्यायालय की राय में, धारा 64(1)(ड) के अंतर्गत प्रतिसंहरण के लिए 5948/डीईएलएनपी/2005 (सिटाग्लिप्टिन फॉस्फेट मोनोहाइड्रेट), 1130/डीईएलएनपी/2006 (सिटाग्लिप्टिन फॉस्फेट एनहाइड्रेट), 2710/डीईएलएनपी/2008 (सिटाग्लिप्टिन प्लस मेटफॉर्मिन) का गैर-प्रकटीकरण प्रथम दृष्टया अपर्याप्त है।”

(जोर दिया गया)

142. परिणामस्वरूप, धारा 8 के गैर-अनुपालन के लिए 'कठोर दायित्व' परीक्षण का इंडेक्स का तर्क विधि के विपरीत है और इसी संदर्भ में विद्वान एकल न्यायाधीश ने निम्नलिखित निष्कर्ष दिए हैं:-

“105. पेटेंट के अतिलंघन के मामले में धारा 8 की बाध्यता पर इतना बल नहीं दिया जा सकता, अन्यथा अतिलंघन के बावजूद किसी भी मामले में व्यादेश नहीं दी जा सकता, क्योंकि ऐसा अभिवाक् झूठा और तुच्छ लगता है। यह विधि की योजना नहीं है।”

(जोर दिया गया)

143. वास्तव में, यह स्वीकार करते हुए कि *केमटुरा कॉर्पोरेशन बनाम भारत संघ* (पूर्वोक्त) में परीक्षण को कमजोर कर दिया गया है, इंटेक्स ने वर्तमान अपील में अपने तर्क को बदलने की माँग की है। लेकिन इस न्यायालय का विचार है कि एक नया अभिवाक्, जिस पर विद्वान एकल न्यायाधीश ने अपने निर्णय में विचार नहीं किया था, यह तर्क देने के लिए नहीं उठाया जा सकता कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने अधिनियम की धारा 8 की व्याख्या करने में गलती की है। किसी भी स्थिति में, इंटेक्स यह दर्शाने में असफल रहा है कि एरिक्सन द्वारा किसी भी दस्तावेज को प्रस्तुत न करना पेटेंट प्रदान करने/न देने के लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण था।

144. अधिनियम की धारा 8(2) के अनुसार नियंत्रक को प्रासंगिक समझी जाने वाली सूचना को माँगना आवश्यक है। प्रश्नों के उत्तर में, एरिक्सन ने नियंत्रक के समक्ष सभी प्रासंगिक सामग्री, जो उचित समझी, विधिवत प्रस्तुत की, जिसके प्राप्त होने के बाद नियंत्रक द्वारा कोई और माँग नहीं की गई तथा पेटेंट विधिवत प्रदान कर दिए गए। इसके अतिरिक्त, प्रथम दृष्टया यूएस में आईएन' 723 से संबंधित पेटेंट में सभी संशोधन भारतीय पेटेंट द्वारा विधिवत शामिल किए गए हैं, जैसा कि एरिक्सन द्वारा दायर चार्ट से स्पष्ट है। ऊपर प्रस्तुत चार्ट से पता चलता है कि यूएस पेटेंट के दावे भारतीय पेटेंट के अंतर्गत आते हैं, जब इसे संपूर्ण विनिर्देश के साथ समग्र रूप से पढ़ा जाता है, जैसा कि रंगबद्ध वर्गीकरण से देखा जा सकता है।

साथ ही आईएन' 723 के स्वीकृत दावे मूल रूप से यूरोप में दिए गए दावों के समान ही हैं। परिणामस्वरूप, अधिनियम की धारा 8(2) के अंतर्गत दायित्व का कोई प्रथम दृष्टया उल्लंघन नहीं बनता है।

145. इस न्यायालय का विचार है कि इंटेक्स द्वारा दायर लिखित बयान में अधिनियम की धारा 3(के) के संबंध में केवल एक साधारण चुनौती दी गई है। तर्क-वितर्क के दौरान, इंटेक्स द्वारा यह प्रतिवाद दिया गया कि पेटेंट किए गए आविष्कार अमूर्त प्रकृति के थे और उनका व्यावहारिक अनुप्रयोग नहीं था। दोनों पक्षकारण द्वारा प्रस्तुत प्रतिवादों पर विचार करने तथा यू.के., यूरोप, यू.एस.ए. और भारत में प्रचलित विधिक स्थिति तथा टीआरआईपीएस अनुबंध के अंतर्गत आवश्यकताओं को ध्यान में रखने के पश्चात, विद्वान एकल न्यायाधीश प्रथम दृष्टया इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि आविष्कार का तकनीकी प्रभाव था और इसलिए, इंटेक्स द्वारा उठाई गई आपत्तियों को स्वीकार नहीं किया जा सकता था कि पेटेंट अमूर्त प्रकृति के थे और उनका व्यावहारिक अनुप्रयोग नहीं था। आक्षेपित आदेश का प्रासंगिक पैराग्राफ नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:-

"120. इस प्रकार, मुझे प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि कोई भी आविष्कार जिसमें तकनीकी योगदान हो या जिसका तकनीकी प्रभाव हो तथा जो मात्र एक कम्प्यूटर प्रोग्राम न हो, जैसा कि प्रतिवादी द्वारा आरोप लगाया गया है, वह पेटेंट योग्य है। अतिलंघन के वाद में प्रतिवादी द्वारा उठाई गई आपत्ति मान्य नहीं है, तथापि, यह सच है कि प्रतिवादी की प्रतिसंहरण याचिकाएँ लंबित हैं, उन पर धारा 3(ट) और (ड) की आपत्ति सहित गुणागुण के आधार पर विचार किया जाना चाहिए।

इस अंतरिम चरण में, यह न्यायालय प्रतिवादी के इस तर्क से प्रभावित नहीं है कि इस आधार पर व्यादेश देने से इनकार कर दिया जाए।”

146. यह न्यायालय विद्वान एकल न्यायाधीश के उपरोक्त प्रथम दृष्टया निष्कर्ष से सहमत है।

147. इंटेक्स द्वारा दायर लिखित बयान में नवीनता और आविष्कारशील कदम की कमी के बारे में कोई विशेष चुनौती भी नहीं थी। वास्तव में, लिखित बयान में पूर्व कला का कोई संदर्भ नहीं है, अधिनियम की धारा 64 के परीक्षण को पूरा करने वाले अभिवाक् की तो दूर की बात है।

148. परिणामस्वरूप, इंटेक्स वादग्रस्त पेटेंट की वैधता के लिए एक विश्वसनीय चुनौती पेश करने में विफल रहा है।

इंटेक्स वांडर लिमिटेड एवं अन्य बनाम एंटोक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में निर्धारित विधि के सिद्धांतों को पूरा करने में विफल रहा है, लेकिन एरिक्सन उक्त कसौटी पर खरा उतरता है।

149. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, यह न्यायालय पाता है कि प्रथम दृष्टया वादग्रस्त पेटेंट आवश्यक हैं, उनका अतिलंघन किया गया है और एरिक्सन द्वारा माँगा गया स्वामिस्व एफआरएएनडी शर्तों के अनुसार है। इसके अतिरिक्त, इंटेक्स प्रथम दृष्टया जानबूझकर अनिच्छुक लाइसेंसधारी है और यह वादग्रस्त पेटेंट की वैधता को विश्वसनीय चुनौती देने में विफल रहा है। परिणामस्वरूप, इस न्यायालय

की राय है कि इंटेक्स *वांडर लिमिटेड एवं अन्य बनाम एंटोक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड 1990 (पूरक) एससीसी 727* में उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि के सिद्धांत को संतुष्ट करने में असफल रहा है, क्योंकि वह यह दर्शाने में असमर्थ रहा है कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने किस प्रकार अपने विवेक का प्रयोग मनमाने, दुराग्रही या स्वेच्छाचारी ढंग से किया है तथा वह विधि के अनुरूप नहीं है।

150. हालाँकि, यह न्यायालय एरिक्सन द्वारा दायर अपील में गुणागुण पाता है, क्योंकि इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है कि दूरसंचार उद्योग ने एरिक्सन के मानक आवश्यक पेटेंट को भारी बहुमत से स्वीकार कर लिया है। वास्तव में, एरिक्सन द्वारा वैश्विक स्तर पर एक ही प्रौद्योगिकी के लिए सौ से अधिक लाइसेंस निष्पादित किए गए हैं और समान कार्यान्वयनकर्ता एरिक्सन द्वारा सुझाई गई शर्तों के अनुसार स्वामिस्व का भुगतान कर रहे हैं। यहाँ तक कि दूरसंचार विभाग ने भी इस प्रौद्योगिकी की अनिवार्य प्रकृति को मान्यता दी है। परिणामस्वरूप, एरिक्सन द्वारा सुझाई गई शर्तें प्रथम दृष्टया एफआरएएनडी शर्तें हैं और अन्य कार्यान्वयनकर्ताओं के साथ समानता सुनिश्चित करने के लिए, इंटेक्स को मानक आवश्यक पेटेंट के पिछले उपयोग के लिए पूर्ण भुगतान करना होगा।

राहत

151. तदनुसार, इंटेक्स की अपील, आ.प्र.अ. (मू.प.)(वाणि.) 296/2018 को खारिज किया जाता है, जबकि एरिक्सन की अपील, आ.प्र.अ. (मू.प.)(वाणि.) 297/2018 को स्वीकार किया जाता है और इंटेक्स को चार सप्ताह के भीतर एरिक्सन को पूरी स्वामिस्व राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया जाता है। इस न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश रद्द माने जाते हैं। हालाँकि, जुर्माने के संबंध में कोई आदेश नहीं है। यह न्यायालय स्पष्ट करता है कि उसके द्वारा की गई टिप्पणियाँ प्रथम दृष्टया प्रकृति की हैं और विद्वान एकल न्यायाधीश इस न्यायालय द्वारा की गई किसी भी टिप्पणी से प्रभावित हुए बिना वाद का अंतिम रूप से निपटान करेंगे।

न्या. मनमोहन

न्या. सौरभ बनर्जी

मार्च 29, 2023

केए/टीएस/एस

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।